राष्ट्रीय संस्करण



सीईए बोले, जल्द सात फीसद पर जाएगी विकास दर

>>7

वर्ष 5 अंक 37

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शनिवार, 17 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

औषधि तैयार कर नाम संग पैसे भी कमा रहीं महिलाएं



कोरबा : घरेलू नुस्खे अपनाने वाली महिलाओं ने जंगल से जड़ी-बूटियां एकत्रित कर औषधि बनाने की शुरुआत की है। देखते ही देखते औषधियों की मांग बढ़ी और अब 44 लाख रुपये का सालाना कारोबार करने लगी हैं। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

20वीं सदी के तरीकों से नहीं चल सकता आज का भारत : मोदी

अहमदाबाद : प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को गुजरात की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि 21वीं सदी में भारत की जरूरतों को पिछली सदी के तौर-तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मोदी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वडनगर का फिर से विकसित रेलवे स्टेशन भी शामिल है।

राजनीति ▸ पृष्ठ 4

सोनिया ने कैप्टन को साधा, सिद्धू को समझाया

नई दिल्ली : पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जंग में फंसे सियासी पेंच का फैसला अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। हाईकमान ने सुलह के फार्मूले पर सहमति लेने की बात कर जहां अमरिंदर सिंह को साधा,वहीं बातचीत कर सिद्धू को भी समझाया।

राष्ट्रीय फलक ▸ पृष्ठ 5

कश्मीर में गोवंश वध पर रोक का आदेश, विवाद बढ़ने पर पलटे

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में बकरीद पर गोवंश के वध पर रोक लगाने संबंधी पशु एवं भेड़ पालन विभाग के निदेशक का आदेश शुक्रवार शाम तक विवादों में घिर गया। इस मामले में विवाद बढ़ता देख अधिकारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह आदेश नहीं है केवल पशु क्रूरता रोकने के लिए अनुरोध है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 7

हवाई किराया महंगा होने के आसार, एटीएफ के दाम बढ़े

नई दिल्ली : हवाई सफर और महंगा होने के आसार हैं। आयल मार्केटिंग कंपनियों ने शुक्रवार को विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत 2.44 फीसद बढ़ा दी है। इसकी कीमत पहली जुलाई को 68,262.35 रुपये प्रति किलोलीटर थी, जो 16 जुलाई को 69,857.97 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 11

भारी बारिश और बाढ़ ने बिगाड़ा यूरोप का हुलिया

बर्लिन : यूरोपीय देशों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों में स्थिति भयावह है। जर्मनी के कई हिस्सों और बेल्जियम में आई भयावह बाढ़ में 120 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1300 से अधिक लोग लापता हैं।

भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घेरा

ताशकंद सम्मेलन ▸ जयशंकर ने कनेक्टिविटी में बाधा बनने और अशरफ गनी ने देश में हिंसा के लिए ठहराया जिम्मेदार

विदेश मंत्री ने कहा, रोड़े अटकाने से किसी को भी नहीं होता है फायदा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के मुद्दे पर ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित सम्मेलन में भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जहां पाकिस्तान पर कनेक्टिविटी में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने देश में बढ़ रही हिंसा के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया।

सम्मेलन में जयशंकर ने अपने भाषण में इस समूचे क्षेत्र में कनेक्टिविटी की कोशिशों को भारत की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, लेकिन यह भी कहा कि इसके लिए मानसिकता बदलनी होगी। एक तरफ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात कहना, लेकिन वास्तविक तौर पर कनेक्टिविटी की राह में रोड़े अटकाने से किसी को फायदा नहीं होगा। कहने की जरूरत नहीं कि जयशंकर का इशारा पाकिस्तान की तरफ था जिसकी वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच कनेक्टिविटी स्थापित नहीं हो पाई। वहीं, चीन पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने यह भी कहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को इस तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कोई देश कर्ज के जाल में नहीं फंसे।

इसी सम्मेलन में अफगानी राष्ट्रपति गनी ने अपने देश में बढ़ रही हिंसा के मद्देनजर पाकिस्तान पर परोक्ष तौर पर आरोप लगाया कि वहां की सरकार तालिबान को शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं कर पाई। गनी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना ने कहा था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उनके हित में नहीं है, लेकिन हालात इसके विपरीत हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले संगठन और नेटवर्क खुलेआम अफगानिस्तान की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। पिछले महीने पाकिस्तान से 10 हजार जिहादी तालिबान का समर्थन करने आए हैं। पाकिस्तान को अब क्षेत्रीय शांति की तरफ देखना चाहिए। गनी जब भाषण दे रहे थे तब वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। प्रेट्र के मुताबिक, गनी ने कहा कि विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के बीच इस बात पर सहमति है कि तालिबान ने आतंकी संगठनों के साथ अपने संबंधों को तोड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा, 'हम अफगानिस्तान के लोग और सरकार पूरी तरह वर्तमान पर केंद्रित हैं और एक देश के तौर पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। हम तालिबान और उसके समर्थकों का तब तक सामना करने के लिए तैयार हैं जब तक उन्हें यह अहसास नहीं हो जाता कि राजनीतिक समाधान ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।'

अफगानी राष्ट्रपति ने कहा, पाकिस्तान से 10 हजार जिहादी उनके देश में तालिबान का समर्थन करने पहुंचे



मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के मुद्दे पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित सम्मेलन में भाग लेते विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

गनी-इमरान की मुलाकात के बाद कल से होने वाली शांति वार्ता रद

गनी की ओर से आरोप लगाए जाने के कुछ घंटे बाद उनकी प्रधानमंत्री इमरान खान से द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने अफगान शांति वार्ता रद होने की बात कही। समाचार एजेंसी 'एएनआइ' के मुताबिक, काबुल में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान ने ट्वीट कर कहा, '17-19 जुलाई तक इस्लामाबाद में होने वाला अफगान शांति सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखें ईद के बाद तय की जाएंगी।' खबरों के मुताबिक, इस वार्ता में शीर्ष अफगान नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसमें तालिबान को नहीं बुलाया गया था।

गनी के आरोप से इमरान नाखुश, बोले- पाकिस्तान को दोष देना ठीक नहीं

समाचार एजेंसी 'एएनआइ' के मुताबिक, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अफगानी राष्ट्रपति गनी के आरोप पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'अफगानिस्तान और तालिबान में जो कुछ चल रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को दोष देना ठीक नहीं है। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच अफगानिस्तान प्राकृतिक जमीनी ब्रिज है। अफगानिस्तान में शांति क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए सबसे अहम है। अफगानिस्तान में शांति पाकिस्तान की शीर्ष प्राथमिकता है क्योंकि इसका उनके देश पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अफगानिस्तान में अशांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा। पिछले 15 साल में पाकिस्तान में 70 हजार लोग मारे गए हैं। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में अशांति हो।' इमरान ने दावा किया कि तालिबान को वार्ता के लिए राजी करने में पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है। अगर उनका देश शांति नहीं चाहता तो वह पिछले साल नवंबर में काबुल की यात्रा नहीं करते। इमरान इस मंच पर भी कश्मीर का मुद्दा उठाने से नहीं चूके। उन्होंने क्षेत्र के अनसुलझे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मुख्य मुद्दा कश्मीर है। क्षेत्र में अनसुलझे मुद्दों की वजह से सहयोग की व्यापक संभावनाओं का दोहन नहीं हो पा रहा है।

अफगानिस्तान में जंग कवर करने में गई भारतीय पत्रकार की जान

काबुल, प्रेट्र : अफगानिस्तान में जंग कवर करने में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जान चली गई। समाचार एजेंसी रायटर के लिए काम करने वाले दानिश कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में तालिबान के हमले की चपेट में आ गए थे। पाकिस्तान सीमा से सटे इस जिले में पिछले कई दिनों से अफगान बलों और आतंकियों के बीच लड़ाई चल रही है, जिसे वह कवर कर रहे थे। पुलित्जर अवार्ड विजेता 38 वर्षीय दानिश दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने दिल्ली के ही जामिया मिलिया इस्लामिया से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद यहीं से 2007 में पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। (पेज-11)

अमेरिका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान व पाक ने बनाया नया क्वाड समूह पेज>>11

दुनिया पर तीसरी लहर का साया, देश के लिए तीन-चार महीने अहम

- पीएम मोदी ने अत्यधिक संक्रमण दर वाले छह राज्यों के सीएम के साथ बैठक में दिया टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके का मंत्र
- माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण के प्रसार को रोकने और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की सलाह



नई दिल्ली में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करते पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

- स्वास्थ्य ढांचे को (खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में) मजबूत करें राज्य। इसमें केंद्र से जारी 23 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का करें इस्तेमाल।
- पीएम-केयर फंड से जल्द आक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने पर ध्यान दें। इन छह राज्यों में 332 संयंत्र लगने हैं, जिनमें 53 ही चालू हैं।

नीलू रंजन, नई दिल्ली

दुनिया पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में बढ़ते मामले को लेकर आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक संक्रमण वाले छह राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी। वहीं, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डा. वीके पाल ने तीसरे लहर के मद्देनजर भारत के लिए अगले तीन-चार महीने को अहम बताया।

महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में मोदी ने संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई और हरसंभव केंद्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर आने से पहले जनवरी में केरल और महाराष्ट्र में केस बढ़ने लगे थे। विशेषज्ञों ने कहा था कि जिन राज्यों में संक्रमण पहले तेजी से बढ़ा था, उनमें पहले गिरावट आएगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल के मामले में यह देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों राज्यों में संक्रमण में बढ़ोतरी बरकरार है। जिन छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की, उनमें जुलाई के कुल संक्रमण के 80 फीसद मामले मिले हैं और 84 फीसद मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिक संक्रमण बने रहने से वायरस के म्यूटेशन का खतरा बढ़ता है और नए स्वरूप में वह अत्यधिक घातक हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों का उदाहरण देते हुए पूरे राज्य में लाकडाउन के बजाय माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को रोकने की सलाह दी। साथ ही टीकाकरण को भी संक्रमण के खिलाफ प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत बताई।

ज्यादा संक्रमण वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने पर जोर: प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को पूरे राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए रखने के साथ-साथ उन जिलों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी, जहां संक्रमण दर अधिक है। इन राज्यों में से केरल के आठ और महाराष्ट्र के एक जिले में संक्रमण दर अब भी 10 फीसद से अधिक है।

तीसरी लहर को रोकना मुश्किल, दुष्प्रभावों को कम करना संभव पेज>>6

'जीवन सर्वोपरि, कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार करे उप्र'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह सांकेतिक कांवड़ यात्रा कराने के फैसले पर पुनर्विचार करे और 19 जुलाई तक इस बारे में सूचित करे। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सेहत और उनके जीवन का अधिकार सर्वोपरि है, धार्मिक भावनाओं सहित अन्य सभी भावनाएं इसके अधीन हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया कि यात्रा नहीं होनी चाहिए। हां धार्मिक भावना के लिहाज से गंगाजल उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत की अखबार में आई खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा कराने की खबर को परेशान करने वाली बताते हुए कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीसरी लहर को रोकने की जरूरत है और उसमें समझौता नहीं किया जा सकता। एक ही समय अलग-अलग राजनीतिक बयानों को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि सरकार इस पर जवाब दे। कोर्ट के आदेश पर केंद्र, उप्र व उत्तराखंड ने हलफनामा पेश कर कांवड़ यात्रा पर स्थिति स्पष्ट की।

केंद्र ने कहा, राज्य को नहीं देनी चाहिए कांवड़ियों को आवागमन की इजाजत : शुक्रवार को मामला फिर जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कांवड़ यात्रा पर केंद्र का नजरिया स्पष्ट करते हुए कहा, गंगाजल लाने के लिए राज्य सरकार को कांवड़ियों को आवागमन की इजाजत नहीं देनी चाहिए। पुरानी परंपरा, धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार को टैंकर के जरिये गंगाजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। टैंकर एक चिह्नित स्थान पर उपलब्ध हों और भक्त वहां से गंगाजल लेकर नजदीक के शिव मंदिर में अभिषेक कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार को तय करना होगा कि शारीरिक दूरी, मास्क व कोरोना प्रोटोकाल सख्ती से लागू हों।

- कहा, धार्मिक भावनाओं सहित अन्य सभी भावनाएं जीवन के अधिकार के अधीन
- प्रदेश सरकार से सोमवार तक मांगा जवाब, उसी दिन फिर होगी सुनवाई



पीठ ने कहा, 100 फीसद शारीरिक रूप से यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते

कोर्ट ने कहा, यह मामला सभी नागरिकों से जुड़ा है और जीवन के मौलिक अधिकार में आता है। लोगों की सेहत व उनके जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। 'प्रेट्र' के मुताबिक,कोर्ट ने कहा, 'एक बात साफ है कि कोरोना के मद्देनजर हम उप्र सरकार को 100 फीसद शारीरिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते। हम सभी भारत के नागरिक हैं। यह स्वतः संज्ञान का मामला इसलिए लिया गया है क्योंकि अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) हम सभी पर लागू होता है। यह हम सभी की रक्षा के लिए है।'

उप्र ने कहा, विचार-विमर्श के बाद लिया सांकेतिक कांवड़ यात्रा का फैसला

उप्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा,यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित होगा। लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए सरकार ने विचार-विमर्श के बाद शर्तों के साथ सांकेतिक कांवड़ यात्रा का फैसला लिया है। इसमें कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन, पूर्व टीकाकरण और आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी।

उत्तराखंड ने कहा, पहले ही कर दी है यात्रा रद करने की घोषणा : कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के हलफनामे को भी रिकार्ड पर दर्ज किया जिसमें बताया गया था कि कोरोना को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पहले ही कांवड़ यात्रा रद करने की घोषणा कर दी है।

टी-20 विश्व कप में महामुकाबले की एंट्री

नई दिल्ली : बेशक भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट बंद हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने इन दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच महामुकाबले के लिए एक और मंच तैयार कर दिया है। आइसीसी ने 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप के पूल घोषित कर दिए हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। वनडे विश्व कप 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। ज्ञात हो, दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमी इस दोनों देशों के बीच होने वाले मैच का इंतजार करते हैं। (पेज-12)

डरपोक-कमजोर लोगों ने ही छोड़ी कांग्रेस : राहुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस इंटरनेट मीडिया विभाग के कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुकाबला करने से डरने वाले लोग कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं, पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वहीं निडर लोगों का कांग्रेस में स्वागत है। ऐसे लोगों को पार्टी में लाया जाना चाहिए। राहुल ने कहा, जो लोग पार्टी से बाहर गए हैं वे वास्तव में डरपोक-कमजोर और आरएसएस के लोग थे।

कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता के अनुसार, राहुल ने कहा कि डर दिखाकर भाजपा लोगों को अपनी पार्टी में लाती है और जो डरपोक हैं वे ही भाजपा में गए हैं। जो लोग निडर हैं वे हमारे साथ हैं। सूत्रों के अनुसार, राहुल ने कांग्रेस छोड़कर हाल में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फिर निशाना साधा और कहा कि सिंधिया इस बात से डर गए कि उनका घर छिन जाएगा और महल चला जाएगा।

पिछले कुछ समय में कई बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से नेताओं-कार्यकर्ताओं में बन रहे मायूसी के वातावरण को खत्म करने की रणनीति के तहत राहुल ने पाला बदलने वालों पर प्रहार किया। साथ ही कांग्रेस में रहकर भी डांवाडोल दिख रहे नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोग जिन्हें डर सता रहा है वे पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। यह भी कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े नहीं हैं मगर आरएसएस-भाजपा से उन्हें कोई डर नहीं है, ऐसे लोगों को कांग्रेस में शामिल कर स्वागत किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया से जुड़े 3,500 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल ने कहा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट मीडिया में विचारों को रखने की स्वतंत्रता होने की चर्चा करते हुए राहुल ने कहा, इसीलिए भाजपा सरकार इंटरनेट मीडिया पर बंदिशें लगाने का प्रयास कर रही है।

जो पार्टी से बाहर गए वे आरएसएस के लोग, निडर लोगों का कांग्रेस में स्वागत



भाजपा और आरएसएस का मुकाबला करने से डरने वाले लोग कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं, पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है।

सोच को लगेंगे पंख

स्कूलों में तैनात होंगे इनोवेशन एंबेसडर, शिक्षक ही निभाएंगे भूमिका, शुरुआत में 50 हजार स्कूली शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, इनमें अकेले उत्तर प्रदेश से साढ़े छह हजार शिक्षक होंगे शामिल

स्कूली बच्चों को दी जाएगी इनोवेशन की सीख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्कूली बच्चों में इनोवेशन के बीज अब शुरुआत से ही रोपे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) और जनजाति मंत्रालय के साथ मिलकर इसको लेकर एक बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत स्कूलों में अब इनोवेशन एंबेसडर तैनात होंगे। वे बच्चों को न सिर्फ इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि उनकी सोच को पंख लगाने में भी मदद करेंगे। फिलहाल इसका जिम्मा स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक ही निभाएंगे। इसके लिए उन्हें जल्द ही एक खास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। शिक्षा मंत्रालय के इस कदम को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इससे जुड़ी योजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत शुरुआत में देशभर के करीब 50 हजार शिक्षकों को इनोवेशन एंबेसडर से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश से साढ़े छह हजार शिक्षक शामिल होंगे। खास बात यह है कि इनमें सीबीएसई, आदिवासी बच्चों के एकलव्य स्कूल और राज्यों के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक शामिल हो सकेंगे। इनोवेशन में रुचि रखने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह पूरा प्रशिक्षण आनलाइन होगा।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस पहल से स्कूली स्तर पर ही इनोवेशन की नई संस्कृति विकसित होगी, जो बच्चों को नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस योजना में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसी माह शुरू हो जाएगा। दो माह के भीतर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली से करीब तीन हजार शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।



बड़ा कदम : बच्चों की सोच को पंख लगाने में मदद करेगी योजना। फाइल/इंटरनेट मीडिया

72 घंटे का होगा यह प्रशिक्षण

शिक्षकों को इनोवेशन एंबेसडर के रूप में तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके तहत उन्हें 72 घंटे का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो आनलाइन होगा। इनमें इनोवेशन, डिजाइन, उत्पादों का विकास, सोच, चिंतन, सृजन और उद्यमिता आदि से जुड़े विषय शामिल होंगे। प्रशिक्षण का माड्यूल एआइसीटीई ने तैयार किया है। शिक्षकों को दिया जाने वाला यह अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण होगा।

अधिवक्ता पैनल को लेकर एलजी और सरकार में बढ़ा टकराव

▸ अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने एलजी के प्रस्ताव को किया खारिज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलन से जुड़े मामलों के लिए वकीलों का पैनल गठित करने को लेकर दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार चाहती है कि सरकारी वकीलों का मौजूदा पैनल ही आंदोलनकारियों के विरोध में दर्ज हुए मामलों और दिल्ली दंगों के मामलों को देखे। उसका कहना है कि पुलिस के वकीलों को आंदोलन से जुड़े मामलों में लोक अभियोजक बनाने की मंजूरी नहीं दे सकते।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस के अधिवक्ता पैनल को मंजूरी देने वाले उपराज्यपाल (एलजी) के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। कैबिनेट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णयों में कहा गया है कि एलजी अनुच्छेद 239 एए (4) को केवल 'अत्यंत दुर्लभ मामलों' में लागू कर सकते हैं। विशेष लोक अभियोजकों की बार-बार नियुक्तियां इस श्रेणी में नहीं आ सकतीं। जांच एजेंसी और अभियोजक सेवा के बीच भेद बनाए रखना जरूरी है। कैबिनेट ने केंद्र के वकीलों को दिल्ली दंगों के मामले में पेश होने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकार के वकील ही कृषि कानून विरोधी आंदोलन से जुड़े मामलों में लोक अभियोजक होंगे। उन्होंने कहा, गृह मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में भी एलजी ने स्वीकार किया था कि सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक काबिल हैं।

श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने ढेर किए आइएसजेके के दो आतंकी

श्रीनगर : श्रीनगर में बड़े हमले का मौका तलाश रहे इस्लामिक स्टेट आफ जम्मू कश्मीर (आइएसजेके) के दो आतंकियों को सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान दो सीआरपीएफ कर्मी जख्मी हो गए। आतंकी ठिकाना बना मकान भी मुठभेड़ के दौरान लगी आग में क्षतिग्रस्त हो गया। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार व गोलाबारूद मिला है। (पेज-5)

शराब पीकर सो गया सहायक स्टेशन मास्टर, सवा घंटे खड़ी रहीं 10 ट्रेनें

औरैया : दिल्ली-हावड़ा रेल रूट के कंचौसी रेलवे स्टेशन (औरैया, उप्र) पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर गुरुवार देर रात शराब पीकर सो गए। सिग्नल न मिलने से 10 ट्रेनें एक घंटा 20 मिनट तक खड़ी रहीं। कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने पर स्टेशन अधीक्षक पहुंचे तो सहायक स्टेशन मास्टर कुर्सी पर सोता मिला। उन्होंने ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया। (पेज-7)

160 लो फ्लोर सीएनजी एसी बसें खरीदने को स्वीकृति दे दी है दिल्ली कैबिनेट ने। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 17 जुलाई, 2021

77 फीसद निजी अस्पतालों को नहीं मिल पा रही वैक्सीन

चिंताजनक ▸ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया की ओर से विभिन्न शहरों में कराए गए सर्वे में सामने आई यह बात

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना के टीकाकरण अभियान में निजी अस्पतालों की भागीदारी पर सवाल उठे तो एसोसिएशन आफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआइ) ने एक सर्वे कराया। इसमें दिल्ली, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल के विभिन्न शहरों के 70 अस्पताल शामिल हुए। इस सर्वे में 77 फीसद निजी अस्पतालों ने कहा कि उन्हें टीका नहीं मिल पा रहा है। खासतौर पर छोटे निजी अस्पतालों को टीका नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से वे टीकाकरण अभियान में तत्परता नहीं दिखा पा रहे हैं। लिहाजा एएचपीआइ ने निजी अस्पतालों को टीका उपलब्ध कराने की मांग की है।

एसोसिएशन के महासचिव डा. गिरधर ज्ञानी ने कहा कि शुरुआत में निजी अस्पतालों में भी सरकार टीका उपलब्ध करा रही थी। तब छोटे अस्पतालों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। एक मई से सीधे कंपनियों से टीका खरीदने की व्यवस्था लागू होने से छोटे निजी अस्पताल टीकाकरण अभियान से दूर हो गए क्योंकि कंपनियों ने छोटे निजी अस्पतालों को टीका देने से मना कर दिया। बाद में 21 जून से दोबारा व्यवस्था बदली और कहा गया कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों में टीका वितरण को सुनिश्चित करेगी। इसके तहत बड़े निजी अस्पतालों के अलावा छोटे निजी अस्पतालों को भी टीका उपलब्ध कराया जाएगा। निजी अस्पतालों में टीका उपलब्धता की सच्चाई जानने के लिए इस माह के पहले व दूसरे सप्ताह में सर्वे किया गया।

सर्वे में यह बात सामने आई कि 53 फीसद अस्पतालों में अधिकृत टीकाकरण केंद्र थे, जो टीकाकरण की सुविधा को लागू रखना चाहते हैं। 27 अस्पतालों में अधिकृत टीकाकरण केंद्र नहीं थे लेकिन वे इस महाअभियान में शामिल होना चाहते हैं। डेढ़ फीसद निजी अस्पताल अपने यहां टीकाकरण नहीं कराना चाहते। 77 फीसद अस्पतालों ने कहा कि उन्हें समय पर टीका नहीं मिल रहा है।

सर्वे में 41 अस्पतालों ने कहा कि उनके इलाके में प्रशासन ने नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। शेष 59 फीसद अस्पतालों ने नोडल अधिकारियों के नियुक्त होने की बात कही, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों का कहना था कि नोडल अधिकारियों से खास मदद नहीं मिलती है।

टीके की कमी से लड़खड़ाया टीकाकरण अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : टीके की कमी के कारण राजधानी में टीकाकरण अभियान लड़खड़ा गया है। एक दिन पहले महज 33,186 लोगों को टीका लगने के बाद रात में कोविशील्ड की एक लाख चार हजार 150 डोज टीका दिल्ली पहुंचा। इससे शुक्रवार को 87,249 लोगों को टीका लगा, जो एक दिन में टीकाकरण की क्षमता से बहुत कम है। पिछले माह 28 व 29 जून को दिल्ली में दो लाख से अधिक लोगों को टीका लगा था। दिल्ली में 1374 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसलिए पर्याप्त टीका उपलब्ध होने पर करीब डेढ़ लाख लोगों को टीका लगाया जाता है। यह आंकड़ा पिछले कई दिनों से कम रहा है। शुक्रवार को भी करीब 870 टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को टीका लगाया गया।

दिल्ली में कोरोना के 66 नए मामले, 79 मरीज हुए ठीक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर 0.10 फीसद के आसपास स्थिर है। पिछले 24 घंटे में भी संक्रमण दर 0.09 फीसद रही है। इस वजह से शुक्रवार को कोरोना के 66 नए मामले आए। 79 मरीज ठीक हुए। हालांकि, कोरोना के मामले बहुत कम हो जाने के बावजूद मौत का सिलसिला पूरी तरह नहीं थमा है। अब भी प्रतिदिन एक से दो मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में भी एक मरीज की मौत हो गई। पिछले सात दिनों में 12 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 14 लाख 35 हजार 419 मामले आए हैं। इनमें से 14 लाख नौ हजार 739 मरीज ठीक हो चुके हैं।



वैक्सीनेशन जरूरी

कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ते खतरे के बीच देशभर में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। नई दिल्ली के यमुना खादर के लोगों को शुक्रवार को वैक्सीन देती स्वास्थ्यकर्मी। एएनआइ

न्यूज गैलरी

अंतिम चरण में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल

नई दिल्ली : 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी केंद्र की तरफ से हाई कोर्ट को दी गई। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि बच्चों का भी टीकाकरण किया जाए। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र के जवाब पर संतोष जताते हुए कहा कि एक बार ट्रायल पूरा हो जाए, उसके बाद एक नीति बनाकर टीकाकरण शुरू किया जाए क्योंकि बच्चों को इसकी सख्त जरूरत है। इस पर केंद्र ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से ही टीकाकरण शुरू किया जाएगा। (जासं)

कोरोना मरीजों के हालचाल पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के हालचाल पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि मरीज के स्वजन को अपडेट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में इसको लेकर क्या योजना है। इस पर सरकार की तरफ से कुछ मोहलत मांगी गई है, जिसे मंजूर करते हुए सुनवाई 31 अगस्त के लिए टाल दी गई है। हाई कोर्ट में एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया है कि कोरोना से पीड़ित मरीज की मौत होने या पैसे जमा कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन अपडेट करते हैं, जबकि रोजाना मरीज की स्थिति पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है। यह व्यवस्था गलत है, क्योंकि स्वजन को बीमार की हालत के बारे में पता होना चाहिए। (जासं)

22 जुलाई से खुलेगा टर्मिनल-दो

नई दिल्ली : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 22 जुलाई से टर्मिनल-दो खोलने की बात सामने आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि उसके विमान का परिचालन 22 जुलाई को टर्मिनल-दो से होगा। ऐसे में यात्री एयरपोर्ट निकलने से पहले टर्मिनल जरूर चेक कर लें, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उधर, डायल के अधिकारी ने बताया कि टर्मिनल-दो से विमान के संचालन के लिए तैयारी चल रही है। अभी 60 हजार लोग प्रतिदिन यहां से यात्रा कर रहे हैं। ज्ञात हो कि मई मध्य में यात्रियों की संख्या काफी कम होने से टर्मिनल-दो से विमान का संचालन बंद कर दिया गया था। (जासं)

पीएचडी सीट पर हाई कोर्ट ने जेएनयू से मांगा जवाब

नई दिल्ली : पीएचडी सीट के जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) और गैर जेआरएफ के बीच बंटवारे को लेकर हाई कोर्ट ने जेएनयू से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि विस्तृत जवाब दाखिल किया जाए। स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया ने याचिका दायर कर प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले गैर जेआरएफ को भी पीएचडी में दाखिला देने की मांग की है, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। जबकि, इस बार संस्थान ने नियमों को बदलकर 100 फीसद सीट जेआरएफ को ही देने का फैसला लिया है। ऐसे में गैर जेआरएफ छात्रों के सामने पीएचडी में प्रवेश को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। (जासं)

बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि ईवीएम पर रोक लगाकर देश में आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं। शुक्रवार को तकनीकी खामी के चलते इस पर सुनवाई तीन अगस्त के लिए टाल दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कई विकसित देश ईवीएम पर बैन लगा चुके हैं, क्योंकि इन मशीनों से छेड़छाड़ कर मनमर्जी के नतीजे पाए जा सकते हैं। इसलिए भारत में भी ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान भी कहता है कि चुनाव निष्पक्ष और बगैर किसी भेदभाव के होने चाहिए। याचिका पर मुख्य पीठ ने कहा कि इसे तीन अगस्त को सुना जाएगा। इसमें जो खामियां हैं, उन्हें भी दूर किया जाए। (जासं)

रैपिड रेल में पुश बटन दबाने पर खुलेंगे दरवाजे, बचेगी बिजली

आशीष गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड रेल के डिब्बों के दरवाजे अपने आप नहीं खुलेंगे। हर दरवाजे पर पुश बटन लगाया जाएगा। कतार में खड़े पहले यात्री को दरवाजा खोलने के लिए उस बटन को दबाना होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने बिजली की बचत के लिए यह व्यवस्था की है।

एनसीआरटीसी ने इस व्यवस्था को अपनाने से पहले कई रेल सुविधाओं का अध्ययन किया है। उसमें देखा गया कि जिस रेल में डिब्बों के दरवाजे खुलने की केंद्रीकृत व्यवस्था होती है, उसके प्लेटफार्म की तरफ वाले सभी दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं। यह व्यवस्था सुबह और शाम पीक आवर्स (व्यस्त समय) में तो ठीक लगती है। लेकिन दिन के बाकी समय में जब यात्रियों की संख्या कम होती है, सभी दरवाजे खुलने से बिजली व्यर्थ होती है। पुश बटन तकनीक से बिजली बचाई जा सकती है। यह दावा भी किया जा रहा है कि पुश बटन की व्यवस्था को अपना कर कम बिजली खर्च में ट्रेन को ज्यादा देर ठंडा रखा जा सकता है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि रेल के सभी दरवाजे एक साथ खुलने से डिब्बों के अंदर एसी की ठंडक कम हो जाती है। दोबारा डिब्बे को ठंडा करने के लिए एसी लगातार काम करता रहता है। जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। वहीं, पुश बटन लगने से सीमित दरवाजे खुलेंगे तो डिब्बों में ठंडक बरकरार रहेगी।



रैपिड रेल से सफर होगा आसान। फाइल फोटो

> बहुत सोच समझ कर रैपिड रेल के डिब्बों में दरवाजे पर पुश बटन लगाने का निर्णय हुआ है। इससे बिजली की कई मायनों में बचत होगी।
>
> -पुनीत वत्स, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, एनसीआरटीसी

डीएमआरसी ने खरीदी इलेक्ट्रिक एसी फीडर बसें, परिचालन का इंतजार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो स्टेशन से घर के नजदीक तक आरामदायक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 25 इलेक्ट्रिक एसी लो फ्लोर बसें खरीदी हैं, जो पिछले करीब दो माह से मेट्रो के डिपो में खड़ी हैं। जिसका अब तक परिचालन शुरू नहीं हो सका है। यह भी तब जब इन फीडर बसों के परिचालन के लिए रूट भी निर्धारित हो चुके हैं। कोरोना के कारण बैठने की 50 फीसद क्षमता के साथ बसों व मेट्रो का परिचालन होने से इन दिनों यात्रियों की परेशानी वैसे ही बढ़ी हुई है, ऐसे में इलेक्ट्रिक एसी फीडर बसों का परिचालन शुरू होने का इंतजार है।

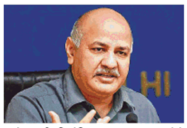
इन इलेक्ट्रिक एसी फीडर बसों के सड़क पर उतरने से यात्रियों को थोड़ी राहत मिलेगी। डीएमआरसी का कहना है कि परिचालन से संबंधित कुछ विभागीय कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। डीएमआरसी का कहना है कि एक से दो माह के अंदर उपलब्ध 25 इलेक्ट्रिक एसी फीडर बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।

सिसोदिया बोले, दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा लगा रहा केंद्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत दुखद है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से जनता द्वारा चुनी हुई दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रही है।

उपमुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा तय वकीलों के पैनल को अस्वीकृत करने की कोशिश की है। लेकिन दिल्ली कैबिनेट ने यह तय किया है कि कोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा चयनित वकीलों का पैनल ही कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी किसानों का पक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि वकीलों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। उसके बावजूद उपराज्यपाल इसमें बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं जो कि संविधान के खिलाफ है। सिसोदिया ने कहा कि जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना सीएम चुना है तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता के हितों के लिए काम करने दिया जाए। किसान विरोधी केंद्र सरकार उपराज्यपाल के सहारे दिल्ली सरकार को किसानों की मदद करने से रोक रही है। उपराज्यपाल द्वारा रोज अपनी वीटो पावर का दुरुपयोग कर सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। इस तरह के केस में जब आप अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं तो आप संविधान का भी मजाक बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के खिलाफ जाते हैं और साथ-साथ निर्णयों की हत्या भी करते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार को अपना काम करने दें और दिन में तीन-तीन बार वीटो लगाना बंद करें।



आरोप : मनीष सिसोदिया। फाइल फोटो

फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल तो विधायक के बेटे पर केस दर्ज

संस, लोनी : वन विभाग के कार्यक्रम में हवाई फायरिंग करने के मामले का वीडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार को लोनी पुलिस ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बेटे नागेश समेत दो के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने एफआइआर में खेल कर नागेश कि पिता का नाम व पता के स्थान पर मालूम नहीं लिख दिया है। लोनी कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक केके गौतम ने यह एफआइआर दर्ज कराई है। उधर, विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि बेटे ने बंदरों को भगाने के लिए रबड़ बुलेट चलाई थीं।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इसमें वन विभाग के पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान एक युवक फायरिंग करता दिख रहा था। जांच में सामने आया है कि फायरिंग कर रहा युवक विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बेटा नागेश गुर्जर है। वीडियो के आधार पर कोतवाली पुलिस ने नागेश गुर्जर व वन विभाग के रेंजर अशोक गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

वाट्सएप ग्रुप पर धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने पर मामला दर्ज

जासं, नई दिल्ली : अगर आप वाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं और उसमें किसी ने आपत्तिजनक सामग्री शेयर की है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। द्वारका इलाके में एक ऐसे ही वाट्सएप ग्रुप में एक धर्म विशेष को लेकर की गई टिप्पणी के बाद मामला दर्ज कर लिया गया।

एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वाट्सएप ग्रुप पर बातचीत के दौरान एक शख्स ने धर्म विशेष पर टिप्पणी की है। इसमें महिला ने संबंधित व्यक्ति व ग्रुप एडमिन के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान पता चला कि पांच लोग आपस में बात कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी की है। फिलहाल उस वाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। मामले में ग्रुप एडमिन से पूछताछ की जा रही है। जरूरत पड़ने पर ग्रुप के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा सकती है।

जल संकट को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन

▸ टैंकर माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए समस्या हल नहीं करने का आरोप

▸ आप सरकार को बताया सभी मोर्चों पर पूरी तरह विफल, जारी रहेगा आंदोलन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राजधानी के कई इलाके में जल संकट को लेकर भाजपा आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के नजदीक प्रदर्शन किया। भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास का पानी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी थी। इसे ध्यान में रखकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। चंदगी राम अखाड़ा से नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए एक बैरिकेड को तोड़ दिया। उसके बाद किसी तरह से पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और फावड़े से सड़क को हल्का नुकसान पहुंचाया।

गुप्ता ने कहा कि हर घर में नल से साफ पानी पहुंचाने का वादा करके सत्ता में आने वाले मुख्यमंत्री अब इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। जल संकट दूर होने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। टैंकर माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए जल संकट को दूर नहीं किया जा रहा है। पाइप लाइन बिछाने के बाद कई कालोनियों में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। इसी तरह से कई इलाके में दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों से किए गए वादे पूरा करने के बजाय मुख्यमंत्री का ध्यान दूसरे राज्यों में अपनी का पार्टी के विस्तार पर है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की जनता से बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के लिए किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों के खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए। प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, जयवीर सिंह राणा आदि मौजूद रहे।



पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास प्रदर्शन करते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता (दाएं) और कार्यकर्ता। जागरण

कांग्रेस ने भी किया मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेयजल संकट और दूषित जलापूर्ति के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए केजरीवाल का यही फंडा है, राजधानी का पानी गंदा है, बीमारी नहीं पानी दो, दिल्ली को स्वच्छ पानी दो आदि नारे लगा रहे थे। चौधरी ने कहा कि राजधानी में पिछले दो महीने से गहराए जल संकट के कारण दिल्ली वासियों को पानी की खासी किल्लत झेलनी पड़ रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संत परमानंद अस्पताल से आगे नहीं बढ़ने दिया। चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली का जल संकट दूर करने की बजाय दूसरे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पैर जमाने के लिए मुफ्त पानी देने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

संघर्ष के बाद यमुना में आया पानी : चड्ढा

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने वजीराबाद बैराज का निरीक्षण किया। इससे पहले वह 12 जुलाई को यहां पहुंचे थे। हरियाणा से 16 हजार क्यूसेक पानी आने पर हालात का जायजा लेने पहुंचे चड्ढा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार दिल्ली वालों का संघर्ष सफल हुआ है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले दिल्ली के हक का पानी रोका, जिसकी वजह से नदी सूख गई थी। संघर्ष के बाद नदी में दिल्ली के हक का पानी आया है। इससे नदी की प्यास बुझी है और दिल्ली वालों की प्यास भी बुझने जा रही है। दिल्ली के सभी जल शोधन संयत्र अधिकतम क्षमता के साथ काम करेंगे। कहा कि यमुना के माध्यम से हरियाणा से पानी को दिल्ली पहुंचने में तीन दिन लगे हैं। यमुना का स्तर साढ़े सात फुट नीचे गिरकर 667 फुट पर आ गया था। अब वापस 674.5 फुट तक बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड अब फिर से अपनी अधिकतम क्षमता के बराबर जल शोधन कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचा रहा है।

गर्व की बात

वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने की सुहास एलवाई के पैरा ओलिंपिक में चयन की पुष्टि

गौतमुद्धनगर के डीएम टोक्यो पैरालिंपिक में दिखाएंगे दमखम

जागरण संवाददाता, नोएडा

गौतमबुद्ध नगर (उप्र) के जिलाधिकारी सुहास एलवाई जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाले पैरालिंपिक में हिस्सा लेंगे। वह बैडमिंटन की एकल प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने सुहास एलवाई का पैरालिंपिक में चयन होने की पुष्टि की है। सुहास एलवाई ने बताया कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि वह पहली बार देश के लिए पैरालिंपिक में हिस्सा लेंगे। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की पुरजोर कोशिश करेंगे। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना उनका लक्ष्य है। परिश्रम उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि आदत है। यही वजह है कि चाहे पढ़ाई हो या फिर खेल, जहां उन्होंने हाथ आजमाया सफलता ने कदम चूमे।

बैडमिंटन नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ी थे सुहास : सुहास एलवाई को खेल का शौक बचपन से था, लेकिन आइएएस में चयन से पहले वह क्रिकेट के खिलाड़ी थे। आइएएस में चयनित होने के बाद उनका बैडमिंटन से नाता जुड़ता चला गया। इसके चलते उन्होंने आइएएस एकेडमी से बैडमिंटन खेलना शुरू किया। आइएएस की ट्रेनिंग आजमगढ़ से की थी। चूंकि आजमगढ़ में बैडमिंटन के कई राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं सो उनकी संगत में इन्हें बैडमिंटन के खेल में न सिर्फ रूचि हुई बल्कि वह इसे संजीदगी से खेलने लगे। आज उनकी वर्ल्ड रैंकिंग तीन है।

कोरोना काल में मिली थी जिले थी जिम्मेदारी : पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण से जूझ रहे नोएडा को बचाने के लिए आइएएस सुहास एलवाई को जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। दमदार प्रोफाइल और सटीक काम के लिए चर्चित सुहास एलवाई दिव्यांग हैं। सुहास एलवाई इससे पहले आजमगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जैसे जिलों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान सुहास एलवाई जिले के डीएम थे। इस दौरान क्राउड मैनेजमेंट से लेकर शहर की साफ-सफाई और साज-सज्जा हर काम को उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया।

प्रशासनिक अनुभव के साथ खेल में माहिर : सुहास एलवाई कर्नाटक के शिमोगा जिले के मूल निवासी हैं। 2007 में आइएएस अधिकारी बने सुहास एलवाई ने प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ अपने खेल को भी पर्याप्त समय देते हैं। सुहास की पत्नी रितु सुहास पीसीएस अधिकारी हैं। सुहास एलवाई को उत्तर प्रदेश की सरकार यश भारती अवार्ड से नवाज चुकी है।



गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई। जागरण आर्काइव

सुहास एलवाई द्वारा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीते गए प्रमुख खिताब

- चीन के बीजिंग में वर्ष-2016 में हुए एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता।
- इंडोनेशिया के जकार्ता में वर्ष-2018 में हुए एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक विजेता।
- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ष-2018 में हुए नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता।

अंतिम वर्ष के छात्र खाली करें छात्रावास : जेएनयू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सर्कुलर जारी कर अंतिम वर्ष के छात्रों को छात्रावास खाली करने के लिए कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रावास आवंटन की मियाद 31 मई को ही समाप्त हो गई। छात्र उसके बाद भी छात्रावास में रह रहे हैं, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। ऐसे छात्रों को तत्काल छात्रावास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अंतिम वर्ष के ऐसे छात्रों को राहत दी गई है, जिनकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं।

जेएनयू प्रशासन ने बताया कि एमए, एमएससी, एमसीए, एमबीए की परीक्षाएं 31 मई के बाद शुरू हुई हैं। परीक्षाएं अभी चल रही हैं, इसलिए इन छात्रों को छात्रावास में रहने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि छात्रों को अपने विभागाध्यक्ष से परीक्षा चलने की बाबत एक पत्र लिखवाकर जमा करना होगा।

संक्रमण के मामले 600 पहुंचे : जेएनयू प्रशासन ने छात्रों को शारीरिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जेएनयू में अब तक संक्रमण के 600 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमितों में छात्र, शिक्षक व कर्मचारी शामिल हैं। जबकि 10 लोगों का निधन हो चुका है। परिसर में कोविड सेंटर खोलने की बाबत एसडीएम वसंत विहार से बातचीत चल रही है। दिल्ली सरकार की अनुमति का इंतजार है। जैसे ही सरकार की अनुमति मिलेगी, कोविड सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

75 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए। जीएसटी परिषद ने 28 मई को फैसला किया था कि केंद्र 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर राज्यों को बैक-टू-बैक आधार पर जारी करेगा।

20वीं सदी के तरीकों से नहीं चल सकता आज का भारत : मोदी

- प्रधानमंत्री ने किया गुजरात की कई परियोजनाओं का उद्घाटन
- कहा, आधुनिकीकरण के साथ गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग का विकास भी जरूरी

अहमदाबाद, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि 21वीं सदी में भारत की जरूरतों को पिछली सदी के तौर-तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वडनगर का फिर से विकसित रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इसी रेलवे स्टेशन पर मोदी बचपन में टी-स्टाल चलाने में अपने पिता की मदद किया करते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जिस पर लक्जरी होटल बनाया गया है।

रेलवे में सुधार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश को दो-ट्रैक वाले विकास की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस देश को दो-ट्रैक वाले विकास की जरूरत है। एक तरफ आधुनिकीकरण की जरूरत है तो दूसरी तरफ गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग का विकास भी जरूरी है। 21वीं सदी में भारत का काम पिछली सदी के तौर-तरीकों से नहीं चल सकता। इसलिए रेलवे में सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार का उद्देश्य सिर्फ कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि हम ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें चरित्र है।

मोदी बोले, सरकार ने रेलवे को एक संपत्ति के रूप में विकसित करना शुरू किया है। इसका मकसद सिर्फ लोगों को सेवा देना नहीं है। रेलवे के विस्तार के साथ क्षमता निर्माण भी जरूरी है। रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए। और इसके ऊपर होटल भी बनाया जा सकता है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एएनआइ के अनुसार, प्रधानमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया।



नई दिल्ली में शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर-वाराणसी सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र



पीएम के पिता की कैंटीन: पीएम नरेंद्र मोदी के पैतृक गांव वडनगर जिला मेहसाणा के रेलवे स्टेशन पर बनी उनके पिता की चाय की कैंटीन। यह आज भी वैसी ही नजर आती है (बाएं)। इस कैंटीन को शुक्रवार को फूलों से सजाया गया (दाएं)। साभार : प्रदीप शर्मा, चीफ पीआरओ, अहमदाबाद रेल मंडल

वैसी ही रही मोदी के पिता की कैंटीन

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो : वडनगर के नवीनीकृत रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदरदास मोदी की कैंटीन आज भी वैसी की वैसी ही रखी है। स्टेशन के साथ कैंटीन को भी फूलों से सजाया गया, लेकिन न उसे हटाया गया है और न ही उसमें कोई बदलाव किया गया, जबकि करोड़ों की लागत से पूरा स्टेशन भव्य बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी इस स्टेशन व कैंटीन से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं तथा लोग इसे देखने आते हैं। इसलिए इसमें कोई बदलाव ठीक नहीं है।

पीएम मोदी ने वाराणसी को दी ट्रेन की सौगात

जागरण संवाददाता, वाराणसी

गुजरात की राजधानी गांधीनगर कैपिटल और वाराणसी के बीच शुक्रवार को नई सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हरी झंडी दिखाकर गांधीनगर कैपिटल से ट्रेन को वाराणसी के लिए रवाना किया। बनारस में कैंट स्टेशन परिसर में लगे एलसीडी टीवी स्क्रीन पर उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे स्थानीय रेलवे अफसरों के साथ यात्रियों ने भी देखा और तालियां बजाकर पीएम की सौगात स्वीकार की।

पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत गांधीनगर कैपिटल-वाराणसी एक्सप्रेस विशेष ट्रेन संख्या-04274 बनकर प्रस्थान हुई। ट्रेन का प्राइमरी मेंटिनेंस कैंट स्टेशन (वाराणसी जंक्शन) पर ही कराया जाएगा। ट्रेन 21 जुलाई से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या-22467 वाराणसी जंक्शन से 15:15 बजे चलेगी। अगले दिन गुरुवार को शाम 15:20 बजे गांधीनगर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या-22468 गांधीनगर कैपिटल स्टेशन से गुरुवार को रात 23:15 बजे प्रस्थान करेगी। अगले दिन शुक्रवार को रात 23:30 बजे कैंट स्टेशन पर आगमन होगा। प्रयागराज, गोविंदपुरी, झांसी, बीना, संत हरिदासनगर, उज्जैन, रतलाम, गोधरा, छायापुरी, आनंद व अहमदाबाद स्टेशन पर भी ट्रेन का ठहराव होगा।

जेल तक जल्द आदेश पहुंचाने को लागू होगी सुरक्षित और भरोसेमंद व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बावजूद आदेश न पहुंचने के कारण रिहाई में देरी का लिया संज्ञान

आगरा सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को जमानत मिलने के चार दिन बाद हो पाई थी रिहाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली



सूचना एवं संचार तकनीक के इस युग में हम अभी भी आदेश भेजने को कबूतरों के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं। - सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बावजूद आदेश न पहुंचने के कारण रिहाई में देरी होने पर चिंता जताते हुए कहा कि कोर्ट जेल में जल्द आदेश पहुंचाने के लिए सुरक्षित, प्रामाणिक और भरोसेमंद व्यवस्था लागू करेगा। कोर्ट ने इस डिजिटल युग में भी आदेश की प्रति जेल पहुंचने में देरी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सूचना एवं संचार तकनीक के इस युग में हम अभी भी आदेश भेजने को कबूतरों के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं।

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 उम्र कैदियों को अपराध के वक्त किशोर होने के आधार पर जमानत देते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट का आदेश जेल पहुंचने में देरी के कारण कैदियों की रिहाई चार दिन बाद हो सकी। कैदियों के वकील ऋषि मल्होत्रा ने गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र करते हुए ईमेल के जरिये जमानत आदेश जेल पहुंचाने का सुझाव दिया था, ताकि जमानत मिलने के बाद रिहाई में देरी न हो। उठाए गए उस मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लिया।

शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जेल में आदेश पहुंचने में देरी के कारण कैदी की रिहाई देर से होने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए आदेश पहुंचाने की त्वरित व्यवस्था लागू करने की बात कही। पीठ ने त्वरित और सुरक्षित तरीके से जेल तक आदेश पहुंचाने की व्यवस्था लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल से दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें भी जेल में इंटरनेट व्यवस्था के बारे में बताएंगी, क्योंकि जेल मे इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर आदेश जेल तक पहुंचना संभव नहीं होगा।

कोर्ट ने राज्यों को इस मुद्दे पर नोटिस भी जारी करते हुए मामले की सुनवाई में मदद के लिए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को न्यायमित्र नियुक्त किया। कोर्ट ने दवे से कहा कि वह योजना के बारे में सेक्रेट्री जनरल से विमर्श करेंगे। सेक्रेट्री जनरल इसमें सालिसिटर जनरल के साथ भी सहयोग करेंगे। पीठ ने सेक्रेट्री जनरल से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट एक महीने में नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेल में आदेश पहुंचने में देरी के कारण रिहाई में देरी की स्थिति पर कहा कि सूचना संचार के इस युग में ऐसा होना 'अति' है। जेल अथारिटी कोर्ट आदेश की प्रति प्राप्त होने तक कैदी को रिहा नहीं करती। इस पर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रिहाई में देरी ठीक नहीं है, लेकिन जेल अथारिटी का आदेश देखकर रिहाई देने का नियम इसलिए है, क्योंकि कई बार फर्जीवाड़ा होता है। मेहता ने कहा कि जेल अथारिटीज को कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड आदेश देखकर रिहाई दे देनी चाहिए।

चीफ जस्टिस ने कहा कि सूचना एवं संचार तकनीक के इस युग में, हम अभी भी आदेश भेजने को कबूतरों के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं। जस्टिस रमना ने कहा कि वे नई व्यवस्था लागू करेंगे, जिसमें कोर्ट का आदेश त्वरित, सुरक्षित और प्रमाणिक (फास्ट एंड सेक्योर ट्रांसमीशन आफ इलेक्ट्रानिक रिकार्ड) रूप से जेल तक या संबंधित जिला अदालत व हाई कोर्ट तक पहुंचेगा। पीठ ने कहा कि इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि आदेश पहुंचना सुनिश्चित होगा और रिहाई में देरी नहीं होगी।

81 हजार पैरामिलिट्री जवानों ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसे अर्धसैनिक बलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले जवानों का आंकड़ा जारी किया है। पिछले एक दशक में 81,000 से ज्यादा जवानों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का रास्ता चुना। अकेले वर्ष 2017 में ही 11,000 से ज्यादा ने यह रास्ता अपनाया।

वहीं, वर्ष 2011 से वर्ष 2020 की इस अवधि में 15,904 कर्मियों ने इस्तीफा भी दिया। वर्ष 2013 में सबसे ज्यादा 2,332 कर्मियों ने इस्तीफा दिया था। ये आंकड़े सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और असम राइफल्स से संबंधित हैं।

निजी कारणों से हुए अलग : मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों से अलग होने वाले जवानों को लेकर कारण नहीं बताया है। हालांकि इन बलों द्वारा किए गए आंतरिक विश्लेषण में पाया गया कि ज्यादातर जवान निजी या पारिवारिक मसलों, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या बेहतर करियर विकल्प के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफा का रास्ता चुनते हैं।



स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	
बीएसएफ	36,768
सीआरपीएफ	26,264
सीआइएसएफ	6,705
असम राइफल्स	4,947
एसएसबी	3,230
आइटीबीपी	3,193
इस्तीफा	
सीआइएसएफ	5,848
बीएसएफ	3,837
सीआरपीएफ	3,366
आइटीबीपी	1,648
एसएसबी	1,031
असम राइफल्स	174

कोरोना की दूसरी लहर में रिहा कैदी फिलहाल नहीं जाएंगे जेल

जाब्यू, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर में जेलों की भीड़ कम करने और कैदियों को संक्रमण से बचाने के लिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई पावर कमेटी ने रिहाई दी थी उन कैदियों को फिलहाल जेल नहीं जाना होगा। कोर्ट ने राज्यों से कैदियों की रिहाई के आधार और मानक मांगते हुए छूटे कैदियों को वापस जेल भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले में तीन अगस्त को फिर सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को जेल में कैदियों को कोरोना से बचाने के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके पहले मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट और आंकड़े नहीं हैं जिससे पता चले कि शीर्ष कोर्ट के आदेश पर राज्यों में गठित हाई पावर कमेटी ने किस आधार पर कैदियों की रिहाई की और कुल कितने कैदी रिहा हुए। जस्टिस रमना ने कहा कि कोर्ट भी जानना चाहता है कि कैदियों की रिहाई के मानक और आधार क्या हैं। कुछ राज्य उम्र और बीमारियों को रिहाई में तरजीह दे रहे हैं, लेकिन बाकी के क्या आधार और मानक हैं-यह पता नहीं है। कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी को निर्देश दिया कि वह राज्यों से आंकड़े एकत्र कर रिपोर्ट दाखिल करे कि हाई पावर कमेटी ने किन मानकों और आधार पर कैदियों की रिहाई के आदेश जारी किए। कोर्ट ने राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी है।

पांच छात्रों को सिविल सेवा के इंटरव्यू में भाग लेने की इजाजत

मिली राहत

- निर्धारित तिथि तक डिग्री का प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए थे अभ्यर्थी
- कोरोना महामारी के चलते उनके विश्वविद्यालयों ने देरी से जारी किया परीक्षा परिणाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिविल सेवा के पांच उम्मीदवारों को विशेष मामले के तहत साक्षात्कार में भाग लेने की इजाजत दे दी। इन पांचों उम्मीदवारों ने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन निर्धारित तिथि तक अपनी डिग्री का प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

जस्टिस एएम खानविलकर और संजीव खन्ना की पीठ ने निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों को विशेष मामले के तहत इंटरव्यू में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते उनके विश्वविद्यालयों ने देरी से परीक्षा का परिणाम घोषित किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये पांचों छात्र साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों की प्रकाशित सूची के अतिरिक्त होंगे।

पीठ ने कहा कि इससे पहले भी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कई ऐसे उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने दिया, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन अपने आवेदन के साथ पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट नहीं पेश कर सके। शपथपत्र देने पर उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई।

उम्मीदवारों को परीक्षा जारी रखने से इन्कार करना न्याय के विरुद्ध होगा : अदालत ने कहा कि इन पांचों उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा जारी रखने से इन्कार करना न्याय के विरुद्ध होगा, क्योंकि कोरोना के कारण विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करने से स्थिति उनके लिए कठिन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित कर रहा है और इसे विशेष मामले के रूप में व्यवहार कर रहा है।

जीएसटी को तर्कसंगत बनाया जाए : थरूर

चेन्नई, प्रेट्र: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार पर ईंधन पर कर का इस्तेमाल सरकार के खजाने को भरने में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को ईंधन पर कर और उपकर और आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती की मांग की। उन्होंने केंद्र से घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को तर्कसंगत और सरल बनाने की भी मांग की। थरूर ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईंधन पर करों और उप कर में बड़ी कटौती, आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया जाए। थरूर ने दावा किया कि केंद्र ने पिछले साल केवल पेट्रोल और डीजल पर कर से करीब 4.2 लाख करोड़ रुपये जुटाए। उन्होंने यहां तमिलनाडु कांग्रेस समिति मुख्यालय सत्यमूर्ति भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह इसके पिछले शासन में एकत्र की गई राशि की तीन गुनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि संप्रग सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 6.45 रुपये का उपकर एकत्र किया और प्रति लीटर तीन रुपया राज्यों को दिया था। वहीं अब मोदी सरकार ने नाटकीय ढंग से ईंधन की कीमतें बढ़ा दी लेकिन अब भी राज्य सरकारों को तीन रुपये प्रति लीटर उपकर दिया जा रहा है।

सबको पता है राजद्रोह कानून में क्या होता है : वोमबटकेरे

- सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने कहा, कानून को लेकर लोगों को कैसा लगता है यह महत्वपूर्ण है
- पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी राजद्रोह कानून को अप्रासंगिक बताया

मैसुरु, प्रेट्र : राजद्रोह की धारा 124-ए की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसजी वोमबटकेरे ने शुक्रवार को कहा कि सबको पता है कि इस औपनिवेशिक कानून के मामले में क्या होता है। इस कानून के दुरुपयोग की ओर इशारा करते हुए सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने कहा, हर कोई जानता है कि राजद्रोह मामले में क्या होता है। इसको लेकर मैं क्या महसूस करता हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लोगों को कैसा लगता है यह जरूर महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों के पास इस बात की बेहतर जानकारी है कि राजद्रोह कानून को लेकर लोग क्या सोचते हैं? हालांकि, उन्होंने चुटकी ली कि वह देश में किसी अन्य व्यक्ति की तरह खुश हैं, लेकिन इसको लेकर ज्यादा बोलने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि मामला अदालत में विचाराधीन है। औपनिवेशिक कानून के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप करने के लिए ब्रिटिश जिस कानून का इस्तेमाल करते थे, सरकार उसे निरस्त क्यों नहीं कर देती? एएनआइ के अनुसार, राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नजरिये से सहमति जताते हुए देश के पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को कहा कि इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और इसका अब कोई उपयोग नहीं है। रोहतगी ने कहा कि भारतवासियों की असहमति को दबाने के लिए ब्रिटिश शासक इस कानून को लेकर आए थे। उन्हें डर था कि एकजुट होकर लोग सरकार के खिलाफ हिंसक मुहिम शुरू कर सकते हैं।

एंटनी व पवार से मिले राजनाथ, सीमा विवाद से अवगत कराया

- क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों के बारे में भी विवरण दिया
- संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी दलों से संपर्क की कवायद

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता एके एंटनी और राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने दोनों नेताओं को पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत कराया।

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि राजनाथ ने बैठक के दौरान दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों को क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों के बारे में भी कुछ विवरण दिया। बैठक में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद थे। राजनाथ के इस कदम के बारे में माना जा रहा है कि सरकार संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हालांकि, इस बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

राजनाथ ने आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के संघों के साथ की बैठक : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के व्यावसायीकरण के मुद्दे पर इसके तीन मान्यता प्राप्त संघों के साथ बैठक की। इस बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मानसून सत्र से पहले विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से मिले गोयल

राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। गोयल जिन नेताओं से मिले उनमें पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह, उनकी पार्टी के सहयोगी आनंद शर्मा और राकांपा नेता शरद पवार शामिल हैं।

मुलाकात

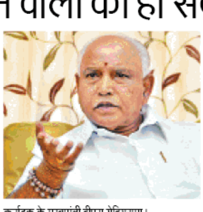
कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, आज शाह और नड्डा से मिलेंगे, हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी पार्टी के नेता और विधायक ही रहे थे मुखर

विवाद खड़ा करने वालों की हो सकती है शिकायत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उठती अटकलों के शांत होने के बाद अब मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो उनकी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। साथ ही अपने दिल्ली दौरे के दौरान वह मोदी कैबिनेट में शामिल कर्नाटक के मंत्रियों और सांसदों से मिलकर राज्य के लिए विशेष जतन करने की अपील भी करेंगे।

येदियुरप्पा के दिल्ली दौरे को लेकर अक्सर अटकलें तेज हो जाती हैं। शुक्रवार को भी जब उन्होंने दिल्ली की उड़ान भरी तो एक बार फिर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगाए जाने लगे। सूत्रों के अनुसार स्थिति इसके उलट है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के साथ येदियुरप्पा की मुलाकात हो गई। बताया जाता है कि शनिवार को वह अमित शाह और नड्डा से भी मिलेंगे। औपचारिक रूप से तो पीएम के साथ मुलाकात विकास और योजनाओं पर केंद्रित रही। पिछली मुलाकात में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के विकास का एक विजन दिया था। येदियुरप्पा ने उसके बारे मे विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने तो नेतृत्व परिवर्तन के बारे मे कुछ नहीं सुना।



कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

सूत्रों की माने तो लगभग एक साल बाद प्रधानमंत्री से सीधे रूबरू होने पर येदियुरप्पा का कुछ राजनीतिक मुद्दे उठाने का भी विचार था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पार्टी के विधायकों और कुछ मंत्रियों की ओर से खुले तौर पर उनके खिलाफ बयान दिए गए थे। उनके पुत्र और प्रदेश उपाध्यक्ष विजयेंद्र को भी निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश तेज रही थी। रोचक तथ्य यह है कि विपक्षी दल कांग्रेस और जदएस के मुकाबले पार्टी के ही कुछ लोग ज्यादा मुखर रहे।

प्रधानमंत्री के सामने येदियुरप्पा ने यह विषय उठाए या नहीं इसकी तो पुष्टि नहीं है लेकिन शाह और नड्डा के समक्ष वह आवश्यक तौर पर बताएंगे कि अब जबकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दो साल का भी वक्त नहीं है तो अंदरूनी विवाद परेशानी का सबब बन सकता है। दक्षिण में कर्नाटक न सिर्फ अकेला भाजपा शासित राज्य है, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम है। लिहाजा सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री और सरकार पर उंगली उठाने वाले भाजपा नेताओं को न सिर्फ ताकीद किया जाना चाहिए, बल्कि उनपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बताते हैं कि शनिवार को येदियुरप्पा कर्नाटक से बने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से भी मिलेंगे।

नवंबर तक पूरा हो जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगले साल गणतंत्र दिवस की परेड नवीनीकृत राजपथ पर होगी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक चल रहा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। यह जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों ने दी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों को जल्द गर्व करने अवसर मिलेगा। पुरी ने एक ट्वीट किया, केंद्रीय विस्टा एवेन्यू परियोजना के चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, ठेकेदार और वास्तुकार बिमल पटेल के साथ की। अब तक की प्रगति संतोषजनक है। एक अधिकारी ने कहा कि राजपथ पुनर्विकास परियोजना में बड़े पैमाने पर पत्थर का काम, अंडरपास का निर्माण, भूमिगत सुविधाओं के ब्लॉक और बागवानी कार्य और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह निकालना शामिल है।

कह के रहेंगे माधव जोशी



23 जुलाई से देहरादून से चलेगी इंदौरी एक्सप्रेस और उज्जैनी एक्सप्रेस 27 जुलाई से। इससे उत्तराखंड से मध्य प्रदेश जाने वाले लोगों को सुविधा होगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 17 जुलाई, 2021

छोटे दिल वाले नहीं संभाल सकते इतना बड़ा उत्तर प्रदेश : नड्डा

मिशन 2022

- प्रदेश कार्यसमिति के वर्चुअल उद्घाटन सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अखिलेश पर तंज
- मोदी सरकार के काम गिनाकर याद दिलाईं कांग्रेस की खामियां, योगी की जमकर तारीफ की
- जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुख चुनाव में शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

'भाजपा के सत्ता में आने से क्या सकारात्मक फर्क पड़ा..?' इसे तथ्यात्मक रूप से कार्यकर्ताओं को समझाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता को भी यह अहसास दिलाने का 'गुरुमंत्र' दिया है। पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का दिल्ली से ही वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने मिशन-2022 के लिए पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का तरकश तथ्यों से सजाया। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस शासनकाल की खामियां भी गिनाईं। वहीं, बिना किसी का नाम लिए भाजपा की वैक्सीन वाले बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा कि इतने छोटे दिल वाले इतना बड़ा उत्तर प्रदेश कैसे संभाल सकते हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्रवार को आयोजित प्रदेश कार्यसमिति में प्रदेश के सांस्कृतिक-राजनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि नुकसान का न पता हो तो फायदे का अहसास भी नहीं होता। कार्यकर्ताओं को यह समझना और जनता को समझाना होगा कि कैसे यूपी तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में फंसा था। सत्ता का दुरुपयोग कर किसी एक समाज को फायदा पहुंचाया जाता था। प्रदेश भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और अनाचार का अड्डा बन गया था, लेकिन अब वही प्रदेश बीते चार वर्षों में अग्रणी राज्यों में से एक हो गया। जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुख चुनाव में शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए नड्डा ने कहा कि सपा-बसपा को सिरे से नकारकर जनता ने हमें काम करने का संदेश दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समृद्ध और विकसित देशों की तुलना भारत से करते हुए कार्यकर्ताओं को समझाया कि देश की आबादी 130 करोड़ होने के बावजूद मोदी सरकार ने कैसे कोविड प्रबंधन किया। संसाधनों को सीमित समय में कई गुना बढ़ाकर कोरोना को काबू किया। आक्सीजन की जरूरत से ज्यादा मांग और ओछी राजनीति का जिक्र कर बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया।

नड्डा ने याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले गुरुवार को काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की। यहां लग रहे आक्सीजन प्लांट का जिक्र करते हुए उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से अपेक्षा जताई कि अस्पतालों में जाएं और प्लांट लगवाने की प्रक्रिया से जुड़ें। फिर मोदी सरकार के कोविड प्रबंधन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए बोले कि टीबी की दवा जब दुनिया में पहुंच गई, उसके बाद भारत में आई। चिकनपाक्स, स्मालपाक्स यहां सबसे बाद में खत्म हो पाया। इसी तरह दुनिया से जब पोलियो खत्म हो गया, तब हमारे देश में अभियान शुरू हुआ। यह है कांग्रेस के शासनकाल की सच्चाई, जबकि मोदी ने मात्र नौ माह में दो-दो वैक्सीन देश को दे दीं। बिना सपा या अखिलेश यादव का नाम लिए इशारों में बोले कि यूपी के नेता ने तो वैक्सीन को भाजपा का बता दिया था। बाद में उनके पिताजी ने भी वैक्सीन लगवाई। इस तरह के बयानों से उन्होंने अपना स्तर बता दिया। जिसकी सोच और दिल इतना छोटा हो, वह इतना बड़ा उत्तर प्रदेश कैसे संभाल सकता है।



उप्र भाजपा कार्यसमिति की बैठक को नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते जेपी नड्डा। एएनआइ

अब न यूपी बीमारू राज्य, न चार वर्ष में कोई दंगा

नड्डा ने योगी की जमकर तारीफ की। कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। बीते चार वर्ष में योगी के नेतृत्व में यूपी ईज आफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर आ गया। मुजफ्फरनगर सहित कई दंगे जनता को याद होंगे, लेकिन चार वर्ष में यहां कोई दंगा भी नहीं हुआ। यहां चार एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। यूपी निवेश का केंद्र बन रहा है।

यह भी रहे शामिल

दिल्ली के मंच पर केंद्रीय मंत्री डा. महेंद्र नाथ पांडेय व स्मृति ईरानी तथा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह थे। वहीं, प्रदेश मुख्यालय के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डा.दिनेश शर्मा थे।

देश विरोधी विपक्ष का चेहरा बेनकाब करना होगा : योगी



योगी आदित्यनाथ। फाइल/इंटरनेट मीडिया

समापन सत्र में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें देश विरोधी विपक्ष का चेहरा बेनकाब करना होगा। आतंकवादियों के शुभचिंतक विपक्ष की नकारात्मकता से लोगों को बचाना होगा। योगी ने आगरा की घटना के साथ ही जबरन मतांतरण के खिलाफ बनाए गए कानून, लखनऊ में आतंकी पकड़े जाने पर विपक्षी दलों के बयान, माफिया पर कार्रवाई आदि मुद्दों के सहारे विरोधी दलों को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना होगा। लोगों को विपक्ष की नकारात्मकता से बचाना होगा।

सोनिया ने कैप्टन को साधा, सिद्धू को समझाया

कांग्रेस में कलह ▸ पंजाब कांग्रेस में सुलह का रास्ता निकालने हरीश रावत आज जाएंगे चंडीगढ़

- सोनिया गांधी ने सिद्धू को कैप्टन से तालमेल बिठाकर चलने की दी सलाह
- कैप्टन से भी कहा, कोई भी फैसला उनकी सहमति से ही होगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी जंग में फंसे अंतिम सियासी पेंच का फैसला अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। हालांकि हाईकमान ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि सुलह का जो भी अंतिम फार्मूला तय होगा उस पर कैप्टन की सहमति हासिल की जाएगी और पार्टी नेतृत्व उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं लेगा। कैप्टन अमरिंदर की नाराजगी दूर करने और सुलह के फार्मूले का एलान करने के लिए हाईकमान ने पंजाब के प्रभारी महासचिव हरीश रावत को शनिवार को चंडीगढ़ भेजने का फैसला किया है। कैप्टन को साधकर रावत चंडीगढ़ में सुलह का एलान कराने का प्रयास करेंगे।

अमरिंदर सिंह के निकट माने जाने वाले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब के सामाजिक समीकरण को देखते हुए हिंदू समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की आवाज उठाकर संदेश दे दिया कि कैप्टन खेमा सिद्धू को अध्यक्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुलह के अंतिम मोड़ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी से फंसे पेंच का ही नतीजा है कि सोनिया गांधी ने सिद्धू को अचानक शुक्रवार को दिल्ली बुलाया। दस जनपथ पर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ सिद्धू की हुई इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार हाईकमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के रावत के बयान से कैप्टन और उनके समर्थकों के अलावा पंजाब कांग्रेस में मची हलचल के हालातों पर चर्चा की। सिद्धू को समझाया गया कि पंजाब में उन्हें सम्माजनक जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। सिद्धू को पुरानी कड़वाहटें छोड़ कैप्टन के साथ तालमेल बिठाने की सलाह दी गई। इसीलिए सिद्धू ने सोनिया से मुलाकात के बाद कोई टीका-टिप्पणी करने से परहेज भी किया।

गलतफहमी दूर करने को कैप्टन से मिलेंगे रावत : सूत्रों के अनुसार सोनिया ने इस बैठक के दौरान हरीश रावत को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीधी बातचीत कर उनके बयान से पैदा हुए विवाद पर अपना पक्ष रखकर गलतफहमी दूर करने को कहा। मालूम हो कि रावत ने ही बयान दिया था कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हो गया है और इसका एलान बाकी है।

कैप्टन ने सोनिया को किया फोन : रावत के बयान के बाद गुरुवार रात ही कैप्टन ने सोनिया गांधी को फोन कर अपनी नाराजगी जताई। सोनिया ने कैप्टन को कहा कि रावत के बयान के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है और कोई भी फैसला उनकी सहमति से ही लिया जाएगा। इसके बाद सोनिया ने रात में ही रावत को उनके बयान को लेकर तलब किया। तब रावत ने सफाई दी कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। इसके बाद शुक्रवार को बैठक के दौरान ही सोनिया ने रावत को चंडीगढ जाकर कैप्टन से मुलाकात करने का निर्देश भी दिया।



नई दिल्ली में शुक्रवार को सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद वापस जाते कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। प्रेट्र

मनीष तिवारी के ट्वीट ने दी हवा

सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर कैप्टन समर्थकों के एतराज को पार्टी के मुखर सांसद मनीष तिवारी ने टवीट के जरिए पंजाब के जातीय सामाजिक समीकरण के आंकड़े की बात उठाकर और हवा दे दी। तिवारी ने कहा, 'सिख 57.75 फीसद, हिंदू 38.49 फीसद और दलित 31.49 फीसद (सिख व हिंदू)। पंजाब प्रगतिशील और सेक्यूलर दोनों है मगर सामाजिक समूहों के बीच संतुलन अहम है। बराबरी सामाजिक न्याय की बुनियाद है।'

तिवारी के ट्वीट के मायने

कांग्रेस सांसद के इस बयान को सीधे तौर पर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ कैप्टन खेमे की आवाज के रूप में देखा जा रहा है। वैसे कैप्टन अमरिंदर हिंदू समुदाय के चेहरे को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपने के पक्ष में हैं और मनीष तिवारी को उनकी पसंद के एक प्रमुख चेहरे के रूप में माना जाता है।

पंजाब कांग्रेस में गुटबंदी हुई तेज

इस बीच, पंजाब कांग्रेस के दोनों खेमों के बीच तत्काल खेमेबंदी तेज हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाकर अपनी नाराजगी दर्शाई वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने समर्थकों संग बैठक की। हालांकि रात में ही सिद्धू को दिल्ली पहुंचने का हाईकमान से बुलावा आ गया और वे शुक्रवार सुबह सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। लेकिन दिलचस्प यह भी रहा कि सिद्धू के साथ बैठक से पहले ही अमरिंदर सिंह के ओएसडी नरिंदर भांबरी सुबह ही कैप्टन के संदेश का लिफाफा लेकर दस जनपथ पहुंच गए। सभी की निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई हैं।

आनलाइन बैठक से पहले भाजपाइयों में चले लात-घूंसे

- पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी पर पवन गोयल को पीटने का आरोप
- स्थानीय भाजपा नेताओं ने इस घटनाक्रम पर साधी चुप्पी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आनलाइन बैठक में हिस्सा लेने के लिए भाजपा जिला कार्यालय (गाजियाबाद) में पहुंचे पार्टी के दो कार्यसमिति सदस्य प्रशांत चौधरी और पवन गोयल वरिष्ठ नेताओं के सामने ही आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर जमकर लाते घूंसे चले। निजी अस्पताल में भर्ती पवन गोयल ने प्रशांत चौधरी पर वैश्य समाज के लिए अपमानजनक शब्द बोलने और विरोध पर पीटने व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत चौधरी का कहना है कि पवन गोयल ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। पवन के भाई संदीप ने थाना सिहानी गेट में प्रशांत चौधरी के खिलाफ शिकायत दी है वहीं दूसरी ओर प्रशांत चौधरी जिले से बाहर चले गए हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साध ली है।

दोनों गुट ने दिया धरना: पवन गोयल को देखने स्वजन और भाजपा नेता गायत्री अस्पताल पहुंचे। यहां अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन ने अस्पताल में ही प्रशांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। संगठन के अध्यक्ष वीके अग्रवाल से भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक मोंगा ने प्रदर्शन न करने की अपील की, लेकिन वीके अग्रवाल नहीं माने।

> पवन गोयल मुझे निशाना बनाते हुए जातिसूचक टिप्पणी कर रहे थे। विरोध पर गाली दी और बाहर आते ही मेरा कालर पकड़ लिया। दूर करने की कोशिश की तो भी पवन का कुर्ता फट गया। मेरे एक कारोबारी साथी की मौत के चलते मुझे सिलीगुड़ी निकलना पड़ रहा है, बाद में पुलिस को शिकायत दूंगा। -प्रशांत चौधरी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, भाजपा।

> प्रशांत चौधरी ने वैश्य समाज के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की व कपड़े फाड़ दिए। मेरे भाई ने तहरीर दी है पुलिस अपनी कार्रवाई करे। -पवन गोयल, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, भाजपा।

त्रिवेदी के इस्तीफे से खाली हुई रास सीट पर भाजपा भी उतारेगी उम्मीदवार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़कर पिछले दिनों भाजपा का दामन थामने वाले दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट पर नौ अगस्त को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। उधर, जीत की संभावना नहीं होने पर भी भाजपा उम्मीदवार उतारेगी।

गौरतलब है कि इसी साल बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 12 फरवरी को त्रिवेदी ने टीएमसी से नाता तोड़ते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग के अनुसार दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर नौ अगस्त को कोरोना नियमों का पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। उधर, दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देने से रिक्त हुई राज्यसभा सीट पर जीत की संभावना नहीं होने के बावजूद भाजपा अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा करने के पीछे भाजपा का मकसद अपने पार्टी विधायकों को व्हिप जारी कर मुकुल राय पर दबाव बनाना है। सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से बातचीत करेगा।

ममता के बाद टीएमसी की एक और पराजित प्रत्याशी ने दी परिणाम को चुनौती

राब्यू, कोलकाता : बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से नंदीग्राम में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद एक और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पराजित प्रत्याशी ने परिणाम को लेकर चुनौती दी है।

उत्तर 24 परगना जिले की बनगांव दक्षिण विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस की हारी हुईं उम्मीदवार की चुनावी याचिका पर शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। इस याचिका में भाजपा प्रत्याशी की जीत को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने चुनाव आयोग को तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार आलो रानी सरकार की याचिका के संबंध में बनगांव दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चुनाव से संबंधित सभी रिकार्ड को संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस सीट से भाजपा के स्वप्न मजूमदार को 2,004 मतों से जीत मिली है। अदालत ने निर्देश दिया है कि मामले पर 30 जुलाई को सुनवाई होगी।

मुकुल को अयोग्य करार देने की अर्जी पर विस में सुनवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : पिछले दिनों बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीतने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में वापस गए वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुकुल को भाजपा विधायक के रूप में अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के समक्ष दायर की गई शिकायत पर शुक्रवार को पहली बार सुनवाई पूरी हुई। बिमान बनर्जी ने भाजपा विधायकों की ओर से की गई शिकायत पर सुनवाई की। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। दूसरी ओर, मुकुल को अयोग्य घोषित करने के लिए भाजपा कलकत्ता हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटागी। सुवेंदु अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

सुवेंदु ने कहा कि मुकुल ने दलबदल कानून का उल्लंघन किया है। हम राज्य में दलबदल विरोधी कानून लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रुख करेंगे।

दूसरी ओर टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दो सांसदों शिशिर अधिकारी व सुनील मंडल को लोकसभा सचिवालय की ओर से दलबदल विरोधी कानून के तहत नोटिस भेजा गया है। इसके बाद मुकुल रॉय पर भी दबाव बढ़ सकता है।

उप्र में लोकतंत्र का हो रहा चीरहरण : प्रियंका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है। कुछ ऐसा ही मानते हुए कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंचायत चुनाव में योगी सरकार की कथित अराजकता के विरोध को मौन अभिव्यक्ति दी। डेढ़ साल बाद शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचीं प्रियंका हजरतगंज के जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पंचायत चुनाव में हुई जोर जबर्दस्ती और अराजकता के खिलाफ मौन धारण कर धरने पर बैठ गईं। तकरीबन पौने दो घंटे धरने पर बैठने के बाद वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचीं जहां उन्होंने अपनी चुप्पी मीडिया के सामने तोड़ी। यह कहते हुए कि यह मौन देश व प्रदेशवासियों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने के लिए था कि उप्र में संविधान नष्ट हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। वह लोकतंत्र के पक्ष में और जनता के समर्थन में बोलने आयी हैं।

अहिंसा के पुजारी और सविनय अवज्ञा के नायक राष्ट्रपिता के प्रतिमा स्थल पर मौन धरना देकर प्रियंका ने प्रतीकात्मक रूप से सियासी संदेश दिया। उनका यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि गांधी प्रतिमा स्थल के बेहद करीब सड़क के उस पार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रियंका ने कहा कि गुरुवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बहुत अच्छा काम करने का प्रमाणपत्र दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब उप्र में विकासवाद चल रहा है। प्रियंका ने सवाल किया कि यह कैसा विकासवाद है कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने पंचायत चुनाव कराये, जिसमें भारी तादाद में लोग संक्रमित हुए और बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जान गंवाई। सरकार ने चुनाव इसलिए कराया, क्योंकि उसे लगता था कि वह जीतेगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख चुनावों में उसने हिंसा फैला दी। पुलिस ने उम्मीदवारों को उठाया, प्रत्याशियों के नामांकन पत्र फाड़े गए। प्रशासन उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को धमकाता रहा, महिलाओं को मारा-पीटा गया, उनके वस्त्र खींचे गए। गोलियां-बम चले। जब से यह सरकार आयी है, लोकतंत्र पर ऐसे वार हो रहे हैं। लोकतंत्र को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। सरकार सोच रही थी कि जनता चुप रहेगी और विपक्ष भी, लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज उठाने आए हैं।

कांग्रेसियों को भी चौंकाया : मौन धरना देकर प्रियंका ने कांग्रेसियों को भी चौंका दिया। दोपहर 3:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय भवन के पोर्टिको में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी अगवानी के लिए लाइन से खड़े हो गए। सब उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर बाद एलान हुआ कि प्रियंका सरकार की नीतियों के खिलाफ गांधी प्रतिमा स्थल पर धरने पर बैठ गई हैं। इसके बाद कांग्रेसियों का हुजूम पीसीसी दफ्तर से हजरतगंज की ओर कूच कर गया, जबकि वरिष्ठ नेता अंदर कमरे में बैठकर अपनी नेता का इंतजार करने लगे।



उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के विरोध में लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठीं प्रियंका गांधी। साथ में हैं अजय लल्लू (दाएं)। जागरण

सामाजिक माहौल को बदले बिना जनसंख्या नियंत्रण असंभव : बशिष्ठ

राज्य ब्यूरो, पटना : जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में शुक्रवार को जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य बशिष्ठ नारायण सिंह ने भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि यह विषय सीधे तौर पर व्यक्ति के निजी जीवन के मसलों से जुड़ा है। इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और उसकी सुरक्षा सभी एक चक्र की भांति काम करते हैं। इसलिए सामाजिक व शैक्षणिक माहौल को बदले बगैर जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है।

बशिष्ठ ने कहा कि हमें बेटियों को सर्वाधिक शिक्षित करना होगा, तभी हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकेंगे। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने भी इससे इतर सभी संभावनाओं को वर्षों पहले नकार दिया था। जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले लाया गया, वहां भी अब तक इसकी कोई संस्थागत समीक्षा नहीं की गई कि लक्ष्य हासिल करने में ये कानून कितने कामयाब रहे। राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर को देखते हुए लगता नहीं कि कानून से कुछ ज्यादा फायदा हुआ है।

बकौल बशिष्ठ, उत्तर प्रदेश से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और हरियाणा में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया। सबसे पहले 2000 में राजस्थान सरकार ने ऐसा कानून लागू किया था, लेकिन 2018 में उसे इस कानून को लचीला बनाना पड़ा।

विश्लेषण

> राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आंख खोलने वाली, आयोग की सिफारिशों पर हाई कोर्ट का कोई भी निर्देश ममता सरकार को पड़ सकता है भारी

रिपोर्ट से बढ़ सकती हैं ममता सरकार की मुश्किलें

इंद्रजीत सिंह, कोलकाता

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी गई 50 पन्नों की अंतिम जांच रिपोर्ट से ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि यह रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। दूसरी तरफ अगर हाई कोर्ट एनएचआरसी की सिफारिशों पर अमल करते हुए कोई निर्देश देता है तो उससे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है।

गौरतलब है कि एनएचआरसी की रिपोर्ट में ममता सरकार की कड़ी आलोचना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में 'कानून का राज' नहीं है, बल्कि यहां 'शासक का कानून' चल रहा है। रिपोर्ट में हिंसा के गंभीर मामलों की सीबीआइ जांच कराने की सिफारिश की गई है। इस पर जाने-माने सियासी विश्लेषक तथा रबींद्र भारती विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर बिश्वनाथ चक्रवर्ती का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस के बाद वाममोर्चा तथा इसके बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) तीनों पार्टियों के शासनकाल में विरोधी दल के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए गए हैं। लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा का दायरा काफी बड़ा रहा है। इस संदर्भ में एनएचआरसी की रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। बिश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि एनएचआरसी ने हाई कोर्ट से दुष्कर्म तथा हत्या से जुड़े गंभीर मामलों की सीबीआइ से जांच कराने तथा अन्य गंभीर मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने की सिफारिश की है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट एनएचआरसी की सिफारिशों पर अमल करते हुए कोई निर्देश देता है तो यकीनन इससे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

सिफारिशों को नकारना हाई कोर्ट के लिए काफी मुश्किल: राजनीतिक विश्लेषक तथा जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. इमनकल्याण लाहिरी का कहना है कि एनएचआरसी की सिफारिशों को नकारना हाई कोर्ट के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि उसी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित हुई है। उन्होंने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे नहीं तो आने वाले दिनों में उसकी और फजीहत हो सकती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस की विस्तार करने योजना को भी बट्टा लग सकता है। भले ही ममता बनर्जी कहें कि यह बंगाल को बदनाम करने की साजिश है, पर इसका असर जरूर पड़ेगा।

केस दर्ज होने पर तृणमूल के कई बड़े नेता आ सकते हैं चपेट में : एनएचआरसी की रिपोर्ट में अपराधियों की सूची में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल किया गया है। करीब 1979 हिंसा की शिकायतों को राज्य के डीजीपी को भेजा गया है ताकि उक्त मामलों में एफआइआर दर्ज हो सके। अगर ऐसा होता है तो तृणमूल के कई बड़े नेता इसकी चपेट में आ सकते हैं, जो सत्ताधारी दल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसके अलावा पीड़ितों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के साथ उनके पुनर्वास, सुरक्षा और आजीविका की व्यवस्था कराए जाने संबंधी हाई कोर्ट का कोई भी निर्देश ममता सरकार का बोझ बढ़ा सकता है।



ममता बनर्जी रिपोर्ट को बंगाल को बदनाम करने की साजिश बता रही हैं। फाइल/इंटरनेट मीडिया

ममता की तरह असहिष्णु सरकार पूरे देश में कहीं नहीं : भाजपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की जांच समिति द्वारा हाई कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट का स्वागत करते हुए प्रदेश भाजपा ने ममता सरकार व तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एनएचआरसी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि ममता सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और राज्य में टीएमसी के गुंडों को हिंसा के लिए खुली छूट दे दी थी। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में ममता की तरह असहिष्णु सरकार नहीं हैं, जहां मुख्य विपक्षी दल के साथ इस तरह प्रतिशोध या अमानवीय व्यवहार किया जाता है।

भाजपा प्रवक्ता ने हिंसा को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की विफलता के लिए ममता को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के बाद अब तक कम से कम 40 कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन हत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

'मानवाधिकार आयोग के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाश रहा हूं'

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति द्वारा कुख्यात अपराधियों की सूची में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के नाम शामिल किए जाने से व्यथित ममता सरकार के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने शुक्रवार को कहा कि वह कानूनी विकल्प तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कदम उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अदालत में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।

4 लाख पेटियां पहुंची सेब राज्य से देश की मंडियों में। 800 से 3500 रुपये प्रति पेटी तक बिक रहा हिमाचली सेब।

मुठभेड़ में आइएसजेके के दो आतंकी ढेर

एक कालोनी में अपने संपर्क सूत्र के घर में छिपे थे दोनों

मुठभेड़ में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर समेत दो जवान जख्मी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर



श्रीनगर में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद क्षतिग्रस्त घर के बाहर जमा लोग। एएनआइ

श्रीनगर में बड़े हमले का मौका तलाश रहे इस्लामिक स्टेट आफ जम्मू कश्मीर (आइएसजेके) के दो आतंकियों इरफान और बिलाल को सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान एक सबइंस्पेक्टर समेत दो सीआरपीएफ कर्मी जख्मी हो गए। आतंकी ठिकाना बना मकान भी मुठभेड़ के दौरान लगी आग में क्षतिग्रस्त हो गया। मारे गए आतंकियों के पास से एक एके-47 राइफल, एक पिस्तौल और चार ग्रेनेड मिले हैं। आइजीपी ने बताया कि कश्मीर में पहली जनवरी, 2021 से अब तक 78 आतंकी मारे गए हैं।

आइएसजेके के दो आतंकी गुरुवार की रात को श्रीनगर शहर के आलमदार कालोनी में अपने एक संपर्क सूत्र के घर में रुके थे। पुलिस को कुछ ही देर में इनकी भनक लग गई। पुलिस ने उसी समय सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर आलमदार कालोनी को चारों तरफ से घेरते हुए तलाशी शुरू कर दी। शुक्रवार की तड़के चार बजे जवानों ने जैसे ही आतंकी ठिकाना बने मकान में घुसने का प्रयास किया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सीआरपीएफ का सबइंस्पेक्टर भूपेंद्र शर्मा और कांस्टेबल यूनिस अहमद डार जख्मी हो गए। दोनों को उसी समय अस्पताल पहुंचाया गया।

सुरक्षाबलों ने आतंकियों को सरेंडर के लिए कई बार कहा, लेकिन वह नहीं माने। आइजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि अंततः हमें उन्हें मार गिराने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह लगातार गोलियां दाग रहे थे। यह मुठभेड़ सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुई। मकान में छिपे दोनों आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों की पहचान इरफान अहमद सोफी और बिलाल अहमद के रूप में हुई है। दोनों ही श्रीनगर के नटीपोरा इलाके रहने वाले थे और 14 दिसंबर 2020 को आतंकी बने थे। मुठभेड़ के दौरान लगी आग में मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। आइजीपी ने बताया कि जून में श्रीनगर और उसके साथ सटे इलाकों में हुई आतंकी घटनाओं के बाद से पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। अब इन दोनों को मार गिराया गया है।

मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल थे : मारे गए दोनों आतंकी उन नौ मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल थे, जिनके नाम व पोस्टर पुलिस ने 13 मार्च 2021 को जारी किए थे। इन दोनों ने बीते सात माह के दौरान श्रीनगर और उसके साथ सटे इलाकों में अपने साथियों संग मिलकर लगभग डेढ़ दर्जन आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। इनमें इंस्पेक्टर परवेज अहमद समेत तीन पुलिसकर्मियों की हत्या, सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला, पुलिस चौकियों और नाका पार्टियों पर ग्रेनेड हमला भी शामिल है।

श्रीनगर में तैयार कर रहे थे आइएसजेके का नेटवर्क : इरफान और बिलाल बीते साल दिसंबर में द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) में बतौर आतंकी शामिल हुए थे। कुछ समय पहले ही दोनों अपने कुछ साथियों के साथ आइएसजेके में शामिल हो गए। यह दोनों अपने ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क के जरिये अपनी वारदात के किस्से स्थानीय युवकों में फैलाते और उनके बीच अपना प्रभाव बढ़ाते। इसके बाद यह दोनों जिहादी मानसिकता वाले युवकों को चिह्नित करते और उन्हें आतंकी संगठन में भर्ती होने के लिए तैयार करते। यह दोनों श्रीनगर और उसके साथ सटे इलाकों में आइएसजेके का नेटवर्क तैयार कर रहे थे।

नटीपोरा में दिनभर रहा तनाव: इरफान और बिलाल के मारे जाने की खबर के साथ ही नटीपोरा में तनाव पैदा हो गया।

पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन

गुरदासपुर, जासं : भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शुक्रवार तड़के फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। हालांकि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों की फायरिंग के बाद वह वापस लौट गया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में डेरा बाबा नानक के ठेठरके, आबाद पोस्ट, मेतला आदि सीमावर्ती पोस्टों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। शुक्रवार सुबह करीब पौने पांच बजे डेरा बाबा नानक के पास बीएसएफ की रोड पोस्ट पर इन्हें देखा गया।

त्राल में आतंकी ठिकाने से मिले सात मोर्टार बम और 260 कारतूस

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर में त्राल में सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। इस ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद मिला है। इसमें 51 एमएम के सात मोर्टार बम और पिका गन के 260 कारतूस भी शामिल हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अवंतीपोरा पुलिस को तड़के नावडल में आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। पुलिस ने उसी समय सेना की 42 आरआर व सीआरपीएफ की 180वीं वाहिनी के जवानों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया।

जम्मू-कश्मीर में गोवंश के वध पर रोक का आदेश, विवाद बढ़ने पर पलटे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- पशु एवं भेड़ पालन विभाग के अधिकारी बोले-यह आदेश नहीं, पशु क्रूरता रोकने का अनुरोध है
- घाटी में बीते कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ी है ऊंट व गोवंश के वध की प्रवृत्ति

जम्मू-कश्मीर में बकरीद पर गोवंश के वध पर रोक लगाने संबंधी पशु एवं भेड़ पालन विभाग के निदेशक का आदेश शुक्रवार शाम तक विवादों में घिर गया। विवाद बढ़ता देख अधिकारी ने सफाई दी कि यह आदेश नहीं केवल पशु क्रूरता रोकने के लिए अनुरोध है। यहां बता दें कि गुरुवार को विभाग के निदेशक ने मंडल आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर बकरीद पर गोवंश की दी जाने वाली बलि पर रोक लगाने को कहा था। इसके साथ ही उन्होंने ऊंट एवं अन्य जानवरों की गैरकानूनी ढंग से दी जाने वाली बलि पर रोक लगाने को कहा था। शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर यह पत्र वायरल होते ही कश्मीरी संगठनों ने विरोध जताना आरंभ कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर में पहली बार ईद से पूर्व जानवरों की कुर्बानी से संबंधित मुद्दे पर पहली बार इस तरह का कोई आदेश अथवा पत्र सरकारी स्तर पर जारी किया गया है। बता दें कि घाटी में बीते कुछ वर्षों से ऊंट व गोवंश के वध की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है।

पत्र में इन नियमों को प्रभावी बनाने पर जोर : निदेशक जीएल शर्मा ने पशु कल्याण बोर्ड के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि बकरीद का त्योहार संभवतः 21 से 23 जुलाई 2021 को है और इस दौरान जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर जानवरों की कुर्बानी किया जाएगा। इसलिए पशु कल्याण से संबंधित सभी नियम और कानून पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960, पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने संबंधित पशु कल्याण बोर्ड नियम 1978, बूचड़खाना नियम 2001, म्यूनिसिपल ला एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया द्वारा पशुओं का वध किए जाने संबंधी नियमों को पूरी तरह प्रभावी बनाया जाए। इसको लेकर जनमत भी तैयार किया जा रहा है।

मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने जताया कड़ा एतराज

पत्र के वायरल होने के साथ ही वादी में तनाव पैदा हो गया। कश्मीर में विभिन्न इस्लामिक संगठनों के साझा मंच मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) के बैनर तले कश्मीर के विभिन्न इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई। बैठक के बाद एमएमयू ने एक बयान जारी कर बकरीद पर सरकार के इस आदेश-निर्देश को आपत्तिजनक और मजहबी मामलों में हस्तक्षेप बताया। उन्होंने सरकार को अपना यह आदेश वापस लेने को कहा।

प्रशासन ने शाम को जारी किया स्पष्टीकरण

मामले को तूल पकड़ते देख प्रशासन ने भी शाम को स्पष्टीकरण जारी कर दिया। पशु एवं भेड़पालन और मछली विभाग के योजना निदेशक जीएल शर्मा ने कहा कि किसी भी जानवर को कुर्बान करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जिस पत्र की बात की जा रही है, वह कोई आदेश नहीं है, वह अनुरोध पत्र है, जिसमें कानून लागू करने वाली संस्थाओं से पशु क्रूरता रोकने का अनुरोध किया गया है।

2019 से पहले जम्मू-कश्मीर में गोवंश का वध दंडनीय अपराध था

पांच अगस्त 2019 से पहले के जम्मू-कश्मीर में रणबीर पैनल कोड (आरपीसी) की धारा 298-ए के मुताबिक गोवंश का वध करना एक गैर जमानती दंडनीय अपराध था। ऐसा करने वाले को कम से कम 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। इसके अलावा 298-बी के तहत ऐसे जानवरों का मांस रखने पर एक साल की सजा का प्रावधान था। यह कानून डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह ने 1862 में लागू किया था। उन्होंने पूरे प्रदेश में बीफ पर पूरी तरह पाबंदी लगाई थी। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद फिर से ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

ईडी ने जब्त की अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ की संपत्ति

राज्य ब्यूरो, मुंबई

कसा शिकंजा

- देशमुख पर चल रहे मनी लांड्रिंग केस के तहत की गई कार्रवाई
- महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर है भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की चार करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई देशमुख पर चल रहे मनी लांड्रिंग केस के तहत की गई है। देशमुख एवं उनका परिवार ईडी के कई समन के बावजूद उसके सामने पेश होने से बचता आ रहा है।

ईडी सूत्रों के अनुसार, पीएमएलए एक्ट के तहत अनिल देशमुख की कुछ ऐसी संपत्तियों की कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किए गए हैं, जो सीधे उनके नाम पर तो नहीं हैं, लेकिन इन पर उनका ही कब्जा है। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 4.20 करोड़ रुपये आंकी गई है। इनमें मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक फ्लैट भी शामिल है। यह फ्लैट उनकी पत्नी के नाम पर है। इसकी कीमत 1.54 करोड़ रुपये आंकी गई है। 2004 में खरीदे गए इस फ्लैट की पूरी कीमत नकद चुकाई गई थी। लेकिन इसकी रजिस्ट्री 2020 में हुई, जब अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे। ईडी ने देशमुख परिवार की रायगढ़ स्थित एक संपत्ति भी कब्जे में ली है, जिसकी कीमत 2.67 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह संपत्ति उनके परिवार की हिस्सेदारी वाली एक कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रा.लि. के नाम पर है। ईडी का कहना है कि इस कंपनी के पास भूखंड एवं कुछ दुकानें मिलाकर 5.34 करोड़ की संपत्ति है। कंपनी में 50 फीसद हिस्सेदारी देशमुख परिवार ने सिर्फ 17.95 लाख रुपये देकर खरीदी थी। यह रकम भी काफी बाद में अदा की गई थी।

बता दें कि अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग का आरोप लगने के बाद ईडी एवं सीबीआइ जैसी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने इसी वर्ष मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर पुलिस अधिकारियों को बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूली का टार्गेट दिया था।

मप्र में बड़ा हादसा, कुएं से निकाले गए 11 शव

नईदुनिया, भोपाल

- गुरुवार शाम को हुए हादसे में कुएं में गिर गए थे 27 ग्रामीण, 16 सकुशल बचाए गए
- रात 10 बजे तक कुएं के मलबे में दबे सभी शव निकाल लिए गए



मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गांव लाल पठार में गुरुवार शाम कुएं को ढंकने के लिए बनाई गई स्लैब के टूटने के बाद घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य करते प्रशासन के लोग। नईदुनिया

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील के गांव लाल पठार में गुरुवार शाम कुएं को ढंकने के लिए बनाई गई स्लैब धराशायी होने से जो 27 लोग कुएं में गिर गए थे, उनमें से 11 की मौत हो गई। 27 में से 16 को गुरुवार को ही सकुशल बचा लिया गया था, जबकि 11 लोगों के शव शुक्रवार रात 10 बजे तक निकाले गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृत व्यक्तियों के स्वजन को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि लाल पठार गांव में गुरुवार शाम 6:30 बजे गांव का ही 14 वर्षीय बालक रवि अहिरवार पानी भरते समय कुएं में गिर गया था। कुआं सीमेंट के स्लैब से ढंका हुआ था और पानी निकालने के लिए जरा सी जगह खुली थी। उसी खुली जगह में से रवि को बचाने के लिए तीन-चार लोग कुएं में उतरे। कुएं के अंदर अंधेरा था, इसलिए अन्य ग्रामीण कुएं की स्लैब पर खड़े होकर अंदर मोबाइल की टार्च से रोशनी करने लगे। इसी दौरान स्लैब पर कौतूहलवश कुछ और ग्रामीण चढ़ गए। इनके वजन से अचानक स्लैब टूट गए और 27 ग्रामीण 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। बारिश के कारण कुआं 20 फीट तक भरा हुआ था। इन्हें बचाने के लिए अन्य ग्रामीणों ने कुएं की मुंडेर के पास ट्रैक्टर खड़ा किया व डीजल पंप से कुएं का पानी बाहर निकालने लगे। बारिश के मौसम के कारण कुएं की मुंडेर के पास की जमीन भी दलदली थी, इसलिए ट्रैक्टर व डीजल पंप के वजन तथा इनके चलने से पैदा हुए कंपन के कारण वह जमीन भी धंस गए। इससे ट्रैक्टर, पंप व बचाव में लगे राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) के कमांडेंट तथा दो जवान भी कुएं में जा गिरे। इसके बाद बाहर खड़े अन्य ग्रामीणों ने 16 लोगों को सकुशल बचा लिया, लेकिन जो गहरे पानी में थे, वे फंसे रह गए। प्रशासन को सूचना मिलने पर गुरुवार रात से ही बचाव कार्य शुरू हुआ था। भोपाल से पहुंचे बचाव दल ने शुक्रवार रात 10 बजे तक कुएं के मलबे में दबे सभी 11 शव निकाल लिए।

प्रसिद्ध अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का शुक्रवार की सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह 75 साल की थीं। मुंबई के सांताक्रूज स्थित श्मशान गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया।



यादों में सुरेखा।

'बधाई हो' अभिनेत्री के मैनेजर विवेक सिधवानी ने बयान जारी करते हुए कहा कि दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वह बीमार चल रही थीं। अपने आखिरी वक्त में वह अपने परिवार के साथ थीं। उन्हें पिछले साल सितंबर में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। जबकि साल 2018 में उन्हें पहली बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। सिनेमा जगत की कई हस्तियों ने इंटरनेट मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

सुरेखा के साथ काम कर चुके आयुष्मान खुराना ने लिखा कि 'बधाई हो' की स्क्रीनिंग के बाद जब वह आटोरिक्शा ले रही थीं, तो ताहिरा (आयुष्मान की पत्नी) और मैंने उन्हें घर के लिए लिफ्ट दी थी। रास्ते में हमने कहा कि मैम, फिल्म की असली स्टार आप हैं। उन्होंने जवाब दिया था काश, मुझे और काम मिलता।

चारधाम के गर्भगृह से नहीं होगा सजीव प्रसारण

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक में हुआ निर्णय
- बोर्ड के सभी सदस्यों की इस भावना से उच्च न्यायालय को कराया जाएगा अवगत

धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए चारधाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों के गर्भगृह से पूजा का सजीव प्रसारण नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को सचिवालय में हुई उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। तय किया गया कि बोर्ड के सभी सदस्यों की इस भावना से उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। न्यायालय ने हाल में चारधाम में पूजा का सजीव प्रसारण करने के निर्देश दिए थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की जो भी शंकाएं हैं, सरकार उनका निदान करेगी।

बोर्ड की बैठक में चारों धामों से पूजा के सजीव प्रसारण के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान तीर्थ पुरोहितों ने इसे सिरे से खारिज किया। उनका कहना था कि मंदिरों के गर्भगृह से पूजा का सजीव प्रसारण धार्मिक परंपराओं के खिलाफ होगा। अलबत्ता, मंदिर परिसर से सजीव प्रसारण हो सकता है। विमर्श के बाद तय किया गया कि चारधाम के मंदिरों के गर्भगृह से पूजा का सजीव प्रसारण नहीं किया जाएगा। ये भी तय हुआ कि बोर्ड के जो सदस्य बैठक में मौजूद नहीं थे, इस संबंध में उनके भी विचार संकलित कर उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उठ रहे विरोध के सुरों के संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि चारधाम के मंदिरों में पुरानी परंपराएं चलती रहेंगी। सरकार का कार्य मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं पर अधिकार करना नहीं, बल्कि सेवा व सहयोग करना है। सरकार का उद्देश्य मंदिर परिसरों की सुविधाओं के विकास में सहयोगी बनना है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों समेत अन्य व्यक्तियों की जो भी शंकाएं हैं, उनसे वार्ता कर इनका समाधान किया जाएगा।

मुंबई में भारी बारिश, 250 लोगों को करना पड़ा स्थानांतरित

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह मीठी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया जिसकी वजह से कुर्ला में झुग्गी इलाके के करीब 250 निवासियों को स्थानांतरित करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से उपनगरीय ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि मीठी नदी का जलस्तर सुबह 3.7 मीटर तक पहुंच गया था जबकि खतरे का निशान चार मीटर पर है। लिहाजा कुर्ला पश्चिम में झुग्गी इलाके क्रांति नगर में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को नजदीकी महानगरपालिका स्कूलों में स्थानांतरित किया गया। बारिश रुकने पर नदी का जलस्तर दो मीटर तक पहुंच गया जिसके बाद लोग अपने स्थानों को लौट गए। भारी बारिश की वजह से पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के कई निचले स्थानों पर जलभराव हो गया जिसकी वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में मुंबई में 253.3 मिलीमीटर बारिश हुई।

फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था मिनहाज

जागरण संवाददाता, कानपुर

पूछताछ में राजफाश

- कुकर बम के बाद इसे बना रहा था, शक्तिशाली हैंड ग्रेनेड जैसा होता धमाका
- शकील ने बताया, कुकर बम की अपेक्षा इसे भीड़भाड़ में रखना आसान
- आवारा जानवरों के फल खाते ही विस्फोट से लोग आते चपेट में

अंसार गजवातुल हिंद के एरिया कमांडर मिनहाज अहमद के इरादे काफी खतरनाक थे। तीन दिन पहले गिरफ्तार आतंकी शकील के मुताबिक, मिनहाज इन दिनों फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था, क्योंकि इसे किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रखना काफी आसान है। उसके घर से आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) को प्रेशर कुकर बम पहले ही मिल चुका है, जिससे वह 15 अगस्त के आसपास धमाका करने की योजना बना रहा था।

एटीएस ने मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके तीन साथियों को भी पकड़ा है। इनमें अंसार गजवातुल हिंद का एरिया सब कमांडर शकील भी है। उसने एटीएस को बताया है कि मिनहाज का मानना था कि प्रेशर कुकर बम वर्षों से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में इस्तेमाल होता रहा है। हालांकि, बड़ें आकार के कारण उसको कहीं पर भी रखने में दिक्कतें हैं। दूसरे कई बार लोगों को शक भी होता है। ऐसे में वह इस तरह के बम की तलाश में था, जिसे रखने में खतरा कम हो और नुकसान अधिक करे।

केरल में हथिनी को मारने की घटना को देखकर बनाई थी योजना : शकील के मुताबिक, मिनहाज को फ्रूट बम बनाने का खयाल केरल के मल्लपुरम में एक साल पूर्व हुई एक घटना को देखकर आया था। वहां जून 2020 में तस्करों ने एक गर्भवती हथिनी को मारने के लिए अनानास में बम रखकर उसे खिलाया था। अनानास खाते ही बम फटने से हथिनी की मौत हो गई थी।

हैंड ग्रेनेड को फल में फिट करने की थी योजना: मिनहाज फ्रूट बम के रूप में हैंड ग्रेनेड रखने की तैयारी में था। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना था कि ग्रेनेड को फल के अंदर रखना था। ग्रेनेड विस्फोट से पहले जहां उसकी पिन निकाली जाती है, वहीं फ्रूट बम में दबाव पड़ते ही विस्फोट होने के तरीके पर काम चल रहा था। योजना के मुताबिक, फ्रूट बम को कहीं पर ले जाकर रखने से भीड़भाड़ वाले स्थान पर जानवर के खाते ही विस्फोट होने से तमाम लोग हताहत होते।

जैसा विस्फोटक, वैसी तबाही: एक जानकार के मुताबिक, फ्रूट बम से कितनी तबाही होती, यह उसमें इस्तेमाल किए गए विस्फोटक पर निर्भर करता। वैसे, इसके असरदार होने का अंदाजा केरल की घटना में हथिनी की मौत से लगाया जा सकता है। अगर शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाने की तैयारी थी तो ये फ्रूट बम एक बार में भीड़भाड़ वाले स्थान पर कई लोगों की जान ले सकता था।

कानपुर में भी पिछले साल हुआ था इस्तेमाल : पिछले साल बाबूपुरवा क्षेत्र में भी इसी तरह के बम का इस्तेमाल हुआ था। इसमें एक गाय घायल हो गई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस अब तक घटना का पर्दाफाश नहीं कर पाई है।

कोट भलवाल जेल में बंद पड़े हैं सभी जैमर

लापरवाही

जेल में पुलिस छापे के दौरान सामने आई लापरवाही, जेल प्रशासन का तर्क, बैटरियों में खराबी के कारण नहीं चल रहे जैमर, जेल में बंद हैं 600 से अधिक आतंकी, अलगाववादी और गैंगस्टर

दिनेश महाजन, जम्मू

देश की अति संवेदनशील जेलों में से एक जम्मू की कोट भलवाल जेल में लगे मोबाइल फोन जैमर बंद पड़े हैं। मौजूदा समय में इस जेल में 600 से अधिक कैदी बंद हैं, जिसमें आतंकियों के अलावा, कई अलगाववादी और गैंगस्टर भी शामिल हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि कैदियों से सांठगांठ के चलते ही जेल में लगे जैमर बंद पड़े हैं। वहीं, जेल प्रशासन का तर्क है कि जैमर के साथ लगाने वाली बैटरियों में आई खराबी के कारण इन दिनों जैमर नहीं चल रहे हैं।

कोट भलवाल जेल में गत गुरुवार को पुलिस के खुफिया विंग के छापे के दौरान हथियार, कई मोबाइल फोन, सिम और मोबाइल बैटरियां मिली थीं। इसी दौरान जेल में लगे जैमर बंद पाए गए। इससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। कोट भलवाल जेल के अंदर से मोबाइल फोन के प्रयोग ने एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाने का काम किया है। इस संबंध में जब पुलिस महानिदेशक जेल वी श्रीनिवासन से पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर फोन लगाया गया तो उन्होंने नहीं उठाया।



कोट भलवाल जेल में लापरवाही। फाइल फोटो

जेल के अंदर से चल रहा नेटवर्क: जेल प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि मोबाइल फोन जैमर को प्रयोग में लाने के लिए बैटरियों की आवश्यकता पड़ती है। पिछले कई महीनों से जैमर की बैटरियां खराब पड़ी हुई हैं। इसी कारण जेल में लगे जैमर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी का लाभ जेल में बैठे आतंकी और गैंगस्टर उठा रहे हैं, जो वहीं से अपने नेटवर्क को चला रहे हैं। इसी वर्ष मार्च में कोट भलवाल जेल से चल रहे रंगदारी के रैकेट का भी जम्मू पुलिस ने भंडाफोड़ किया था।

समय-समय पर बंद कर दिए जाते हैं जैमर : कोट भलवाल जेल में वर्ष 2013 में गृह मंत्रालय द्वारा छह मोबाइल फोन जैमर लगाए गए थे। सूत्र दावा करते हैं कि किन्हीं कारणों से इन मोबाइल फोन जैमर को समय-समय पर बंद कर दिया जाता है।

कैसे काम करता है मोबाइल फोन जैमर: यह जैमर एक ऐसा डिवाइस है, जो मोबाइल पर आने वाले नेटवर्क को रोकता है। जब इसे आन किया जाता है तो इसकी रेंज में आने वाले सभी मोबाइल में सिग्नल आना बंद हो जाता है और नो नेटवर्क का निशान आने लगता है। इस दौरान मोबाइल फोन पर इंटरनेट का प्रयोग भी नहीं हो पाता है। जैमर मोबाइल फोन के अलावा रिमोट और वाकी-टाकी को भी रोक देता है।

बड़ी आतंकी वारदात के फिराक में थे जेएमबी आतंकी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : पिछले दिनों कोलकाता से गिरफ्तार जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आतंकियों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) व कोलकाता के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की पूछताछ में इसके संकेत मिले हैं। एनआइए की टीम में दिल्ली से आए लगभग 15 अधिकारी शामिल हैं। जांच में कोलकाता एसटीएफ को आतंकी नजीउर अंसारुल्लाह के पास से 'हलाल एंड फ्रेश' नाम के एक विशेष कोड की जानकारी मिली है। एसटीएफ के अधिकारी उसे डीकोड करने में लगे हैं। इस विशेष कोड का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने में किया जा सकता था।

आइएसआइ के लिए जासूसी के आरोप में पुलिसकर्मी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पलवल

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान के पोखरण और उप्र के आगरा कैंट के बाद अब हरियाणा के पलवल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अंबाला का रहने वाला पूर्व सैन्यकर्मी सुरेंद्र कुमार पलवल पुलिस कार्यालय में तैनात है। उसके पास से दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। झज्जर के खाचरौली गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार का परिवार अर्से से अंबाला के ओह गांव में रह रहा है। उसका विवाह चरखी दादरी में हुआ है। 1993 में सेना में भर्ती हुआ सुरेंद्र 30 जून, 2017 को सेवानिवृत्त होने के बाद सैनिक कोटे से मार्च, 2019 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ। पुलिस के मुताबिक 2017 में सेवानिवृत्त होने के बाद सुरेंद्र फेसबुक के माध्यम से एक महिला के संपर्क में आया। महिला ने खुद को दुबई की रहने वाली बताया था और कहा कि वह एक पत्रकार है। लिहाजा, आपको सिर्फ जानकारी देनी है और इसके बदले में राशि देंगे, जिसके बाद आरोपित महिला को वाट्सएप पर आर्मी से जुड़ी खुफिया सूचना देने लगा। इस दौरान वह महिला के अलावा कुछ और लोगों से संपर्क में आया, जो आइएसआइ से जुड़े थे। जानकारी देने के बदले 2018 से अब तक सुरेंद्र को 65 से 70 हजार रुपये मिल चुके हैं। पुलिस ने आरोपित के मोबाइल को साइबर लैब भेज दिया गया है। आरोपित के खाते में विदेश से कई बार रकम डाली गई थी, वह खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया था। कैंप थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को अदालत में पेश कर छह दिन की रिमांड पर लिया है।

डेल्टा वैरिएंट ने दोनों डोज लेने वालों को भी किया संक्रमित

परेशानी ▶ आइसीएमआर के मुताबिक , टीकाकरण के बाद संक्रमित होने वाले 86 फीसद में मिला डेल्टा वैरिएंट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में वे लोग भी संक्रमित हो गए, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों या एक डोज ली थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के अध्ययन से साफ हुआ है कि इसके लिए मुख्यतौर पर कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट जिम्मेदार है। हालांकि, वैक्सीन लेने वालों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत कम आई और मौतें भी न के बराबर हुईं।

आइसीएमआर के एक वरिष्ठ विज्ञानी ने बताया कि अध्ययन में महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, मणिपुर, असम, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, दिल्ली, बंगाल और तमिलनाडु से कुल 677 ऐसे केस लिए गए, जिन्होंने वैक्सीन की कोई न कोई डोज ले रखी थी। इनमें से 71 ने कोवैक्सीन, 604 ने कोविशील्ड और दो ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म लगवाई थीं। अध्ययन में पाया गया कि वैक्सीन लेने वालों में से 86 फीसद से अधिक संक्रमण डेल्टा वैरिएंट के कारण हुआ है, जिसे भारत में दूसरी लहर के लिए मुख्यतौर पर जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा कप्पा और अल्फा वैरिएंट भी कुछ मामलों में पाए गए। विज्ञानी के अनुसार अध्ययन से एक बार फिर साबित हुआ है कि वैक्सीन भले ही संक्रमण रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हो, लेकिन उसकी गंभीरता को कम करने में कारगर है। अध्ययन में शामिल 677 मामले में सिर्फ तीन की मौत हुई, जो कुल संक्रमितों का 0.04 फीसद है। जबकि कोरोना के कारण मृत्युदर अब भी 1.33 फीसद बनी हुई है। इसी तरह से 677 संक्रमितों में से केवल 67 को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी, जो कुल संक्रमितों का 9.9 फीसद है।

दूसरी लहर में सांस लेने में तकलीफ के ज्यादा मामले मिले : संक्रमितों में सांस लेने की शिकायत देखी गई थी और इसी कारण आक्सीजन की किल्लत खड़ी हो गई थी, जबकि वैक्सीन लेने वालों में से सिर्फ छह फीसद में ही सांस लेने की तकलीफ देखने को मिली।

संक्रमण के हल्के लक्षण मिले

आइसीएमआर ने अध्ययन में यह भी जानने की कोशिश की कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वालों में कौन-कौन से लक्षण देखे गए। इसमें पाया गया कि सबसे अधिक 69 फीसद में बुखार, 56 फीसद में सिरदर्द व जी-मिचलाना, 45 फीसद में खांसी, 37 फीसद में गले में दर्द, 22 फीसद में स्वाद और गंध का चले जाना, छह फीसद ने दस्त, छह फीसद ने सांस लेने में तकलीफ और एक फीसद में आंख में जलन व लाली की शिकायत देखने मिली है।



सेना के सुरक्षा कवच : राजौरी में कोरोना प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद सेना के जवान दूरदराज के गांवों के बच्चों को उनकी कक्षाओं तक सुरक्षित पहुंचाने का बेहद अहम दायित्व भी निभा रहे हैं। एएनआइ

केंद्र ने राज्यों को अब तक वैक्सीन की 41.10 करोड़ डोज मुहैया कराई

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 41.10 करोड़ डोज मुहैया कराई जा चुकी हैं। इसके साथ ही जल्द ही इन्हें 52 लाख डोज और मिल जाएंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार सुबह आठ बजे तक के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इनमें से 38.58 करोड़ से ज्यादा डोज का उपयोग किया गया है। इस तरह अभी इनके पास 2.51 करोड़ डोज बची हुई हैं।

वहीं, कोविन प्लेटफार्म पर शाम छह बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 37,74,666 डोज दी गईं। जबकि, अब तक कुल 39.43 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 31.49 करोड़ लोगों को पहली और 7.93 करोड़ लोगों को दूसरी डोज दी गई हैं। शुक्रवार को कुल 37,033 केंद्रों पर टीके लगाए गए, जिनमें 35,010 सरकारी और 2,023 निजी केंद्र शामिल हैं। कोशिश है कि वैक्सीन की लगातार उपलब्धता बनी रहे।

कोरोना के सभी मौजूदा वैरिएंट के खिलाफ काम करेगी 'वार्म' वैक्सीन

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगर सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में देश को एक ऐसी कोरोना रोधी वैक्सीन मिल जाएगी, जिसे रखने के लिए किसी तरह के विशेष इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे इसे कहीं भी लाना-ले जाना आसान होगा, जिससे टीकाकरण की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु स्थित प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) के स्टार्ट-अप ने इस वैक्सीन को विकसित किया है, जिसे चूहों और हैमस्टर्स पर परीक्षण में कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वैरिएंट के खिलाफ कारगर पाया गया है।

एसीएस इंफेक्शस डिजीज जर्नल में गुरुवार को प्रकाशित शोध रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना रोधी वैक्सीन का यह फार्मूला आइआइएससी के स्टार्ट-अप मायनवैक्स ने विकसित किया है, जिसने चूहे में मजबूत प्रतिरक्षा पैदा की है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक चूहे की प्रजाति के हैमस्टर्स पर भी इसका परीक्षण किया और कारगर पाया गया। यह वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक महीने तक सुरक्षित रहेगी और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी डेढ़ घंटे तक खराब नहीं होगी।

ज्यादातर वैक्सीन के लिए रेफ्रिजरेटर जरूरी: शोध करने वाली टीम में आस्ट्रेलिया के कामनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च आर्गेनाइजेशन (सीएसआइआरओ) के शोधकर्ता भी शामिल थे। टीम के मुताबिक ज्यादातर वैक्सीन को प्रभावी बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत पड़ती है। जैसे आक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए 2-8 डिग्री सेल्सियस तापमान और फाइजर की वैक्सीन के लिए माइनस 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है।

गर्म मौसम वाले देशों के लिए अहम

आइआइएससी के स्टार्ट-अप द्वारा विकसित यह टीका 'गर्म वैक्सीन' है। सीएसआइआरओ के स्वास्थ्य एवं जैव सुरक्षा निदेशक राब ग्रेनफेल ने कहा कि थर्मोस्टेबल या गर्म वैक्सीन गर्म मौसम वाले दूर दराज के क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए बहुत ही अहम है। साबित होगी।

कुछ महीनों में पता चलेगा कितने समय तक बनी रहेगी कोरोना एंटीबाडी

नई दिल्ली, एएनआइ : कोरोना वायरस के खिलाफ संक्रमण और वैक्सीन के चलते पैदा होने वाली एंटीबाडी कितने समय तक आपके शरीर में बनी रहेगी इसके बारे में कुछ महीनों में पता चल जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने यह बात कही, साथ ही यह भी जोड़ा कि एंटीबाडी का जीवनकाल उसके वर्ग और प्रकार पर निर्भर करेगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक एंटीबाडी विभिन्न तरह की हैं और सभी की अलग-अलग उम्र है। यह देखने में आया है कि पिछले साल जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, उनमें से कई को दोबारा कोरोना हो गया। आइजीएम और आइजीजी एंटीबाडी का व्यापक समूह है और इनके अंदर भी कई समूह हैं। शरीर में जब कोई वायरस प्रवेश करता है तो सबसे पहले आइजीएम एंटीबाडी सक्रिय होती है। आजीजी एंटीबाडी देर से बनती है और ज्यादा समय तक टिकी रहती है। मेदांता अस्पताल के इंस्टीट्यूट आफ चेस्ट सर्जरी विभाग के चेयरमैन डा. अरविंद कुमार ने कहा कि अलग-अलग तरह की एंटीबाडी होती हैं और सबकी अपनी उम्र होती है। कोरोना वायरस या वैक्सीन अलग-अलग वर्ग और प्रकार की एंटीबाडी पैदा करती हैं। हर एंटीबाडी की अपनी उम्र होती है और उससे ज्यादा कोई भी नहीं बनी रहती है।

उन्होंने कहा कि हमें अगले कुछ महीनों में पता चल जाएगा कि क्या कोरोना एंटीबाडी छह या एक साल से ज्यादा समय तक बनी रहती है।

अब ड्रोन से होगा कोविड किट एवं नमूने का परिवहन

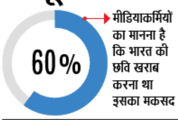
जासं, भुवनेश्वर : कोरोना नमूना संग्रह करते समय संग्रहकर्ता को संक्रमित होने का खतरा रहता है। ऐसे में, ओडिशा में अब ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। नमूना संग्रह से लेकर कोविड के लिए उपयोग होने वाली मेडिकल किट एवं अन्य उपकरणों को ले जाने में ड्रोन की मदद ली जाएगी। गुरुवार को रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर (आरएमआरसी) परिसर में परीक्षण के तौर पर ड्रोन का उपयोग किया किया गया। आरएमआरसी के निदेशक संघमित्रा पति के अनुसार, राज्य में प्रतिदिन 60 से 70 हजार लोगों की जांच की जा रही है। दूरदराज एवं पहाड़ी क्षेत्र में नमूना संग्रह कर लाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के भी संक्रमित होने की संभावना रहती है। यदि नमूना संग्रह में ड्रोन का उपयोग किया जाता है, तो फिर नियोजित कर्मचारियों के मन से संक्रमित होने का भय दूर हो जाएगा।

पश्चिमी मीडिया ने की भारत में कोरोना की पक्षपातपूर्ण कवरेज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भारतीय जन संचार संस्थान (आइआइएमसी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 82 प्रतिशत भारतीय मीडियाकर्मियों की राय में पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत में कोरोना की कवरेज पक्षपातपूर्ण रही है। 69 प्रतिशत मीडियाकर्मियों का मानना है कि इस कवरेज से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई है। 56 प्रतिशत लोगों का कहना है कि इस तरह की कवरेज से विदेश में बसे प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति नकारात्मक राय बनी है।

आइआइएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने बताया कि संस्थान के आउटरीच विभाग द्वारा यह सर्वेक्षण इस साल जून में किया गया। इस सर्वेक्षण में देशभर से कुल 529 पत्रकारों, मीडिया शिक्षकों और मीडिया विशेषज्ञों ने भाग लिया। सर्वेक्षण में शामिल 60 प्रतिशत मीडियाकर्मियों का मानना है कि पश्चिमी मीडिया की कवरेज पूर्व निर्धारित एजेंडे के तहत की गई। 71 प्रतिशत लोगों का मानना था कि पश्चिमी मीडिया की कवरेज में संतुलन का अभाव था। प्रो. द्विवेदी के अनुसार सर्वेक्षण में यही बात कही गई है।



47 जिलों में अब भी संक्रमण दर 10 फीसद से अधिक

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई है, लेकिन 15 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में देश के 12 राज्यों में 47 जिलों में अभी भी संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा बनी हुई है। यही नहीं 73 जिलों में प्रतिदिन औसतन 100 मामले पाए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के नए मामले कम हो रहे है और फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। परंतु, कुछ चिंता बनी हुई है। अभी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, यह जरूर है कि वह कुछ क्षेत्रों में सीमित हो गई है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।

उन्होंने कहा कि जिन 47 जिलों में 10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर है, वे मणिपुर, केरल, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र में फैले हैं।

तीसरी लहर रोकना मुश्किल, दुष्प्रभाव कम होना संभव

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

डा. पाल ने तीसरी लहर की आशंका जताते हुए कहा इस वक्त इसे रोकना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के बावजूद देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो संक्रमण से बचे हुए हैं और वे आसानी से संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से भारत में अभी तक वैक्सीन भी उतनी मात्रा में नहीं लगी है कि संक्रमण के प्रति लोगों में हर्ड इम्युनिटी तैयार हो सके। इस संबंध में उन्होंने अगले तीन-चार महीने को अहम बताया। इस दौरान यदि भारत बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करने में सफल रहता है तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है या उसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

डब्ल्यूएचओ की चेतावनी को हल्के में नहीं ले सकते: डा. पाल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में चेतावनी जारी की है कि दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। तीसरी लहर को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया सकता, यह रेड फ्लैग है।

कोरोना से बचाएगी वैक्सीन: तमिलनाडु पुलिस पर दूसरी लहर प्रभाव का रियल टाइम स्टडी का हवाला देते हुए पाल ने बताया कि वैक्सीन की एक डोज कोरोना से होने वाली मौतों को 85 फीसद और दोनों डोज 95 फीसद तक कम करने में सफल रहा है।

66 करोड़ डोज का आर्डर: सरकार ने तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण की गति तेज करने में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्र ने जुलाई से दिसंबर तक के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 66 करोड़ डोज की आपूर्ति के लिए 14,505.75 करोड़ रुपये का आर्डर कर दिया है। ये दोनों कंपनियां इस दौरान 22 करोड़ डोज निजी क्षेत्र को भी सप्लाई करेंगी। माना जा रहा है कि भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद सरकार स्पुतनिक-वी और दवा नियामक (डीसीजीआइ) से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद जायडस कैडिला को भी वैक्सीन सप्लाई के लिए आर्डर करेगी।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ पर दूसरी बार गिरी आकाशीय बिजली

संवाद सूत्र, उदयपुर: विश्व धरोहर में शुमार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर तेरहवीं सदी में बने कीर्ति स्तंभ पर तीन दिन में दूसरी बार आकाशीय बिजली गिरी है। दूसरी बार गिरी बिजली से स्मारक के झरोखे को नुकसान पहुंचा है, जिससे विश्व धरोहर के संरक्षण को लेकर चिंता गहराने लगी है। इस घटना के बाद जहां जिला कलेक्टर ने मौके का निरीक्षण कर पुरातत्व विभाग के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है, वहीं जैन समाज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि वह ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण नहीं कर पा रहे तो समाज के हवाले कर दें।

गौरतलब है कि गत गुरुवार को कीर्ति स्तंभ पर आकाशीय बिजली गिरी थी। उस समय पुरातत्व विभाग का गार्ड मनीष कलाल पास के ही मंदिर में ड्यूटी दे रहा था। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने संभलने के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इससे पहले गत मंगलवार रात को भी कीर्ति स्तंभ पर बिजली गिरी थी और गुरुवार सुबह जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ संरक्षण सहायक रतन जीतरवाल के साथ कीर्ति स्तंभ का जायजा लेकर नुकसान की जानकारी ली थी। इस दौरान उन्होंने यहां तड़ित चालक नहीं लगे पर होने पर नाराजगी भी जताई थी।

आठ साल पहले तड़ित चालक का तार चुरा ले गए थे चोर: बताया गया कि कीर्ति स्तंभ पर पुरातत्व विभाग ने तड़ित चालक लगवा रखा था, लेकिन आठ साल पहले चोरों ने उसका तांबे का तार चुरा लिया था। इसके बाद नया तार नहीं लगाया गया। जैन समाज हर बार बारिश के मौसम से पहले नया तड़ित चालक लगवाने के लिए विभाग से मांग करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है।

बेहद खास स्मारक है कीर्ति स्तंभ: कीर्ति स्तंभ ऐतिहासिक एवं विश्व धरोहर में शामिल बेहद खास स्मारक है। सात मंजिला 22 मीटर ऊंचे इस स्तंभ का निर्माण भगेरवाल जैन ने बारहवीं सदी में कराया था। यह प्रथम जैन तीर्थंकर, आदिनाथ को समर्पित है। दीवारों पर सुंदर नक्काशी और गलियारों के साथ कीर्ति स्तंभ की वास्तुकला सोलंकी शैली की है। श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष महेंद्र टोंगिया बताते हैं कि इस स्तंभ पर एक हजार से अधिक प्रतिमाएं हैं, जिनका अत्यधिक धार्मिक महत्व है।

बीमारी भगाने के नाम पर झारखंड में चल रहा मतांतरण का खेल

संजय कुमार, रांची: बीमारी भगाने के नाम पर झारखंड के कई इलाकों में मतांतरण का खेल चल रहा है। मतांतरण कराने वाले इसे चंगाई सभा और कई अन्य नाम से जानते हैं। बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिह्नित कर उन्हें ईसाई धर्म के किसी खास व्यक्ति की चमत्कारिक शक्तियों के प्रभाव से बीमारियां भगाने का भरोसा दिलाया जाता है। कम पढ़े- लिखे या अनपढ़ लोग उनकी बातों में आकर ऐसी सभाओं में जाते हैं, जहां मनोवैज्ञानिक तरीके से पीड़ित व्यक्ति से अपनी बात मनवा ली जाती है। सुनियोजित तरीके से मतांतरण टीम के सदस्य पीड़ित व्यक्ति और उसके पूरे परिवार वालों का ब्रेन वाश करते हैं। एक व्यक्ति धर्म बदलता है तो आसपास के कई अन्य लोग भी उसकी राह पकड़ लेते हैं। मतांतरण के काम में लगे लोग चार-पांच की टोली बनाकर पीड़ितों के घर जाते हैं और बीमारी भगाने के नाम पर पानी में दवा मिलाकर पिला देते हैं। मरीज के ठीक होने पर उन्हें झांसा देते हैं और कहते हैं कि चमत्कार के कारण बीमारी ठीक हुई है। जिस सिमडेगा जिले में स्वतंत्रता के समय 90 प्रतिशत हिंदू थे, वहां अब 30 से 35 प्रतिशत हिंदू बचे हैं। इस जिले के लोहरा, बड़ाइक, खड़िया व उरांव समाज के तो 90 प्रतिशत लोग मतांतरित हो चुके हैं। वहीं लातेहार जिले का महुआडांड़ इलाका तो पूरी तरह ईसाई हो चुका है। इस इलाके में गांव के चौक-चौराहों पर क्रूस के चिह्न और मरियम की मूर्ति आसानी से दिख जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री केशव राजू का कहना है कि इन जिलों के कई इलाकों में तो मतांतरण का खेल चल रहा है।

नौकरी और शादी की लालच में बन गया पास्टर: महुआडांड़ के लुरगुमी गांव के बच्चु तुरी का परिवार मतांतरण का शिकार हो गया है। पांच बेटा और तीन बेटी में एक रांची में रहते हुए पास्टर के संपर्क में आया। उसने नौकरी और ईसाई लड़की से शादी का प्रलोभन दिया। उस पास्टर ने सभी को दिग्भ्रमित कर दिया।



लातेहार जिला के महुआडांड़ प्रखंड स्थित चटकपुर गांव के बाहर स्थापित मरियम की मूर्ति। जागरण

छग में गांव-गांव में शाखा और संपर्क

राधाकिशन शर्मा, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में मिशनरियों की गुपचुप चल रही गतिविधियों और मतांतरण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए धर्म जागरण मंच ने नई व्यवस्था बनाई है। मंच के अलावा समरसता विभाग और स्वयंसेवकों की टीम संयुक्त रूप से काम पर जुट गई है। मिशनरियों के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए प्रदेश के गांव-गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बैनर तले शाखा शुरू की जा रही है। कोशिश है कि शाखाओं का शिक्षक कम से कम प्रथम वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हो।

छत्तीसगढ़ में सरकारी भूमि पर बना अवैध चर्च ढहाया गया

पूनमदास मानिकपुरी, कोंडागांव: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर स्थित कोंगेरा पंचायत के एक गांव में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए चर्च को ढहा दिया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने की।

बताया जाता है कि गांव तेलंगा के करीब 20 परिवारों ने मिशनरियों के प्रभाव और प्रलोभन में आकर मतांतरण कर लिया है। उन्होंने गांव में सरकारी जमीन पर कच्ची दीवार और एसबेस्टस शीट की छत डालकर चर्च बना दिया था। कुछ महीने सब ठीक चला पर बाद में सामुदायिक भावना से ओतप्रोत आदिवासी संस्कृति पर असर पड़ने लगा। मतांतरित ग्रामीण न गांव की परंपरा को मानते हैं और न सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इससे नाराजगी बढ़ी तो आदिवासियों ने करीब एक महीने पहले कोंडागांव थाने में शिकायत कर दी थी। ग्राम तेलंगा के एक व्यक्ति ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाया था।

सरकारी सुविधाओं से वंचित हों मतांतरण करने वाले : विहिप

जताया क्षोभ

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे का कहना है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोग हमारे हिंदू परिवार के सदस्य हैं। बहका-फुसलाकर और धन का लोभ देकर उनका मतांतरण करा दिया जाता है और फिर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वह भी प्रदान कराने की साजिश रची जाती है।

यहां विहिप के दो दिवसीय चिंतन शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे परांडे दैनिक जागरण से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे हिंदू परिवार के वंचित और वनवासी भाइयों के हितों पर डाका है। इसके खिलाफ केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में ही इसका प्रारूप सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतांतरण निरोधक कानून में यह प्रविधान भी होना चाहिए कि जिनका मतांतरण हो गया है, उन्हें सरकारी सुविधाएं न मिलें। ईसाई संगठन जिनका मतांतरण कराते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपना नाम न बदलें और सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं लेते रहें। जहां तक मुस्लिम समुदाय द्वारा मतांतरित कराने की बात है तो उनका निशाना निर्धन और जरूरतमंद लोग होते हैं, वे उनको नौकरी अथवा धन से पहले प्रभाव में लेते हैं और फिर ब्रेनवाश करते हैं।

मतांतरण नैतिक अपराध, शून्यकाल में उठाएगे मामला : सांसद विजय बघेल

नईदुनिया, भिलाई : छत्तीसगढ़ में दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने कहा कि मतांतरण नैतिक अपराध है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है, वह राज्य सरकार के संरक्षण में मतांतरण का खेल चल रहा है। जल्द बिल आने वाला है।

पीरखोह से बाहु फोर्ट तक गंडोला से करें मंदिरों के शहर का दीदार

जागरण संवाददाता, जम्मू

आखिरकार मंदिरों के शहर जम्मू की बहुप्रतीक्षित केबल कार परियोजना के पीरखोह से महामाया मंदिर के हिस्से को शुक्रवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केबल कार परियोजना के इस पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके पहले दूसरे चरण (महामाया मंदिर से बाहु फोर्ट तक) का पहले ही उद्घाटन हो चुका है। अब पर्यटक पीरखोह से बाहु फोर्ट तक गंडोला यानी केबल कार के सफर का आनंद उठा सकेंगे और यह सफर आठ मिनट में पूरा कराया जाएगा। इससे पर्यटकों को तवी नदी, मुबारक मंडी, हरि की पौढ़ी, सिदड़ा आदि इलाकों का विहंगम नजारा देखने को मिलेगा।



रोपवे का आनंद: पिरखो से महामाया तक शुरू हुई रोपवे सेवा का आनंद लेते पर्यटक। प्रेट्र

रामपुर के नवाब खानदान के सभी पक्षकारों को पांचों संपत्तियों में मिला हिस्सा

जासं, रामपुर : रामपुर के नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे के लिए जिला जज ने जो योजना बनाई है, उसमें सभी पक्षकारों को पांचों संपत्तियों में हिस्सा मिल रहा है। चल संपत्ति को उसकी कीमत के हिसाब से बांटा गया है। रामपुर में नवाब खानदान की 2,651 करोड़ की संपत्ति है। इसके बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है।

वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। जिला जज ने सभी पक्षकारों से आपसी सहमति से बंटवारे का प्रयास किया। इसके लिए स्पेशल जज को मध्यस्थ भी नियुक्त किया। लेकिन, पक्षकारों में सहमति नहीं बनी।

इसपर जिला जज ने गुरुवार को योजना पेश की। इस योजना के बारे में 15 दिन के अंदर आपत्ति मांगी गई हैं। पक्षकारों के वकीलों ने शुक्रवार को अदालत से योजना की प्रमाणित कापी लीं।

पटना के महावीर मंदिर पर हनुमानगढ़ी का दावा, मंदिर न्यास ने किया खारिज

जागरण संवाददाता, पटना

▶ हनुमानगढ़ी अयोध्या ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को पत्र लिखकर नियंत्रण का मांगा अधिकार

पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमानगढ़ी (अयोध्या) के साधुओं ने अपना दावा किया है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े साधुओं ने इसके लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को पत्र लिखा है। महावीर मंदिर न्यास पर्षद के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने दावा को खारिज करते हुए कहा कि महावीर मंदिर पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चलता है। अयोध्या में राम-रसोई का संचालन महावीर मंदिर की ओर से किया जा रहा है। महावीर मंदिर रामजन्म भूमि में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये की राशि का सहयोग दे रहा है। यह सब हनुमानगढ़ी के साधुओं को रास नहीं आ रहा है। साधुओं की मंडली महावीर मंदिर पर अपना फर्जी दावा पेश करने के लिए अयोध्या में अभियान चला रहे हैं।

हनुमानगढ़ी व पर्षद को उपलब्ध कराया गया दस्तावेज : आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास एवं बिहार राज्य धार्मिक पर्षद के अध्यक्ष एके जैन को महावीर मंदिर का इतिहास और कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। महावीर मंदिर में हनुमानगढ़ी के साधु पूजा-अर्चना करते रहे हैं। पुजारी उमा शंकर दास के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिलने के कारण उन्हें मंदिर के सेवा भाव से हटा दिया गया था। हनुमानगढ़ी से आए आठ साधु में सात एक ही परिवार से हैं। जिसमें कुछ पुजारी अभी सेवा भाव में लगे हैं। 1987 से 1996 तक महावीर मंदिर में कांची मठ के शैव पुजारी नारायण भट्ट, सूर्य नारायण भट्ट और रवींद्र भट्ट मंदिर के पुजारी रहे हैं।

किसी आदेश व दस्तावेज में हनुमानगढ़ी की चर्चा नहीं : महावीर मंदिर न्यास पर्षद का कहना है कि 15 अप्रैल, 1948 को पटना उच्च न्यायालय ने महावीर मंदिर को सार्वजनिक मंदिर घोषित किया था। न्यायालय के किसी आदेश में हनुमानगढ़ी की चर्चा नहीं है। 1935 से मंदिर का संचालन न्यास समिति की ओर से हो रहा है। 1956 में धार्मिक न्यास पर्षद और महावीर मंदिर न्यास समिति के बीच समझौता के अनुसार न्यास समिति जब तक मंदिर का आर्थिक विकास करते रहेगी न्यास पर्षद इसके संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1958 में पटना उच्च न्यायालय ने इस समझौते को स्वीकृति दी थी। आचार्य कुणाल ने बताया कि 1990 में धार्मिक न्यास पर्षद ने इसके सुचारू संचालन के लिए विस्तृत योजना बनाई। इसी के अनुरूप मंदिर का संचालन हो रहा है। योजना के विरुद्ध राम गोपाल दास ने पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। दोनों जगह उनकी हार हुई।

शीघ्र होगा मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता : डब्ल्यूटीओ

नई दिल्ली : डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते पर जल्द ही पहुंचने का संकल्प लिया है। समझौता होने के बाद वैश्विक मत्स्य उद्योग के लिए नए नियम बनेंगे और सरकारी सब्सिडी भी सीमित हो जाएगी। गुरुवार को इस संबंध में बैठक बुलाई गई थी और भारत की तरफ से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया था। (प्रेट्र)



सरकार के लिए यह समय साहस दिखाने का है। विकास को गति देने के लिए राजकोषीय घाटे की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए।

– केवी कामथ, पूर्व प्रमुख, न्यू डेवलपमेंट बैंक

सेंसेक्स	53,140.06	▼ 18.79
निफ्टी	15,923.40	▼ .80
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 47,319	▼ ₹73
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹68,043	▼ ₹196
डॉलर	₹74.57	▲ ₹0.03
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 73.11	

भारत निवेश के लिए आकर्षक बाजार : निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को विदेशी निवेश के बेहद आकर्षक बाजारों में एक बताया है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद (यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल) की एक बैठक में अमेरिकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार की दिशा में उठाए गए चौतरफा व्यापक कदम भारत को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बाजार बनाते हैं। इस बैठक में जनरल इलेक्ट्रिक, बैक्सटर हेल्थकेयर यूएसए, ब्रैंबल्स, मार्श एंड मैक्लेनान और पेप्सिको समेत अन्य कंपनियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। सीतारमण ने बताया कि भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय कारोबार 500 अरब डॉलर पर पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। हाल के महीनों में आर्थिक रिकवरी में जीवंतता दिखी है और वृहत आर्थिक मोर्चे पर स्थायित्व दिख रहा है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में कई सेक्टरों में निवेश के व्यापक मौके हैं।

सुधार कार्यक्रमों के दम पर वित्त वर्ष 2023 के बाद दिखेगा सात फीसद से अधिक विकास

तेज विकास में कोई बाधा नहीं : सीईए

मुंबई, प्रेट्र : देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 व उसके बाद देश की विकास दर सात फीसद तक पहुंच जाएगी। सरकार द्वारा किए गए सुधार और कोरोना टीकाकरण में तेजी इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसद की गिरावट आई है।

डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में सुब्रमणियन ने कहा कि सुधारों और टीकाकरण पर ध्यान देने के चलते मुझे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 तक विकास दर सात फीसद पर पहुंच जाएगी और वहां से तेजी पकड़ेगी। पिछले डेढ़ वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों का हवाला देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले एक दशक के दौरान विश्व में सबसे अधिक विकास दर भारत की होगी।



कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ● फाइल फोटो

वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही पर कोरोना की दूसरी लहर का थोड़ा-बहुत असर दिखाई देगा। सीईए ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दूसरी लहर का असर सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव सीमित है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर की अवधि बहुत कम रही है। वहीं, जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, वे राज्यों तक ही सीमित रहे। उन्होंने कहा कि देश को अगर महामारी से उबरना है तो टीकाकरण की गति को बनाए रखना होगा।

राज्य करें श्रम सुधारों की पहल : अमिताभ कांत

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश सरकारों को ना केवल श्रम सुधारों को शुरू करने की पहल करनी चाहिए, बल्कि उद्योगों के लिए बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को व्यापार के लिए सबसे अच्छे स्थान के तौर पर विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। उद्योग संगठन पीएचडीसीसीआइ द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांत ने तिलहन और खाद्य तेलों के चलते महंगाई दर में हुए इजाफे पर भी चिंता व्यक्त की। पीएचडीसीसीआइ ने उनके एक बयान के हवाले से कहा, 'अब हर स्तर पर काम करने



अमिताभ कांत ● फाइल फोटो

का समय आ गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, समयबद्ध मंजूरी और जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर प्रदेश सरकारों को ध्यान देना चाहिए।' उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक और निजी भागीदारी (पीपीपी) की व्यापक संभावना है। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस गठजोड़ की अत्यंत आवश्यकता है।

हरियाणा-पंजाब की डिस्काम सुधरीं, उप्र-बिहार की हालत जस की तस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश में पर्याप्त बिजली पैदा हो रही है और ट्रांसमिशन लाइनें भी काफी सुधार दी गई हैं। लेकिन जब तक राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक इसका फायदा आम जनता को मिलना मुश्किल है। खासतौर पर बिहार, उप्र, तमिलनाडु, मप्र, राजस्थान, असम और झारखंड की बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति खराब बनी हुई है। इससे इन राज्यों में लोगों को निर्बाध व सस्ती बिजली मिलने में परेशानी हो रही है। बिजली मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को राज्यों की डिस्काम की जारी नई रैंकिंग लिस्ट से यह पता चलता है। इस लिस्ट में गुजरात की बिजली वितरण कंपनियां लगातार नौवें वर्ष शीर्ष पर बनी हुई हैं।

वर्ष 2013 से जारी हो रही इस सालाना सूची से पता चलता है कि देश में बिजली चोरी रोकने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 41 डिस्काम में से 10 डिस्काम के क्षेत्र में बिजली की चोरी बढ़ी है।



लगातार नौवें वर्ष गुजरात की बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर ● फाइल

बिजली मंत्री आरके सिंह ने सूची जारी करते हुए कहा कि हाल ही में केंद्र ने बिजली सेक्टर के लिए तीन लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, जिसका फायदा उठाने के लिए डिस्काम को आगे आना चाहिए। अब उपभोक्ताओं का फायदा पहुंचाना ही सर्वोपरि है। महामारी के बाद बिजली की निर्बाध आपूर्ति एक चुनौती है जिसका केंद्र व राज्यों को मिलकर सामना करना है। जो डिस्काम जितनी तेजी से अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर बनेंगी उन्हें केंद्र से उतनी ज्यादा राहत मिलेगी। पैकेज के तहत जो कर्ज डिस्काम को दिया जाएगा, उसकी लागत भी वे ही तय करेंगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली डिस्काम को कम ब्याज देना पड़ेगा। उन्होंने रैंकिंग लिस्ट में खराब प्रदर्शन वाले डिस्काम से बड़े सुधार करने की अपील की।

शुक्रवार को जारी लिस्ट में शीर्ष 10 बेहतरीन डिस्काम में गुजरात की चार, हरियाणा की दो व पंजाब, मप्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक की एक-एक डिस्काम हैं। इनमें शीर्ष पांच में गुजरात के अलावा एक हरियाणा की हैं। इन्हें बिजली खरीद, बिजली चोरी रोकने तथा ज्यादा से ज्यादा मीटर लगाने में देश की सबसे बेहतरीन वितरण कंपनियों का दर्जा दिया गया है। रैंकिंग में 11 से 18 स्थान पर आने वालों में उत्तराखंड की यूपीसीएल 13वें और उप्र की पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम 18वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश की एचपीएसईबीएल 12वें स्थान पर है। इन सभी को 'बी प्लस' रैंकिंग दी गई है, यानी इनका प्रदर्शन औसत कहा जा सकता है। बिहार की नॉर्थ बिहार डिस्काम 21वें, साउथ बिहार डिस्काम 25वें, यूपी की केईएससीएल 22वें, पूर्वांचल विद्युत वितरण 27वें और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम 29वे स्थान पर है।

एक नजर में

पेट्रोल में 20 फीसद एथनाल मिलाने का लक्ष्य

नई दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 तक पेट्रोल में 20 फीसद एथनाल मिलाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैटरी प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि सरकार सहित विभिन्न कंपनियां इस पर भारी निवेश कर रही हैं। गोयल ने कहा कि गैस स्टेशनों पर चार्जिंग सुविधा की शुरुआत की जाएगी। (प्रेट्र)

डीबीटी में इस वर्ष अब तक 37 फीसद की बढ़ोतरी

मुंबई : यूआइडीएआइ के सीईओ सौरभ गर्ग ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) में इस साल अब तक 37 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह 3.9 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन के स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020 में इसका आंकड़ा 2.8 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन था। (प्रेट्र)

हवाई किराया महंगा होने के आसार, एटीएफ के दाम बढ़े

नई दिल्ली, आइएएनएस: आने वाले दिनों में हवाई सफर और महंगा होने के आसार हैं। आयल मार्केटिंग कंपनियों ने शुक्रवार को घरेलू एयरलाइंस के लिए विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमत 2.44 फीसद की बढ़ा दी है। इसकी कीमत पहली जुलाई को 68,262.35 रुपये प्रति किलोलीटर थी, जो 16 जुलाई को 69,857.97 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई। मुंबई में इसकी कीमत 66,482.90 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर 68,064.65 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है।

ईंधन की कीमत बढ़ने से विमानन कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ जाती है। विमान के परिचालन में सबसे अधिक खर्च (35-50 फीसद) ईंधन के तौर पर होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईंधन की कीमत बढ़ने से पहले से ही दिक्कतों से जूझ रहीं विमानन कंपनियों की

40 फीसद तक महंगा हो चुका है विमान ईंधन जनवरी से अब तक

बैलेंस शीट पर असर पड़ सकता है। जनवरी से अब तक एटीएफ में 40 फीसद तक बढ़ोतरी हो चुकी है। इस वर्ष की शुरुआत में एटीएफ की कीमत 50,000 रुपये प्रति किलोलीटर थी, जो अब लगभग 70,000 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। हालांकि विमानन कंपनियों के पास विदेश से भी एटीएफ खरीदने का विकल्प है, लेकिन सीमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के चलते यह बहुत लाभप्रद दिखाई नहीं पड़ता है। विमानन कंपनियों की दिक्कतें यहीं कम नहीं होती हैं।

माना जा रहा है कि अगर उन्होंने एटीएफ की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ यात्रियों पर डालने की कोशिश की तो लोग हवाई यात्रा से दूरी बना सकते हैं।

रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल को खरीदा

जाब्यू, नई दिल्ली : देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शाखा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने जस्ट डायल लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की है। कंपनी जस्ट डायल में फिलहाल 40.95 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 3,497 करोड़ रुपये निवेश करेगी। बाद में इसकी 26 फीसद हिस्सेदारी ओपन आफर के जरिये खरीदी जाएगी। वीएसएस मणि जस्ट डायल के एमडी व सीईओ बने रहेंगे। इस वर्ष 31 मार्च तक जस्ट डायल के डाटाबेस में 3.04 करोड़ लिस्टिंग थी। उस तिथि के हिसाब से 12.91 करोड़ यूजर्स जस्ट डायल प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे थे।

आरआरवीएल की निदेशक, ईशा अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल पहली पीढ़ी के उद्यमी वीएसएस मणि के साथ साझेदारी करने को लेकर उत्साहित है, जिन्होंने अपने व्यापारिक कौशल और दृढ़ता के बल पर मजबूत व्यवसाय खड़ा किया है।

पेटीएम लाएगी 16,600 करोड़ का आइपीओ

जागरण ब्यूरो नई दिल्ली : डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम जल्द 16,600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक पब्लिक आफर (आइपीओ) लाएगी। यह पूंजी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आइपीओ होगा। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसने पूंजी बाजार नियामक एजेंसी सेबी के पास आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन किया है।

कंपनी की योजना 8,300 करोड़ रुपये नये शेयरों के माध्यम से और इतनी ही रकम वर्तमान हिस्सेदारों की हिस्सेदारी बेचकर जुटाने की है। आइपीओ के बाद कंपनी में इसके प्रमुख प्रमोटर विजय शंकर शर्मा और चीन की अलीबाबा की कंपनी एंटफिन की होल्डिंग कम हो जाएगी। इन दोनों के अलावा समूह में दूसरे छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी भी घटेगी।

पेटीएम ने बाजार में उतरने की तैयारी तब की है जब भारतीय शेयर बाजार लगातार नए रिकार्ड बना रहा है और कई स्टार्ट-अप भी बाजार में उतर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी से अभी तक 22 कंपनियों के आइपीओ आ चुके हैं। जुलाई में भी 12 कंपनियों के शेयर जारी हो रहे हैं। माना जा रहा है कि 40 कंपनियां चालू वित्त वर्ष में भारतीय शेयर बाजार में आइपीओ लाने वाली हैं। इनकी संयुक्त रूप से 80,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी है।

जानकारों का मानना है कि पेटीएम आने वाले दिनों में सरकारी बैंकों की निजीकरण प्रक्रिया में भी भाग लेने की तैयारी में जुटी है। आइपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के लिए यह काम आसान होगा। हालांकि पेटीएम तेजी से विस्तार कर रही है और इसमें निवेश करने वालों की भी कमी नहीं है। इसके बावजूद पिछले तीन वर्षों से यह लगातार घाटे में है।

ये भी हैं मैदान में

- **जोमैटो** : इस आनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफार्म के तीन दिनों तक खुले आइपीओ का सब्सक्रिप्शन शुक्रवार को बंद हो गया। यूनीकार्न स्टार्ट-अप्स की सूची में यह पहला आइपीओ था। कंपनी के 5,178 करोड़ रुपये के आइपीओ को 38 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।



- **तत्व चिंतन** : यह स्पेशलिटी केमिकल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी 500 करोड़ रुपये का आइपीओ लाई है। शुक्रवार को पहले ही दिन इसे 4.51 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

जून में भारत का निर्यात 31.87% बढ़ा

नई दिल्ली, एएनआइ: जून 2021 में भारत का सकल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) बढ़कर 49.85 अरब डालर हो गया है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31.87 फीसद और जून, 2019 के मुकाबले 17.17 फीसद अधिक है। जून में आयात 52.18 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 73.65 फीसद और जून, 2019 की तुलना में 1.08 फीसद अधिक है।

इस वर्ष अप्रैल-जून तिमाही में सकल निर्यात 147.64 अरब डालर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 50.24% और जून, 2019 के मुकाबले 10.92% ज्यादा है। अप्रैल-जून तिमाही में कुल आयात 156.58 अरब डालर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की इसी समयावधि की तुलना में 80.75% ज्यादा है। हालांकि जून, 2019 की तुलना में इसमें 3.48 फीसद की कमी दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

नक्सलियों को हथियार आपूर्ति मामले में पांच गिरफ्तार

बालाघाट : नक्सलियों को आपूर्ति के लिए लाए गए हथियारों की बरामदगी के मामले में पुलिस ने गुरुवार को महाराष्ट्र के गोंदिया से एक पूर्व पार्षद छत्रसाल उर्फ बंटी बानेवार, जिलेटिन छड़ें उपलब्ध कराने वाले राजेश पाटिल सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। (नईदुनिया)

हरिद्वार के बहादरपुर जट गांव में मिले आपत्तिजनक पर्चे

हरिद्वार : पथरी क्षेत्र के बहादरपुर जट गांव में आपत्तिजनक पर्चे मिलने का मामला सामने आया है। इन पर्चों में हिंदुओं को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया गया है। तनाव को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है। पूरे मामले के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ माना जा रहा है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। (जासं)

जम्मू-पुंछ हाईवे से मिला संदिग्ध बैग, यातायात रहा बंद

पुंछ : जम्मू संभाग के पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील और भींबर गली इलाके के बीच जम्मू-पुंछ हाईवे पर सेना के शिविर के नजदीक एक संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सुरक्षा को देखते हुए हाईवे पर यातायात बंद कर दिया गया। करीब तीन घंटे बाद यातायात बहाल हुआ। (संस)

शराब से चंपारण में दर्जनभर लोगों की मौत

बेतिया (प. चंपारण) : बिहार के बेतिया के लौरिया और रामनगर प्रखंड के देवराज के इलाके में पिछले दो दिनों में संदिग्ध परिस्थितियों में 16 लोगों की मौत के बाद सन्नाटा पसरा है। शुक्रवार को सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता वहां पहुंचे तो मृतकों के स्वजन ने बताया 13 जुलाई की शाम देउरवा गांव की एक दुकान पर शराब पीने से दर्जनभर लोगों की मौत हुई। (जासं)

अस्पताल की सीढ़ियों पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म

जयपुर : राजस्थान में करौली जिले के कुड़गांव में स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही के कारण एक महिला का प्रसव स्थानीय अस्पताल की सीढ़ियों पर ही हो गया। इस पर स्वजन ने हंगामा किया। (जासं)

शराब पीकर सो गया सहायक स्टेशन मास्टर, सवा घंटे खड़ी रहीं 10 ट्रेनें

सिस्टम पर सवाल

जागरण टीम, औरैया

दिल्ली-हावड़ा रेल रूट के कंचौसी रेलवे स्टेशन (औरैया, उप्र) पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर गुरुवार देर रात शराब पीकर सो गए। सिग्नल न मिलने के कारण स्टेशन के कानपुर व दिल्ली छोर पर 10 ट्रेनें एक घंटा 20 मिनट तक खड़ी रहीं। कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने पर स्टेशन अधीक्षक पहुंचे तो सहायक स्टेशन मास्टर कुर्सी पर सोता मिला। उन्होंने ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया, तब अफसरों ने राहत की सांस ली। इस बड़ी लापरवाही पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक प्रयागराज ने सहायक स्टेशन मास्टर को निलंबित कर चार्जशीट दी है।

कंचौसी रेलवे स्टेशन पर रात 12 से सुबह आठ बजे तक की शिफ्ट में सहायक स्टेशन मास्टर अनिरुद्ध कुमार की ड्यूटी थी। रात 12:40 बजे फफूंद व झींझक स्टेशन मास्टर ने परिचालन कंट्रोल रूम को बताया कि कंचौसी स्टेशन पर कोई

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक प्रयागराज एसके शुक्ल ने सहायक स्टेशन मास्टर को निलंबित किया है। उसका टूंडला रेलवे चिकित्सालय में मेडिकल कराया गया तो शराब पीने की पुष्टि हुई है।

-अमित कुमार सिंह, उत्तर-मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी।

तकनीकी दिक्कत है। इससे अप व डाउन में ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। तीन एक्सप्रेस व सात मालगाड़ियां ट्रैक पर रोकी गई हैं। इससे रेलवे अफसरों के होश उड़ गए और उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में खलबली मच गई। गुरुवार शाम की शिफ्ट करके घर पहुंचे स्टेशन अधीक्षक विशम्भर दयाल पांडेय को पूरा मामला बताया गया तो वह स्टेशन पहुंचे। कुर्सी पर सो रहे सहायक स्टेशन मास्टर के मुंह पर पानी डालकर जगाने की कोशिश की पर वह नहीं जागा। मुंह सूंघा तो शराब की बदबू आई। इस पर उन्होंने रुकी ट्रेनों को सिग्नल देकर गंतव्य की ओर रवाना किया। रात दो बजे तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो सका।

टी सीरीज के एमडी भूषण कुमार पर दुष्कर्म का आरोप

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई: टी सीरीज कंपनी के एमडी भूषण कुमार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। भूषण कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही कंपनी में काम दिलाने के नाम 30 साल की महिला का शोषण किया। यह मामला अंधेरी (वेस्ट) स्थित डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस ने भूषण कुमार के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 (यौन दुराचार), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।

दूसरी तरफ, टी सीरीज द्वारा जारी बयान में इन आरोपों को गलत बताया गया है। बयान के मुताबिक, महिला का साल 2017 से 2020 के बीच काम दिलाने के बहाने यौन शोषण करने का आरोप गलत है। वह पहले भी टी-सीरीज के बैनर तले फिल्म और म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी है। मार्च 2021 के आसपास उसने भूषण कुमार से एक वेब सीरीज का निर्माण करने के लिए मदद मांगी, जिसे वह प्रोड्यूस करना चाहती थी। अनुरोध नहीं मानने पर साथी के साथ मिलकर टी-सीरीज से बड़ी राशि मांगनी शुरू कर दी।

'राजनयिक माध्यम से तस्करी आतंकी कृत्य'

कोच्चि, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने केरल हाई कोर्ट में कहा है कि स्वप्ना सुरेश और अन्य ने नवंबर, 2019 से जून, 2020 के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से देश में 167 किलोग्राम सोने की तस्करी करके आतंकी कार्रवाई की है। वे जानते थे कि ऐसा करने से देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा होगा।

एनआइए ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि राजनयिक माध्यमों से सोने की तस्करी में शामिल स्वप्ना और अन्य इस बात से परिचित थे कि उनके कार्यों से यूएई के साथ भारत के रिश्तों को नुकसान होगा, इसलिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकी कृत्य, साजिश और आतंकी संगठन का हिस्सा बनने का अपराध बनाया गया है। एनआइए ने ये दलीलें स्वप्ना की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दीं। इस आदेश के खिलाफ स्वप्ना की याचिका पर जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जियाद रहमान एए की पीठ ने कहा कि स्वप्ना की याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई तक टाल रहे हैं।

वैक्सीन फेंकने वाली एएनएम को राहत नहीं

विधि संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक 29 डोज वैक्सीन लाभार्थियों को नहीं लगाकर दवा सहित सीरिंज फेंकने की आरोपित एएनएम निहा खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने याची के अधिवक्ता व सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया है। निहा खान के विरुद्ध थाना सिविल लाइन जिला अलीगढ़ में डा. दुर्गेश सिंह द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 203, 176, 465, 427, 120बी सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम 3/4 तथा महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप लगाया है कि कोविड पोर्टल वैक्सीनेशन के दौरान 29 डोज भरे सीरिंज कूड़ेदान में मिले थे।

गलत टाइपिंग से छूटा आरोपित, फैसला पलटा

चेन्नई, प्रेट्र: निचली अदालत में मामले की रिकार्डिंग के दौरान एक शब्द की टाइपिंग में जरा सी गलती से एक आरोपित छूट गया, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो सारा भेद खुल गया। मामला मद्रास हाई कोर्ट का है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट पाक्सो एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई कर रही थी। निचली अदालत में मामले की रिकार्डिंग के दौरान टाइपिस्ट ने गलती से जो शब्द टाइप किया उसका बचाव पक्ष ने फायदा उठाया और आरोपित छूट गया। उस शब्द का तमिल में अर्थ लाल मिट्टी होता है। आरोपित के छूटने से आहत बच्ची की मां ने निचली अदालत के फैसले को सितंबर 2018 में हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि कभी-कभी निचली अदालतें अपने विवेक और अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करतीं। वे जांच का पुनः आदेश दे सकती हैं और संबंधित रिकार्ड मंगा सकती हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ।

एक सप्ताह में प्रभावितों को लौटाए साठ लाख

राब्यू, शिमला : सेब बागवानों से धोखाधड़ी मामले में सीआइडी ने रिकवरी तेज कर दी है। एक सप्ताह के भीतर प्रभावितों के साठ लाख रुपये लौटाए हैं। अब तक रिकवरी का आंकड़ा 21 करोड़ तक पहुंच गया है। जिन शिकायतों में पूरा पैसा लौटा दिया है, इनमें आढ़तियों को सेब का कारोबार करने की अनुमति होगी। वे लाइसेंस लेकर आढ़त कर सकेंगे, लेकिन जिनमें मामले दर्ज हैं और रिकवरी पूरी नहीं की है, उनमें आरोपित आढ़ती कारोबार नहीं कर पाएंगे। वे दूसरे नाम से आढ़त न करें, इस पर नजर रखी जा रही है।

इन राज्यों के हैं आरोपित: सेब का पैसा डकारने वाले आढ़तियों का संबंध हिमाचल समेत महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल, बिहार, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश व हरियाणा से हैं। आरोप है कि इन्होंने हिमाचल में 2015 से पिछले वर्ष तक सेब तो खरीदा, लेकिन पैसे डकार गए। गड़बड़झाले में सीआइडी के पास रिकार्ड 109 एफआइआर दर्ज हैं। हजारों शिकायतें आईं।

राजस्थान में एसडीएम ने किसान को मारी लात, वीडियो वायरल



किसान को लात मारते एसडीएम भूपेंद्र यादव। इंटरनेट मीडिया

किसानों ने काम रुकवा दिया था। उनको जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर लाठी से हमला करने का प्रयास किया। ऐसे में अपने बचाव में मुझे भी लात चलानी पड़ी।

भूपेंद्र यादव, एसडीएम, सांचौर

संवाद सूत्र, जोधपुर

राजस्थान में जालौर जिले में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों को रोकते समय हाथापाई में एसडीएम ने एक किसान को लात मार दी। इससे जुड़ा वीडियो वायरल हुआ तो एसडीएम ने कहा कि वह तो उग्र किसानों से बचाव की कोशिश कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार सांचौर क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत होने जा रहे निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने गांव की सरहद पर ही कार्य को रुकवा दिया। मुआवजे को लेकर भी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने उचित मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान हुई हाथापाई में एसडीएम भूपेंद्र यादव ने एक किसान को लात मार दी। उधर, किसानों के खिलाफ राज कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया गया है।

कश्मीर के दो पूर्व डिवीजनल कमिश्नर के आवास सहित नौ जगह मारे छापे

जागरण संवाददाता, जम्मू : पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त घोटाला मामले में शुक्रवार को सीबीआइ ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआइ ने कश्मीर के दो पूर्व डिवीजनल कमिश्नर, श्रीनगर के दो पूर्व डिप्टी कमिश्नर, पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर (नजूल), श्रीनगर के पूर्व तहसीलदार (नजूल) के अलावा जमीन खरीदने वालों के जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली में नौ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आरोप है कि इन पूर्व नौकरशाहों ने गुलमर्ग में जमीन को कौड़ियों के दाम पर बेच दिया। सीबीआइ के अनुसार, अभी मामले की जांच की जा रही है। छापे के दौरान जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली स्थित ठिकानों से चल अचल संपत्ति के दस्तावेजों, 25 लाख रुपये से भी अधिक के फिक्स डिपाजिट, दो लाख कैश, छह बैंकों के लाकर व बैंक खातों का ब्योरा भी मिला है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच जारी है।

सपा के जुलूस में देश विरोधी नारे लगाने पर पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा

आगरा में समाजवादी पार्टी के जुलूस में देश विरोधी नारे लगने का वीडियो वायरल होने पर गुरुवार शाम पुलिस हरकत में आ गई। जांच के बाद देर रात गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पांच नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से सभी जमानत पर रिहा हो गए। रिपोर्ट में 20-25 अज्ञात आरोपित हैं।

एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर सपा के जुलूस के वायरल वीडियो की जांच की गई। देर रात नाई की मंडी थाने में दारोगा विकास राणा की ओर से नारेबाजी करने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पांचों नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में न्यायिक रिमांड स्वीकृत होने के बाद आरोपित पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दी गई। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

पाकिस्तान से हमारे देश के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसमें नारेबाजी करने वाले की नीयत को देखकर आइपीसी की धारा 153 बी की तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

-डा. हरिदत्त शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता।

शत्रु राष्ट्र का सार्वजनिक रूप से गुणगान करना अपराध की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी भी अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 153 बी और आइपीसी की धारा 505 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। -दुर्ग विजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

सपा ने झाड़ा पल्ला : जुलूस में देश विरोधी नारा लगाने वाले युवकों से सपा ने पल्ला झाड़ लिया है। महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार का कहना है कि उक्त युवक सपा कार्यकर्ता नहीं हैं।

दैनिक जागरण

प्रकृति सबसे बड़ी रचयिता है

तालिबान के शिकंजे में अफगानिस्तान



विवेक काटजू

जब तक अफगान सरकार और तालिबान के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं तलाशा जाता तब तक वहां हिंसा और संघर्ष का दौर चलता ही रहेगा

अफगानिस्तान में जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं। हाल में तालिबान ने देश के कई इलाकों पर अपना शिकंजा और कसा है। उत्तर पूर्व, उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में उसकी पैठ और मजबूत हुई है। अफगान सरकार भले ही यह दावा करे कि सुरक्षा स्थिति अभी भी उसके नियंत्रण में है, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। कंधार की सुरक्षा स्थिति भी खराब है। इसे देखते हुए भारत ने वहां स्थित अपने वाणिज्य दूतावास के भारतीय कर्मियों को गत सप्ताह वापस बुलाने का फैसला किया। यह बिल्कुल सही था, क्योंकि इन कर्मियों को खतरे में नहीं झोंका जा सकता था। गत वर्ष भी भारत ने जलालाबाद और हेरात स्थित अपने वाणिज्य दूतावास बंद किए थे। उसके पीछे आधिकारिक वजह कोरोना महामारी को बताया गया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार को आभास हुआ कि ये दोनों अफगान शहर भारतीय स्टाफ के लिए असुरक्षित हो गए हैं। इन वाणिज्य दूतावास बंद करने से जहां भारतीय हितों को आघात पहुंचा वहीं पाकिस्तान को संतुष्टि मिली। पाकिस्तान ने हमेशा ये मिथ्या आरोप लगाए हैं कि अफगान स्थित इन प्रतिनिधि कार्यालयों का उपयोग भारत उसके लिए समस्याएं उत्पन्न करने में करता रहा है।

फिलहाल तालिबान अमेरिकी सेनाओं की वापसी का फायदा उठा रहा है। इससे अफगानिस्तान में अनिश्चितता बढ़ गई है। इससे कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। एक तो यही कि क्या तालिबान की मौजूदा सैन्य कार्रवाई के पीछे यह वजह है कि वह अपनी स्थिति मजबूत करके अफगान सरकार से वार्ता करेगा या फिर उसने वार्ता की राह पूरी तरह छोड़ दी है और ताकत से सत्ता हथियाना चाहता है? हमारे पास अभी तक इसका जवाब नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर तालिबान सत्ता साझेदारी के आधार पर अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने पर सहमत हुआ तो वह रक्षा क्षेत्र और खुफिया एजेंसियों पर नियंत्रण की मांग करेगा। शायद अफगान सरकार इस पर राजी न हो। जो भी हो, जब तक अफगान सरकार और तालिबान के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं तलाशा जाता तब तक हिंसा और संघर्ष का दौर चलता रहेगा। इस बीच 14 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की ताजिकिस्तान में बैठक हुई। वहां अफगानिस्तान की हालत ही मुख्य मुद्दा रहा। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अन्य सदस्य देशों चीन, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। अफगान विदेश मंत्री ने भी इसमें भाग लिया। जयशंकर ने हिंसा की समाप्ति और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। तालिबान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अगर सत्ता ताकत से हासिल की जाएगी तो उसे मान्यता नहीं मिल पाएगी। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि अफगान जनता के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उसके पड़ोसी देशों को अफगान धरती से उपजे आतंकवाद से पीड़ित न होना पड़े।

इस दौरान एससीओ विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान पर एक संयुक्त बयान भी जारी किया। इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरना चाहिए, जो हिंसा, चरमपंथ और अवैध अफीम की पैदावार से मुक्त हो। बयान में यह भी उल्लेख था कि अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों की गतिविधियां अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह हैं। एससीओ विदेश मंत्रियों ने सभी अफगान पक्षों से यह आह्वान भी किया कि वे बल प्रयोग न करें। संयुक्त बयान के अनुसार अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता के जरिये ही वहां शांति संभव है। इस सबके बीच पाकिस्तान का यही दावा है कि वह इस पक्ष में है कि अफगान लोग अपने भविष्य का फैसला खुद करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। तालिबान की मदद कर रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार है। तालिबान की सहायता करके पाकिस्तान ने उसे यह अवसर दिया कि वह सैन्य सफलता प्राप्त करे। ऐसे में जयशंकर ने उचित ही कहा कि कुछ ऐसी ताकतें भी सक्रिय हैं, जिनका अलग ही एजेंडा है। इससे यही ध्वनित हुआ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं चाहता।



अवधेश राजपूत

सामरिक मोर्चे सहित अफगानिस्तान में भारत के व्यापक हित जुड़े हुए हैं। उसने अफगान सरकार और वहां की राजनीतिक बिरादरी के विभिन्न वर्गों से बेहतरीन संबंध बनाए हैं। काबुल की संस्थाओं का भारत के प्रति बहुत सम्मान भाव है। पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर यह जानते हुए भी कदम बढ़ाए थे कि इससे पाकिस्तान कुपित होगा। अफगानिस्तान को मदद पहुंचाकर भारत अफगान जनता में भी लोकप्रिय हुआ। इस सबके बावजूद जमीनी स्तर पर मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान की मौजूदा स्थिति यकायक मजबूत नहीं हुई है।

जब स्थिति राष्ट्रहित के विपरीत बन रही हो तो सफल कूटनीति के लिए जरूरी हो जाता है कि वह मौके की नजाकत को समझे और उसी हिसाब से कदम उठाए। बीते कई वर्षों से स्पष्ट हो रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में रणनीतिक हार स्वीकार कर वहां से निकल जाएगा। इसी कारण उसने पाकिस्तान सीमा तक युद्ध का विस्तार नहीं किया। ऐसा किए बिना तालिबान को हराया नहीं जा सकता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि अमेरिका और तालिबान में वार्ता होगी, जिससे इस समूह को एक किस्म की अंतरराष्ट्रीय वैधता मिल जाएगी। यही वास्तव में हुआ भी। जहां कई देशों ने तालिबान से सीधे संपर्क साधा, लेकिन भारत ने नहीं किया, पर वह अतीत की बात है। अब भारत के हित में यही है कि वह वास्तविकता को स्वीकार करते हुए तालिबान से वार्ता करे, भले ही उसकी कड़ियां पाकिस्तान से क्यों न जुड़ी हों। ऐसा करके भारत तालिबान की कट्टरपंथी सोच पर मुहर नहीं लगाएगा। वास्तव में ऐसे संवाद से वह उसे यह बता सकता है कि दुनिया मध्यकालीन विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगी। कूटनीति तो उन लोगों से भी संपर्क की मांग करती है, जिनके विचार हमारे राष्ट्रीय सिद्धांतों के एकदम खिलाफ होते हैं। समय की यही मांग है कि राष्ट्रीय हितों के लिए दुश्मन देश के दोस्त से भी बात की जाए।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे हैं)

response@jagran.com

राहुल गांधी का निशाना

राहुल गांधी ने यह कहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद सरीखे नेताओं पर ही निशाना साधा कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। इसका मतलब है कि वह उन कारणों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं, जिनके चलते इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस का परित्याग किया? राहुल गांधी कुछ भी दावा करें, सच यही है कि वही नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं जिन्हें न तो अपना और न ही पार्टी का कोई सुखद भविष्य दिख रहा है। राहुल गांधी के बयान से यह भी साफ है कि वह उन कारणों को भी समझने को तैयार नहीं, जिनके चलते कांग्रेस लगातार दो आम चुनाव बुरी तरह हारी और हाल के विधानसभा चुनावों में भी कुछ खास नहीं कर पाई। बंगाल में उसे एक भी सीट नहीं मिली और केरल में इस बार उसके नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक मोर्चे की बारी होते हुए भी वाम मोर्चा फिर से सत्ता में आ गया। राहुल गांधी के बयान से यह भी लगता है कि वह उन नेताओं को भी कोई सख्त संदेश देना चाहते हैं जो पार्टी संचालन के तौर-तरीकों से सहमत नहीं और जिन्हें जी-23 समूह का सदस्य माना जाता है। यदि राहुल गांधी इस समूह के नेताओं को आरएसएस की विचारधारा पर यकीन करने वाला अथवा डरपोक करार देना चाहते हैं तो इसका यह भी मतलब है कि वह कांग्रेस में कोई सुधार या बदलाव लाने के बजाय उसे वैसे ही चलाना चाहते हैं, जैसे बीते लगभग दो साल से चला रहे हैं। उन्होंने दो साल पहले आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन तबसे वह बिना कोई जिम्मेदारी लिए पार्टी को पिछले दरवाजे से संचालित कर रहे हैं। क्या वह इस व्यवस्था से असहमत लोगों को आरएसएस का आदमी करार देंगे? उनकी मर्जी, लेकिन उन्हें इससे अवगत होना चाहिए कि कथित तौर पर आरएसएस-भाजपा से न डरने वालों के लिए कांग्रेस कोई आदर्श विकल्प नहीं रह गई है।

यह एक तथ्य है कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस की जमीन पर काबिज हो रहे हैं। कहीं-कहीं तो भाजपा भी कांग्रेस को उसकी जमीन से बेदखल कर रही है। आज राहुल गांधी को भले ही भाजपा-आरएसएस से न डरने वाले नेता चाहिए हों, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक समय वह इन दोनों संगठनों के डर से ही मंदिर-मंदिर जा रहे थे और खुद को जनेऊधारी बताने के साथ अपने गोत्र की जानकारी भी दे रहे थे। राहुल गांधी ने भाजपा-आरएसएस से निडर रहने को अपनी विचारधारा बताया, लेकिन सच तो यह है कि किसी को नहीं पता कि आज कांग्रेस वस्तुतः किस विचार पर चल रही है।

सरकार के समक्ष चुनौती

पंजाब के लिए राहत की बात यह है कि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब डेढ़ हजार से नीचे आ गई है। इसके बावजूद अभी पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य में मृत्यु दर अब भी 2.7 फीसद है। यह राष्ट्रीय दर 1.32 फीसद से दोगुनी अधिक है। लंबे समय से मृत्यु दर का कम न होना चिंतित करने वाली बात है। प्रदेश सरकार की ओर से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने और सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट इत्यादि खोलने की इजाजत देने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ उमड़ रही है। आए दिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ ही मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के लिए एक और चिंता की बात है टीकाकरण की गति अपेक्षा के अनुरूप न होना। वीरवार तक मात्र 84 लाख 61 हजार लोगों को ही टीका लग सका है। प्रदेश की करीब पौने तीन करोड़ की आबादी को देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाना बहुत जरूरी है। 18 साल से कम उम्र वालों को यदि छोड़ भी दिया जाए तो करीब दो करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है। मृत्यु दर और टीकाकरण की सुस्त रफ्तार को लेकर विपक्षी दल भी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे अंतर्कलह का असर कोरोना से निपटने की मुहिम पर पड़ना स्वाभाविक है। आशंका के मुताबिक यदि प्रदेश में तीसरी लहर आ जाती है तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वैक्सीन के अभाव में कई टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसे देखते हुए बेहतर यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को यथाशीघ्र टीका लगाया जाए। जब प्रदेश सरकार को पूरी तरह कोरोना से प्रभावी तरीके से निपटने पर ध्यान देना चाहिए तब कैबिनेट मंत्रियों के बीच चल रही खेमेबाजी किसी भी तरह पंजाब के हित में नहीं है।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बेहतर यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को यथाशीघ्र टीका लगाया जाए

विमर्श से बाहर होता आम आदमी



क्षमा शर्मा

आम आदमी तमाम मुश्किलों से त्रस्त है, पर खांचे ऐसे बन गए हैं कि साधनहीनता भी स्त्री-पुरुषों में बंट गई है

हवा में चुनावों की चर्चा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर। इसके बाद कुछ और राज्यों के चुनाव। जैसे ही चुनाव आते हैं, विभिन्न जातियों, धर्मों और उनसे जुड़े दल अपने-अपने घोषणापत्र लेकर हाजिर हो जाते हैं। नए समीकरण बनने लगते हैं। आज तक जो विरोधी था, वह दोस्त हो जाता है और दोस्त पानी पी-पीकर कोसने लगता है। यही हाल दूसरे समूहों का होता है। कोई महिलाओं के नाम पर, कोई ट्रांसजेंडर तो कोई पर्यावरण के नाम पर अपनी-अपनी मांगें उठाने लगता है। पिछले कुछ दशकों में जैसे-जैसे महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है और वे वोट का गुणा-भाग करने लगी हैं, वैसे-वैसे हर दल उनका हितैषी दिखने की कोशिश करने लगे हैं। अपने-अपने दलों के घोषणा पत्रों में उन्हें विशेष जगह दी जाने लगी है। आधी आबादी की निर्णयकारी क्षमता से दल घबराने लगे हैं। वे उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते दिखते हैं, लेकिन जब एक वर्ग, समूह को आप अपनी तरफ खींचते हैं तो अक्सर दूसरे समूह पीछे रह जाते हैं और वे अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि विमर्श से, बहसों से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। समझा यह जाता है कि ये समूह कहां जाएंगे। हमें ही वोट देंगे, लेकिन यह सच नहीं है।

जब सरकारें किसी एक तरफ ध्यान देती हैं तो दूसरी तरफ इसकी प्रतिक्रिया होती दिखाई देती है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में ये प्रतिक्रियाएं धीमी हों और उनकी आवाजों को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन चुनावी गणित में हाशिये की ये आवाजें अपने करतब दिखा देती हैं। आप सोचेंगे कि आखिर इन दिनों कौन सी वे आवाजें हैं, जिन्हें हाशिये की आवाजें कहा जा रहा है। ये आवाजें हैं-पुरुषों की। बहुत से लोग यह पढ़कर नाक-भौं सिकोड़ सकते हैं। इस लेखिका को स्त्री विरोधी होने का तमगा भी दे सकते हैं, लेकिन डरकर सच बात कहने से अगर रुक जाएं तो फिर लिखना, सोचना, समझना सब व्यर्थ है। कितने दशक हुए जबसे आपने यह सुना कि सरकार गरीब पुरुषों के लिए भी कोई योजना बना रही है? उनकी पढ़ाई, लिखाई, रोजगार, चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है? कह सकते हैं कि आखिर पुरुषों को इस तरह की योजनाओं की क्या जरूरत? वे तो पहले ही हर निर्णयकारी जगह पर बैठे हैं यानी यह मान लें कि पुरुष न तो गरीब होते हैं, न साधनहीन, न उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है, न ही वे बेरोजगार होते हैं और न ही उनके मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है। परिदृश्य में हम देखते हैं कि पुरुषों की छवि इन दिनों किसी ऐसे खलनायक की बना दी गई है, जिसके जीवन में कोई दुख ही नहीं। जिस किसान-मजदूर की चिंता में हम दुबले हुए जाते हैं, जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता में हाहाकार करते हैं, क्या वे पुरुष नहीं हैं? इस पर गौर करें कि गरीब और साधनहीन पुरुष किसी विमर्श का हिस्सा नहीं हैं। वे मात्र पिटने और नफरत करने लायक हैं। सारे पुरुष या मर्द होते ही ऐसे हैं का मुहावरा इस कदर चल पड़ा है कि हमें वर्गों की खाई दिखाई देना बंद हो गई है। वे तो पैदा ही इसलिए होते हैं कि दूसरों को सता सकें, लेकिन क्या बिल गेट्स और उनका ड्राइवर पुरुष होते हुए भी एक जैसे होंगे। किसी दफ्तर का सबसे बड़ा अधिकारी और चाय-पानी पिलाने वाले लड़के की समस्याएं एक तरह की हो सकती हैं।



फिक्र नही हाशिये के लोगों की। फाइल

दरअसल इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं, उनकी समस्याएं कैसी हैं, कितनी तरह की हैं, वे ही बता सकते हैं। किसी की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती, लेकिन पिछले पांच दशक से अधिक समय में अपने देश में पुरुषों की छवि ऐसी बना दी गई है, मानो बस वे ही हैं, जिनके कारण यह धरती नर्क बनी हुई है। वे न होते, तो सब ठीक होता। जबकि हमें मालूम है कि इस धरती को हर तरह से जिन्होंने दुहा है, जिनका भगवान ही उनका मुनाफा है, वे इस तरह की बातों और सोच से साफ बच जाते हैं। असली खलनायकों को अक्सर भुला दिया जाता है।

कई दशक पहले मेरे यहां गैस का सिलेंडर देने एक युवा आता था। एमए-एमएड था, मगर कहीं नौकरी नहीं मिली। उसकी सबसे बड़ी समस्या ढंग के रोजगार की थी, क्योंकि वह घर में अकेला कमाने वाला था। उसका कहना था कि उस जैसे लोगों की कोई नहीं सुनता, क्योंकि वह गरीब है। सारे पुरुषों को खदेड़कर हम क्या करना चाहते हैं? ध्यान रहे कि जिन समाजों में स्त्रियां खुद मुख्तार हैं, वहां भी सारी समस्याएं हल नहीं हो गई हैं। लोग कहते हैं कि पुरुषों की आलोचना का मतलब उनके बदलने से है। सवाल यह है कि जब हम अपने अनुसार दूसरे के बदलाव की मांग करते हैं तो क्या कभी यह सोचते हैं कि क्या हम दूसरों के हिसाब से वैसे ही बदल सकते हैं, जैसी मांग दूसरों से कर रहे हैं?

अपने देश में साधारण आदमी तरह-तरह की मुश्किलों से परेशान है, मगर खांचों का बंटवारा इन दिनों ऐसा कर दिया गया है कि गरीबी और साधनहीनता भी स्त्री-पुरुषों में बांट दी गई है। कोरोना काल में जिन लाखों को हमने अपने-अपने घरों की तरफ दौड़ते देखा, परेशान और बेहाल देखा उनमें स्त्री-पुरुष दोनों थे, मगर वे गरीब और साधनहीन ही थे, जो विपत्ति से बचने के लिए अपने घर, गांव की ओर भाग रहे थे। सच तो यह है कि गरीब की कोई जाति, धर्म, लिंग नहीं होता। गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर गरीबी न हो, तो बाकी की समस्याएं भी हल हो जाएं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

लक्ष्य की प्राप्ति

स्वामी विवेकानंद अमेरिका के प्रवास पर थे। वहां भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि एक पुल के पास कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी का निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देखकर स्वामीजी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया। निशाना एकदम सटीक लगा। उसके बाद स्वामीजी ने एक के बाद एक बारह निशाने लगाए। सभी एकदम सही लक्ष्य पर लगे। लड़कों ने उत्सुकतावश पूछा, 'आपने यह कैसे किया?' स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यह सब ध्यान की शक्ति से संभव हुआ है। उन्होंने लड़कों को सीख दी कि हमेशा एकाग्रचित्त होकर केवल लक्ष्य पर ध्यान दो, तभी लक्ष्यभेद संभव है।

प्रत्येक मनुष्य के जीवन का प्रायः एक निश्चित लक्ष्य होता है। फिर भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे मनुष्य उस गेंदबाज की तरह होते हैं, जो गेंद तो लगातार फेंकते रहते हैं, लेकिन वह कभी लक्ष्य यानी विकेट पर नहीं लगती। वास्तव में लक्ष्य से विहीन होना उस बिना पता लिखे उस लिफाफे के समान है, जो कभी भी, कहीं भी नही पहुंच पाता। इसीलिए यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तो परिणाम विपरीत होता है। इसीलिए सर्वप्रथम आपको अपना लक्ष्य चुनकर उसे पाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में असफलताओं का आप पर कोई नकारात्मक असर भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने में कितना समय लग रहा है, उससे विचलित होने की भी आवश्यकता नहीं। स्मरण रहे कि अच्छा भोजन भी वही होता है, जो धीमी आंच पर देर तक पके। इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास जितना प्रभावी होगा परिणाम उतना ही आपकी अपेक्षा के अनुरूप होगा। ऐसे में लक्ष्य को जितनी शीघ्रता से तय कर लिया जाए उतना ही बेहतर, क्योंकि इससे उसकी प्राप्ति के प्रयास भी उतनी ही शीघ्रता से शुरू हो पाएंगे।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

एक अद्भुत संसार के रचनाकार

योगेश कुमार गोयल

वाल्ट डिज्नी की सफलता की गाथा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक है, जो थोड़ी असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं

आज डिज्नीलैंड किसी परिचय का मोहताज नहीं। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के एनाहिम स्थित डिज्नीलैंड ऐसा मनोरंजन और थीम पार्क है, जो मौज मस्ती के लिए किसी का भी स्वप्निल ठिकाना हो सकता है। डिज्नीलैंड की स्थापना 17 जुलाई 1955 को हुई थी। उस दिन टीवी प्रसारण के साथ डिज्नीलैंड का पूर्वावलोकन किया गया था। अगले दिन 18 जुलाई को उसे आम लोगों के लिए खोला गया। एक डॉलर मूल्य का इसका सबसे पहला टिकट उसके संस्थापक वाल्ट डिज्नी के भाई ने ही खरीदा था।

वाल्ट डिज्नी चाहते थे कि वह एक ऐसे थीम पार्क का निर्माण करें, जहां अभिभावक और बच्चे दोनों ही एक साथ आनंद ले सकें। डिज्नीलैंड के रूप में उन्होंने अपने इसी विचार को मूर्त रूप दिया। यह वर्ष 1940 के आसपास की बात है। एक दिन रविवार को वाल्ट डिज्नी अपनी दोनों बेटियों डियान और भोरान के साथ ग्रिफिथ पार्क में घूमने गए थे। वहां दूसरे बच्चे तो मस्ती कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटियों को वह पार्क अच्छा नहीं लगा। तब वाल्ट डिज्नी के मन में विचार आया कि क्यों न ऐसी जगह विकसित की जाए, जहां बच्चों को कोई शिकायत न रहे। फिर वाल्ट डिज्नी अपनी इस कल्पना को साकार करने में जुट गए।

यह बिल्कुल आसान नहीं था। कहा जाता है कि डिज्नीलैंड की स्थापना के प्रयास में वह करीब 300 बार असफल हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अथक परिश्रम के बाद आखिरकार डिज्नीलैंड के रूप में उनका सपना साकार हुआ। असफलताओं से जूझते-जूझते सफलता के इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने की उनकी यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो एक-दो बार असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं।

वाल्ट डिज्नी जब 19 साल के थे तो उन्होंने एक दोस्त के साथ एक कामर्शियल आर्टिस्ट कंपनी की नींव रखी। उस समय वह कई अखबारों और प्रकाशकों के लिए कार्टून बनाया करते थे। 16 अक्तूबर 1923 को उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो की नींव रखी। थोड़े ही समय में डिज्नी के कार्टून्स की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग चिट्ठियां लिख-लिखकर उनके स्टूडियो में आने की इच्छा जताने लगे। चूंकि उनका स्टूडियो छोटा था इसीलिए उन्होंने ऐसा थीम पार्क बनाने के अपने विचार को मूर्त रूप देने का निश्चय किया, जहां लोग दिनभर परिवार के साथ खूब मस्ती कर सकें।

पहले इस पार्क को स्टूडियो के पास ही तीन एकड़ जगह पर बनाए जाने पर विचार हुआ, किंतु बाद में इसे एनाहिम में 65 एकड़ के विशाल भूखंड में बनाया गया। डिज्नीलैंड की स्थापना के बाद वाल्ट डिज्नी दुनियाभर के मनोरंजन पार्कों में घूम-घूमकर देखते रहे कि वहां लोगों की दिलचस्पी किन-किन चीजों में है। उसी के आधार पर डिज्नीलैंड में भी वह उन चीजों का समावेश करते रहे, जो लोगों को ज्यादा आकर्षित करती थीं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

लागू हो समान नागरिक संहिता

'सबके हित में समान नागरिक संहिता' लेख में प्रो. हरबंश दीक्षित ने भारतीय समाज में समरसता और एकजुटता की भावना को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 44 को लागू करने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट और देश के कई ख्यातिप्राप्त बुद्धिजीवियों ने भी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। आधुनिक हाईटेक दौर में सरकार को पंथ, मत, क्षेत्र आदि का बंटवारा करने वाले आधार की परवाह किए बगैर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने विवाह और भरण-पोषण को किसी पंथ से न जोड़कर इसको मानवता से जोड़ा था। समान नागरिक संहिता लागू न होने से इसका दुरुपयोग कानून को धोखा देने के लिए हो रहा है। वैवाहिक संबंधों को खत्म करने के लिए लोग अपना मजहब बदलकर दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरे मजहब से जुड़े कानून में दूसरी शादी का प्रविधान और मान्यता दी गई है। एक प्रगतिशील समाज के लिए केंद्र सरकार को देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। जब सरकार एक देश, एक विधान सारे देश में लागू करने का साहसिक फैसला कर सकती है तो देश में सभी के लिए समान नागरिक संहिता वाले अनुच्छेद 44 को लागू करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। कुछ विपक्षी दल और संगठन सरकार का विरोध करेंगे। सरकार को तुष्टीकरण जैसी नीति को ताक पर रखकर देशहित में सख्त फैसला लेकर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। यह कदम संविधान निर्माताओं की आकांक्षा पूर्ति भी करेगा।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उन्नाव (उत्तर प्रदेश)

मेलबाक्स

साझा प्रवेश परीक्षा का उम्दा विचार

केंद्रीय विश्वविद्यालयों की एकल प्रवेश परीक्षा पर प्रो. निरंजन कुमार का आलेख पढ़ा। लेख वर्तमान समय में सीयूसीईटी की जरूरत तथा महत्व को बेहद गंभीर तथा तार्किक ढंग से रेखांकित करता है। लॉ, मेडिकल, इंजीनियर आदि कोर्स के लिए बीते कुछ वर्षों में शुरू हुए कामन एंट्रेंस टेस्ट की आशातीत सफलता तथा छात्रों की इससे मुश्किलें कम होने से जेईई, कैट, नीट आदि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का महत्व निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया है। करीब एक दशक पूर्व तक दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध अलग-अलग कालेजों में प्रवेश के लिए अलग-अलग आवेदन करने की जरूरत होती थी, लेकिन अब इसे केवल विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु आवेदन करने की व्यवस्था में बदल दिया गया है। हालांकि कई राज्यों के विश्वविद्यालयों में अभी भी एक ही विश्वविद्यालय से संबद्ध अलग-अलग कालेजों के लिए अलग-अलग आवेदन करना पड़ता है। यह व्यवस्था छात्रों तथा अभिभावकों के लिए दुरूह, अवसरों को कम करने वाली और खर्चीली है। ऐसे में केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों को एक प्लेटफार्म पर लाकर बीए, बीएससी, बीकाम, डिप्लोमा कोर्सेज आदि के लिए एक मानक केंद्रीकृत आवेदन व्यवस्था तथा उसी पर आधारित प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था शुरू करने की जरूरत है। इससे छात्रों की अनावश्यक भागदौड़ कम हो सकेगी। साथ ही आवेदन, परिवहन आदि में खर्च भी कम होगा। यह व्यवस्था इसी सत्र से लागू की जानी चाहिए। इससे छात्रों को लाभ मिलेगा।

आशुतोष सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय

नीतिगत मोर्चे पर परिवर्तन

मोदी सरकार का मंत्रिमंडल में फेरबदल निश्चित ही कुछ बड़े सुधार की आशा के साथ उठाया गया कदम लगता है। निश्चित ही यह कोरोना महामारी में चली राष्ट्रव्यापी तालाबंदी से अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है, उसे सुधारने, सत्ता विरोधी लहर पर काबू पाने, आगामी चुनावों में मजबूत पकड़ बनाने और 2024 के लोकसभा चुनाव में सरलता से जीत हासिल करने की सोच भी है। यदि मोदी सरकार कुछ और जनवादी नीतियों के जरिये जनता को कुछ और अच्छी राहत देती है तो निश्चित ही वह इस चुनौतीपूर्ण कार्य में भी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकती है। इसके लिए उसे तुरंत जनसंख्या पर ठोस नियंत्रण करना होगा। साथ ही निजीकरण से परहेज करते हुए राष्ट्रीयकरण की नीति पर पारदर्शी तरीके से जल्द वापस लौटना होगा।

वेद मामूरपुर, नरेला

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

33 करोड़ थी भारत की आबादी वर्ष 1930 में, जबकि आज यह बढ़कर 135 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यानी केवल नौ दशकों के दौरान इसमें चार गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

आजकल



निरंकार सिंह
स्वतंत्र पत्रकार

जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार पर लगे लगाम

बढ़ती आबादी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। यदि हमने इसे नियंत्रित कर लिया तो हमारी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। हमारी आबादी इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि हम कितनी भी प्रगति करें, कितना भी संपत्ति निर्माण करें, उसका खास सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि हम जितने संसाधन सृजित करते हैं उससे कई गुना अधिक उनका उपभोग करने वाले पैदा हो जाते हैं। इससे हमारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। लिहाजा जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगानी ही होगी



बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे संसाधनों पर भार बढ़ने के साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। फाइल

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को जारी कर दिया है। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फार्मूला तैयार किया गया है। राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ी सिफारिशों की वकालत की गई है। माना जा रहा है कि इसे सख्ती से लागू करने के लिए विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को भी मंजूरी मिल सकती है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। यह शपथपत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो इसके प्रारूप में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है।

उल्लेखनीय है कि चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति से आज मानव जाति के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। देश में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। लिहाजा मौत पर लगाम लगाने के साथ जन्म पर भी लगाम लगानी होगी। एकतरफा लड़ाई महंगी पड़ेगी। हमने मौत का दरवाजा तो छोटा कर दिया है, लेकिन जन्म द्वार पुरानी रफ्तार से ही बढ़ रहा है।

इस धरती पर कभी बड़े-बड़े डायनासोर होते थे। लेकिन उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि उनके खाने और रहने की जगह कम पड़ गई और उन सबका विनाश हो गया। आज मुश्किल से उनके सिर्फ कंकाल ही मिलते हैं। उनके विनाश का और कोई कारण नहीं है, न तो इतना बड़ा भूकंप आया और न अकाल पड़ा, बल्कि सबकी मौत भोजन की कमी से हो गई। जीव-जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां तो इस धरती से लुप्त हो गई हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लंदन विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन के अनुसार आज मानव जाति के सामने सबसे बड़ा संकट जनसंख्या विस्फोट का है। बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन कोई संयोग नहीं है। हम दुनिया की मौजूदा आबादी का ही पेट नहीं भर पा रहे हैं। बढ़ती आबादी की वजह से भोजन का संकट होने लगा है। खेती की जमीन सिकुड़ती जा रही है और बंजर जमीन में बदल रही है। पहले जहां खेती-बाड़ी होती थी, उन जगहों पर भी आज बस्तियां बस गई हैं और कल-कारखाने लग गए हैं। ऐसे में सबके लिए खाद्यान्न कहां से आएगा, यह कोई नहीं सोच रहा है। बढ़ती आबादी के साथ साथ संसाधनों की कमी आज भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए बहुत बड़ा संकट है।

आज इस पृथ्वी पर सात अरब से अधिक लोग हैं। भारत की आबादी वर्ष 1930 में 33 करोड़ थी। आज 135 करोड़ से अधिक हो गई है। सिर्फ 90 वर्षों में यह बढ़कर चार गुना से भी ज्यादा हो गई। यदि आबादी में वृद्धि की यह रफ्तार जारी रही तो इस सदी के अंत तक हम कहां खड़े होंगे कोई नहीं बता सकता। सभा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम जहां भी खड़े होंगे सभा ही होगी। सड़कों पर चलने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन इतने लोग कैसे जी सकते हैं। यह सवाल सारी दुनिया के सामने है, हमारे सामने सबसे अधिक है। सबसे अधिक इसलिए कि समृद्ध समुदायों के लोग बच्चे कम पैदा करते हैं और गरीब समुदायों के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। फिर समुदाय और जाति की राजनीति करने वाले दलों को देश की कोई चिंता नहीं है, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पतन की जिस पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, उसकी तो दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती है। कुछ धर्म गुरु कहते हैं कि बच्चे भगवान देते हैं। पर जो धर्म गुरु यह समझाते हैं कि बच्चे भगवान देता है, वे यह नहीं समझाते कि बीमारी भी भगवान देता है, उसका भी इलाज नहीं करवाना चाहिए। बीमारी का इलाज डाक्टर से करवा रहे हैं और बच्चे भगवान पर थोप देते हैं। ऐसे बहाने नहीं चलेंगे।

दुनिया के विकसित देशों ने अपनी आबादी को नियंत्रित कर लिया है। कई देशों में पिछले एकाध दशकों से आबादी स्थिर है। फ्रांस और जापान में तो घट रही है। चीन ने भी अपनी आबादी पर लगभग नियंत्रण पा लिया है, लेकिन भारत इस मामले में अभी तक पिछड़ा है। हालांकि अब ऐसे कृत्रिम साधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कर परिवार नियोजित किया जा सकता है। लेकिन लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। समाज को जागरूक बनाने की सरकार ने बहुत कोशिश की है। परंतु अभी तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लागू होना ही चाहिए।

अब जनसंख्या नियंत्रण या संतति नियमन को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जीवन मरण का सवाल है। यह अनिवार्य होना चाहिए। अनिवार्य का मतलब यह कि जिनके बच्चों की संख्या दो से अधिक हो, उन्हें तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। जिनके पास बच्चे कम हों उनको ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी हालत यह है कि अविवाहित आदमी पर टैक्स ज्यादा है और विवाहित पर टैक्स कम है। बच्चे हो जाएं तो और कम है। यह उल्टी बात है। अब अविवाहित आदमी पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए या न्यूनतम होना चाहिए। विवाहित पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए और बच्चों की संख्या के अनुसार पर बढ़ता जाना चाहिए। तभी हम आबादी को बढ़ने से रोक पाएंगे। सब तरफ से दो बच्चों के बाद सख्त से सख्त कदम उठाकर रोक लगानी चाहिए। उन्हें सरकारी नौकरियों के अलावा मताधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए। अब यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून बनाकर उसे लागू नहीं किया तो सबके सामूहिक विनाश की तैयारी कर लेनी चाहिए।

संसाधनों पर कम हो आबादी का बोझ



अनिल झा
पूर्व विधायक, दिल्ली विधानसभा व पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष, दिल्ली विवि

आज दुनियाभर में इस विषय पर गहनता से चिंतन हो रहा है कि जनसंख्या संसाधन है या समस्या। निश्चित रूप से यह गंभीर चिंतन का विषय है, खासकर भारत के संदर्भ में तो यह बेहद गंभीर मामला है। इस बारे में हमें इजरायल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इजरायल में भूमि बहुत ज्यादा नहीं है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश हरियाणा से भी छोटा है। लेकिन वहां की आबादी लगभग 90 लाख है। वैज्ञानिक शोध, कृषि उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, शक्तिशाली सैन्य बल, स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यवस्थित यातायात, शानदार पुलिसिंग जैसी व्यवस्थाएं इजरायल को प्रगतिशील बनाने का माद्दा रखती हैं।

क्या भारत में हम कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं? कई बुद्धिजीवी कह सकते हैं भारत जैसे विशाल देश और विशाल जनसंख्या के कारण हम इजरायल से इसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तो मानते ही हैं कि देश की आबादी या परिवार की संख्या अगर छोटी, शिक्षित और व्यवस्थित हो तो वह देश और परिवार अत्यधिक तरक्की करता है। हम यह भी जानते हैं कि विश्व की कुल भूमि का भारत में मात्र ढाई प्रतिशत है और जनसंख्या लगभग विश्व की कुल आबादी का 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत में अत्यधिक तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरों पर दबाव बढ़ गया है।

बढ़ती आबादी का बोझ ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लायक रोजगार नहीं पैदा कर पाता और वे शहरों की ओर पलायन करते हैं। लिहाजा अधिकांश शहर बेहद विकृत होते जा रहे हैं। शहर सुव्यवस्थित होने के बजाय स्लम बस्तियों में तब्दील होते जा रहे हैं। बढ़ती आबादी का बोझ शहरों में बीमारियों का बोझ भी बढ़ा रहा है।

इस पूरे प्रकरण का एक पहलू यह भी है कि हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। देश में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू मौजूद हैं। भारत में सिख मात्र तीन करोड़ हैं, लेकिन देश में रोजाना अपने गुरुद्वारों के माध्यम से वे पांच करोड़ लोगों को भोजन कराते हैं। यह अपने धर्म के अनुशासन, श्रद्धा और मान्यताओं के आधार पर ही हो सकता है। सिखों ने धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही शिक्षा का मिश्रण करते हुए अपनी आबादी को अत्यधिक शिक्षित और प्रगतिशील बनाया है। यही मामला जैन और पारसी से भी जुड़ा है। इन तीनों समुदाय के लोग अपनी जनसंख्या में पुरुषार्थ का गौरव भरते हैं, लिहाजा देश के व्यापार, उद्योग और निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। पारसी समुदाय की संख्या भारत में एक लाख के आसपास होगी, लेकिन भारत में वाहन उद्योग, ऊर्जा और स्टील उत्पादन में इस समुदाय के लोगों का व्यापक योगदान है। भारत के निर्माण और उसकी प्रगति में पारसी समुदाय की अहम भूमिका है।

बढ़ती आबादी किसी भी समुदाय की हो, अगर वह संविधान के कायदे-कानून के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं है तो उस देश में संसाधनों की लूट जैसी समस्याएं पैदा होने का प्रमुख कारण बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों की कमी होने के कारण लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। सीरिया, लीबिया, दक्षिण सूडान और यमन जैसे देश इसका ताजा उदाहरण हैं। बढ़ती आबादी, अशिक्षा और संसाधनों में असमानता के कारण मध्य और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों और मध्य एशिया के देशों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2010 के मध्य जनसंख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2030 तक विश्व की आबादी 8.6 अरब होने का अनुमान है। इस दौरान भारत की जनसंख्या में भी तेजी से वृद्ध हुई है। ऐसे में भारत के बेहतर भविष्य के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इसे कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।

खरी-खरी

कथित साहित्यकार का छिपा एजेंडा

देवेंद्रसिंह सिसौदिया

शहर में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। शहर के प्रसिद्ध मानसिक रोग विशेषज्ञ को एक पल की फुर्सत नहीं थी। उन्हें समाज सेवा के जरिये पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर दिखने लगा था। इस हेतु उन्होंने अपने सुसुप्त कवि को जागृत किया। उन्होंने अपने कंपाउंडर को एक प्रश्नावली तैयार करके दे दी कि कोई भी मरीज आए तो इसे भरवाओ।

जब भी कोई मरीज आता, कंपाउंडर उस प्रश्नावली को सामने रख देता। मरीज चौंक जाता कि इसका बीमारी के इलाज से क्या लेना-देना? पर मरता क्या न करता। वो चुपचाप प्रश्नावली को भरना शुरू कर देता। प्रश्न कुछ इस प्रकार थे...

कोई कविता लिखी हो तो उसकी चार लाइन लिखें? कविता या समाज सेवा में कोई पुरस्कार मिला है? यदि हां, तो पुरस्कार प्राप्त करने की जुगाड़ कैसे बैठाई? क्या आज भी समाजसेवा या लेखन में रुचि रखते हैं? यदि साहित्य की संस्था बनाएं, तो आप सदस्य बनेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

पचासेक प्रश्नावली इकट्ठी होने पर कंपाउंडर और डाक्टर विश्लेषण करने बैठे। कंपाउंडर ने पूछा, 'साहब इस प्रश्नावली का क्या मतलब?'

'अरे मोहन, तू नहीं समझेगा। देखता जा बस।' डाक्टर साहब ने उनमें से दस नाम निकाले और बोले, 'कल इन्हें बुलाओ। बैठक करेंगे।'

दूसरे दिन नियत समय पर सभी आ गए। डाक्टर ने कहा, 'मित्रो, आज हम यहां अपने शौक को पूरा करने के उद्देश्य से एक साहित्य संस्था का गठन करने के लिए एकत्रित हुए है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य होगा, महिला एवं बाल विकास के साथ उन में साहित्यिक रुचि जागृत करना।' कुछ दिनों के अंतराल पर संस्था की तमाम गतिविधियों से संबंधित समाचार छपते रहे।

आगामी 12 माह में 13 खबरें छप गईं। सभी अपने एलबम तैयार करने में जुटे थे। डाक्टर साहब अपने हिडन एजेंडा को पूरा करने में सफल रहे। उन्होंने फाइल तैयार कर समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए मंत्रालय को भेज दी। संस्था के कवि सदस्य अपना फोटो अखबारों में देख-देख कर खुश होते रहे और कविता एक कोने में खड़ी आंसू बहाती रही।

ट्वीट-ट्वीट

अब भले ही राजद्रोह कानून की आवश्यकता पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन जज जो गाउन पहनकर अदालत में बैठते हैं, उससे लेकर अपराध संहिता तक न्यायपालिका से जुड़ा प्रत्येक पहलू औपनिवेशिक प्रतीकों से जुड़ा है।
विकास सारस्वत@VikasSaraswat

यह बात कोई और नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के उप-राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वायु सेना तालिबान को मदद मुहैया करा रही है।
संदीप@SandeepUnnithan

दानिश सिद्दीकी भारत की आंख जैसे थे। उन्होंने हाल के दौर की कुछ बेहतरीन तस्वीरें उतारी थीं। हमने अफगानिस्तान युद्ध में उन्हें गंवा दिया। दो दिन पहले ही वह बाल-बाल बचे थे।
बशारत पीर@BasharatPeer



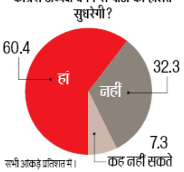
न्यायाधीशों और एनएचआरसी को राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित और पक्षपात करने वाला बताने पर ममता बनर्जी की कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। आखिर बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में हत्या, दुष्कर्म और विस्थापितों की संख्या झूठी तो नहीं है। ये सभी राजनीतिक अपराध हैं। बस सवाल यही है कि क्या ममता ने उन्हें भड़काया।
महेश जेठमलानी@JethmalaniM

खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे।
अरुण गोविल@arungovil12

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या गांधी परिवार से बाहर के नेता के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पार्टी की हालत सुधरेगी?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या राजद्रोह से संबंधित कानून रद कर दिया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अमरिंदर की काट कर राजनीति में जोत,
उनका आधा खेत यदि जोतेंगे नवजोत।
जोतेंगे नवजोत पटेगा कैसे सौदा,
सौ की सीधी बात यही है असली मुद्दा!
बैटिंग में नवजोत भले हों बड़े सिकंदर,
लेकिन असली टीम कैप्टन हैं अमरिंदर!!
– ओमप्रकाश तिवारी



आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

रेत सरीखे ढह रहे रेत से जगे अरमान

जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय बिहार के पास खेतिहर जमीन और बालू ही बची थी। सारे खनिज झारखंड की झोली में चले गए थे। जब कुछ नहीं बचा तो बालू से तेल निकालने का यहां सिलसिला शुरू हो गया जो इस समय चरम पर है। अवैध खनन की बढ़ती शिकायतों और बालू के बेतहाशा बढ़ते दाम से आजिज सरकार ने जब गुपचुप जांच कराई तो पांच जिलों के ही 41 अधिकारी लपेटे में आ गए। अभी और कितने नपेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन कार्रवाई को लेकर कई महकमों में हड़कंप मचा है। इस कार्रवाई से रेत से कमाई करने वालों के अरमान रेत सरीखे ही ढहते दिखाई दे रहे हैं।

बालू घाटों की बंदोबस्ती में हमेशा बाहुबल का बोलबाला रहता है। बिहार के 24 जिले बालू के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय केवल आठ जिलों से ही बालू निकालने की अनुमति है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ष 2019 में राज्य सरकार यह नियम लाई थी कि अब एक जिले में एक ही बंदोबस्तधारी के बजाय घाटों के छोटे-छोटे बंदोबस्त किए जाएं। यह मामला एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में चला गया। हालांकि एनजीटी ने सरकार के पक्ष में फैसला तो दे दिया, लेकिन इसे पर्यावरण विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाई। सरकार ने बाद में 50 फीसद शुल्क बढ़ाकर पुरानी व्यवस्था ही इस ढील के साथ बहाल कर दी कि बालू का रेट वे स्वयं निर्धारित कर लें। इस पर 16 जिलों के बंदोबस्तधारी विरोध कर गए और वहां खनन बंद हो गया। रेट निर्धारित करने का परिणाम यह निकला कि पिछले साल तक ढाई-तीन हजार में सौ घन फीट मिलने वाली बालू चार-साढ़े चार हजार से होती हुई सात हजार तक पहुंच गई। जहां खनन बंद हुआ, वहां अवैध खनन शुरू हो गया। थानों से लेकर चुंगी तक के रेट बढ़ गए। अभी आलम यह है कि जिलों के हिसाब से अलग-अलग रेट हैं। राजधानी पटना तो में 12 से 15 हजार में मिल रही है।



गंगा में इन अवैध नावों से आरा के विभिन्न घाटों पर जारी बालू का अवैध खनन। सोन और गंगा में अवैध खनन में हजारों नावें लगी रहती हैं। इसमें पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। जागरण

बिहार में बालू का अर्थशास्त्र कुछ इस तरह है कि यहां 24 जिलों में छह से सात करोड़ घन फीट प्रतिमाह के हिसाब से नौ महीने तक बालू का खनन होता है। सरकार को करीब 766 करोड़ रुपये इससे आय होती है। मार्च में 16 जिलों में खनन रुकने के बाद इन जिलों में अवैध खनन तेजी से शुरू हो गया। महकमे-महकमे रेट तय हो गया। चढ़ावों ने बालू की कीमत उछाल दी, जो आम उपभोक्ताओं की पकड़ से बाहर होने लगी। सरकार ने इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी। पांच जिलों (पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और रोहतास) में गुपचुप हुई जांच में इस खेल में बड़े-बड़े संलिप्त दिखाई दिए। इसमें भोजपुर और औरंगाबाद के एसपी समेत 41 अधिकारी पहले झटके में लपेटे में आ गए। इतना ही नहीं, इसमें चार इंस्पेक्टर, 14 दारोगा, एक एसडीओ, छह खनन पदाधिकारी, पांच अंचलाधिकारी, तीन एमवीआइ (मोटर वेहिकल इंस्पेक्टर) दो जिला परिवहन अधिकारी और चार एसडीपीओ शामिल हैं। अभी जांच जारी है और माना जा रहा है कि इस खेल में और भी बड़े-बड़े नाम शामिल हैं, जिनका बचना मुश्किल है।

खनन बंद होने और अवैध खनन के कारण बालू की बढ़ती कीमत का असर बाजार पर भी पड़ा है। बरसात के समय बालू का होने वाला स्टाक इस बार नहीं है, हालांकि खान एवं भूतत्व विभाग का दावा है कि राज्य में 46.26 करोड़ घन फीट का भंडार है, लेकिन बालू की जबरदस्त किल्लत है और उसके कारण निर्माण कार्य लगभग ठप हो गया है। कहा जा सकता है कि मकान बनाने के लिए सबसे जरूरी बालू ने इस समय सीमेंट, सरिया, ईंट, बिजली के सामान, टाइल्स आदि सभी पर नजर लगा दी है, जिनके दाम तो मार्च के बाद बढ़े, लेकिन बिक्री ठप हो गई है। इस समय राजधानी पटना में फ्लैट्स के दाम 20 फीसद तक बढ़ गए हैं। जिसमें बालू का योगदान सबसे ज्यादा है। बालू की तेजी ने बाजार का हाल मंदा कर दिया है। अब सरकार पर काफी कुछ निर्भर है कि वह इस हालात से कैसे निपटती है। उसके सामने 16 जिलों में घाटों की बंदोबस्ती करने, घूसखोर अधिकारियों पर अंकुश लगाने और अवैध खनन रोक कर बालू की हालत सामान्य करने की चुनौती है, ताकि निर्माण की चाहत रखने वालों को कम कीमत पर बालू मुहैया हो सके।

मंथन



डा. लक्ष्मी शंकर यादव
पूर्व प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान विषय

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार और रक्षा नवाचार संगठन का देश की रक्षा और वैमानिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशीकरण को हासिल करना प्रमुख उद्देश्य है



सेना के लिए हथियारों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते कदम। फाइल

रक्षा और वैमानिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुसंधान एवं विकास पर जोर देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने अगले पांच वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार (आइ-डीईएक्स) के लिए रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) को पिछले माह 499.8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता मंजूर की है। इस रकम से रक्षा क्षेत्र में इस नए अन्वेषण के साथ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन फ्रेमवर्क के साथ लगभग 300 स्टार्ट अप्स, एमएसएमई, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों और 20 साझेदार इनक्यूबेटर को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह कदम रक्षा जरूरतों के बारे में भारतीय नवाचार पारितंत्र में जागरूकता बढ़ाने और इसके विपरीत भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिनव समाधान देने की उनकी क्षमता के प्रति जागरूकता पैदा करने में सहायता प्रदान करेगा। इससे रक्षा नवाचार संगठन अपनी टीम के साथ नवोन्मेषकों के लिए चैनल बनाने में सक्षम होगा जिससे वे भारतीय रक्षा उत्पादन उद्योग के साथ जुड़ सकें। जहां भारतीय सेना द्वारा नवोन्मेषकों के प्रयास को सूचीबद्ध करना आम बात होती है।

इस योजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा और वैमानिकी क्षेत्र के लिए नई स्वदेशी तथा अभिनव प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास को सरल बनाना है। इसकी सफलता से अल्प समय सीमा में उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। यह रक्षा एवं वैमानिकी जरूरतों के बारे में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के पार्टनर इनक्यूबेटर सहित अन्य प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ संवाद करेगा। इसके अलावा, यह विभाग संभावित प्रौद्योगिकियों और संस्थाओं को शार्टलिस्ट करने तथा रक्षा एवं वैमानिकी सेटअप पर उनकी उपयोगिता व प्रभाव के संदर्भ में प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का मूल्यांकन करेगा। रक्षा क्षेत्र की अन्य गतिविधियों में पायलटों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से निर्धारित नवाचार विधियों का उपयोग करके उनका वित्तपोषण करना है। इसके साथ ही प्रमुख नवीन प्रौद्योगिकियों के बारे में सुरक्षा बलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करके उपयुक्त सहायता के साथ रक्षा प्रतिष्ठानों में उनको अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया जाना शामिल है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत को सैन्य प्लेटफार्म तथा उपकरणों के विनिर्माण में निवेश के लिए एक आकर्षक स्थल के रूप में पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। गत माह भारत स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने स्वीडन की अग्रणी रक्षा उत्पादन कंपनियों को भारत में विनिर्माण के केंद्र बनाने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने अनेक ऐसे सुधार किए हैं जो भारत की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही वैश्विक मांगों को भी पूरा करने में रक्षा उद्योग के लिए काफी मददगार साबित होंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सरकार ने स्वचालित रूप से 74 प्रतिशत तथा सरकार के रास्ते 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान कर दी है।

विदेश के वास्तविक उपकरण निर्माता अपने बल पर ही संस्थान स्थापित कर सकते हैं और इस काम के लिए वे भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी भी कर सकते हैं। इस तरह स्वीडन की कंपनियां भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल का फायदा उठा सकती हैं। स्वीडन की कुछ कंपनियां भारत में पहले से मौजूद हैं और वे अच्छा कार्य कर रही हैं। उस आधार पर नई कंपनियां समझ सकती हैं कि भारत रक्षा निर्माण एवं निवेश के लिए एक प्रमुख स्थल है। इस तरह भारत के रक्षा उद्योग और स्वीडन की कंपनियों के बीच रक्षा उपकरण उत्पादन की विशेष संभावनाएं हैं।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने अगस्त 2020 में 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी। अब भारत में ही इनका निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने इन रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए 460 से ज्यादा लाइसेंस जारी कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में आयुध कारखानों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वे अपनी कुल आय का एक चौथाई हिस्सा राजस्व निर्यात से हासिल करें। यदि यह सब संभव हुआ तो भारत जल्द ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा।

रक्षा मंत्री ने 31 मई को 108 सैन्य हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है। इन 108 शस्त्र और रक्षा प्रणालियों में अगली पीढ़ी के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, टैंक के इंजन और रडार जैसे सिस्टम व साजो-सामान शामिल हैं। इस सूची में शामिल सभी 108 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में उत्तरोत्तर प्रभावी रहेगा। भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 2024 के बाद लंबी दूरी के ग्लाइड बम भी स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। इतना ही नहीं, इसी साल से फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर बमों को भी स्वदेश में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा, पहाड़ों पर लगने वाले लंबी दूरी तक की टोह लेने वाले रडार भी इसी साल से भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जा सकेंगे। कुल मिलाकर आयात नहीं किए जाने वाले उपकरणों की सूची 209 तक पहुंच गई है।

20 लाख भारतीय अकाउंट पर 15 मई से 15 जून के बीच मैसेजिंग एप वाट्सएप ने लगाई रोक। यह प्रतिबंध नुकसानदेह और अवांछित संदेशों के कारण लगाया गया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 17 जुलाई, 2021

बंगाल

एनएचआरसी की जांच रिपोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की विशेष समिति ने जांच कर अंतिम रिपोर्ट पांच जजों की पीठ को सौंप दी। इस अंतिम रिपोर्ट से राज्य प्रशासन की काफी फजीहत होने वाली है। 50 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। समिति ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर की धरती बंगाल पर 'कानून का राज' नहीं है, बल्कि यहां 'शासक का कानून' चल रहा है। समिति ने हिंसा की जांच के बाद अपनी सिफारिशें दी हैं, जिसमें कहा गया है कि जिन गांवों में हिंसा के पांच से ज्यादा मामले हुए हैं, वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) लगाई जाए।

आयोग की टीम ने सिफारिश की है कि हत्या, अस्वाभाविक मौत, दुष्कर्म जैसे सभी गंभीर मामलों को जांच के लिए सीबीआइ को सौंपा जाए। कई केस के बारे में कहा गया है कि उनके ट्रायल राज्य से बाहर किए जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक विशेष जांच टीम (एसआइटी) का तुरंत गठन किया जाए जिसमें सीनियर आइपीएस अधिकारी हों। इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि चुनाव बाद बंगाल में हिंसा हुई है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव बाद बंगाल में हिंसा होने से इन्कार किया था। परंतु यह सत्यापित उसी समय हो गया जब हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने माना कि हिंसा हुई है और इसके लिए एनएचआरसी को विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया। यहां तक कि जांच के दौरान कोलकाता के जादवपुर इलाके में जब एनएचआरसी की जांच टीम के सदस्य पहुंचे तो उन के साथ भी बदसलूकी की गई थी।

> रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य प्रशासन ने जनता में विश्वास खो दिया है। समिति ने कहा है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, बल्कि शासक का कानून चल रहा है

अब जब कि रिपोर्ट सामने आई है तो ममता इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार पर हमले बोल रही है। जबकि सच्चाई यह है कि एनएचआरसी की जांच हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उन्होंने वहां जांच करने के लिए कितने कमीशन भेजे हैं? हाथरस से लेकर उन्नाव तक कई घटनाएं हो चुकी हैं। वे बंगाल को बदनाम करते हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा चुनाव से पहले हुई थीं। उन्होंने एचआरसी की रिपोर्ट लीक होने को लेकर भी सवाल उठाया। परंतु ममता बनर्जी को समझना होगा कि यह जांच हाई कोर्ट के निर्देश पर है, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

बिहार

नियोजन प्रक्रिया पर उचित निर्णय

शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की शिकायतों पर सरकार ने 400 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद करने का निर्णय लिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह उचित कदम है। हद तो यह है कि ये अनियमितताएं तब की गईं जब इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराई जा रही थी। राज्य सरकार ने तीन दिनों के अंदर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला कार्यक्रम अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है तथा इसके आधार पर नियोजन इकाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया है।

राज्य सरकार की ओर से शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की आनलाइन मानीटरिंग की व्यवस्था करते हुए वीडियो रिकार्डिंग कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद सरकार को मेधा सूची में नाम नहीं रहने के बावजूद अभ्यर्थी को बुलाए जाने, रजिस्टर से छेड़छाड़ करने, रोस्टर का उल्लंघन करने तथा हंगामा व मारपीट की शिकायतें मिलीं। सबसे अधिक ग्राम पंचायत की नियोजन इकाइयों में अनियमितता की शिकायतें थीं। ऐसे में दोषी पाए जाने वाले लोगों को हर हाल में दंडित किए जाने की जरूरत है।

> शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को हर हाल में गैर विवादित व पारदर्शी बनाने की जरूरत है। तभी राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव हो सकेगा


पारदर्शिता के साथ हो शिक्षकों का चयन। फाइल

सरकार ने साफ कहा है कि गड़बड़ी करने वाले पंचायत के प्रतिनिधि या अधिकारी हों या फिर खुद अभ्यर्थी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल, ऐसे कृत्यों से जहां सरकारी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगता है, वहीं आमजन में गलत संदेश जाता है, जिससे सरकार की नकारात्मक छवि बनती है। इससे पहले भी जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई, तब अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। शिक्षकों की योग्यता भी गाहे-बगाहे मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं। यही वजह है कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर वर्ष 2006 से 2015 के बीच विभिन्न नियोजन इकाइयों द्वारा नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी ब्यूरो कर रही है।

इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच में छूटे 87,665 शिक्षकों को वेबपोर्टल पर शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक कागजात अपलोड करने के लिए 21 जून से 20 जुलाई तक का समय दिया था, किंतु अब तक करीब 68 हजार शिक्षकों ने अपना ब्योरा अपलोड नहीं किया है।

ऐसे में यह उचित ही है कि बिहार सरकार ने उन शिक्षकों की सेवा समाप्त करते हुए वेतन के रूप में उन्हें मिली राशि की वसूली का निर्णय लिया है जो तय समय सीमा के बीच अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं।

झारखंड

नक्सलियों पर नकेल

खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर झारखंड के विकास में नक्सली सबसे बड़ी बाधा रहे हैं। विकास कार्यों को यहां लगातार नक्सलियों ने रोका है। उद्योग, खनन व्यवसाय, पर्यटन समेत तमाम क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। हाल के वर्षों में ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों की ताकत पहले की अपेक्षा थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन बीच-बीच में नक्सली सिर उठाकर हिंसक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। सरकार के साथ ही आम लोगों को भी उग्रवादी नुकसान पहुंचाते रहे हैं। सरकार की ओर से लोगों में पनपी असुरक्षा की भावना को दूर करने के प्रयास भी लगातार हो रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में भय का माहौल दूर हुआ है।

गुमला में लगातार दो दिनों तक जंगल में बम बिछाकर नक्सलियों ने विस्फोट कर सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन घटनाओं में पुलिस के श्वान दस्ते के एक श्वान और एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने

> लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर नक्सली विकास में बाधक बनते रहे हैं। इनसे अब सख्ती से निपटना ही होगा


नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें सुरक्षाबल। फाइल

15 लाख के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर को मार गिराया है। नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मुख्य धारा में लौटने की इच्छा रखने वाले नक्सलियों को भले ही समर्पण का मौका मिले, लेकिन जो नक्सली पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ आंखमिचौली खेल कर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनका सफाया होना चाहिए। नक्सलियों की नकेल कसने के लिए प्रभावी आपरेशन लगातार चलते रहने चाहिए। इसके साथ ही सुदूर क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को भी जारी रखना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सलियों से संवाद और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

पूरे राज्य में अब तक दर्जनों बड़े नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। नक्सलियों को भी यह बात समझनी होगी कि अलगाव का रास्ता उन्हें किसी मुकाम पर नहीं ले जाएगा। लोकतंत्र में संविधान के रास्ते चलकर ही अपने विचार को रखा जा सकता है। जो समाज के दुश्मन हैं, उन्हें न तो समाज माफ करता है, न कानून। सरकार को नक्सल समस्या को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखते हुए नक्सलियों पर नकेल कसनी ही होगी। इसके लिए संवाद और सख्ती दोनों रास्ते अपनाने होंगे।

उत्तराखंड

परिवहन निगम की कार्यशैली पर सवाल

गठन के 18 वर्ष बाद भी परिवहन निगम की आर्थिकी का पटरी पर न आना चिंताजनक है। मौजूदा स्थिति यह है कि निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। निगम इसके लिए पूरी तरह सरकार के भरोसे है। स्थिति यह बनी कि कर्मचारियों के वेतन को लेकर हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। हाईकोर्ट ने सरकार व शासन को परिवहन निगम कर्मियों का वेतन देने और परिवहन निगम प्रबंधन को आय के साधन बढ़ाने की कार्ययोजना बनाने को कहा है। जो आदेश कोर्ट ने दिए, बेहतर होता कि उन पर निगम प्रबंधन पहले ही स्वयं अमल शुरू कर देता।

निगम की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो गठन के बाद से अभी तक परिवहन निगम 520 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। यह स्थिति तब है जब सरकार ने समय-समय पर परिवहन निगम को नई बसों की खरीद और व्यवस्था सुचारु रखने के लिए स्वयं तो आर्थिक मदद दी ही, साथ ही ऋण भी दिलाया है। ऋण के ब्याज का भुगतान भी कई बार सरकार ने खुद किया है।

> उत्तराखंड परिवहन निगम का लगातार घाटे में चलना कहीं न कहीं निगम प्रबंधन की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा करता है। निगम को पेशेवर रवैया अपनाना ही होगा

यह बात सही है कि सरकार परिवहन निगम में समाज के कई वर्गों को मुफ्त सफर करा रही है, मगर इसकी प्रतिपूर्ति देर सवेर तो हो ही रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बसों के संचालन से होने वाले नुकसान का पैसा भी सरकार दे रही है। ऐसे में निगम का घाटे में चलना समझ से परे है। अन्य प्रदेशों के निगमों पर नजर दौड़ाएं तो वे उत्तराखंड से बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तराखंड परिवहन निगम में भ्रष्टाचार के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं, बावजूद इसके दोषी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में निगम प्रबंधन सख्ती नहीं दिखाता। इससे निगम प्रबंधन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इसी वजह से निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कई बार मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। निगम की माली हालत सुधरती न देख इस बार निगम प्रबंधन बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन के साथ ही सुविधाओं में कटौती करने का निर्णय लिया, जिसका विरोध हुआ। कर्मचारी यदि पूरा काम कर रहे हैं तो उनके वेतन व सुविधाओं में कटौती उचित नहीं है। निगम कार्मिकों का भी दायित्व है कि वे भी पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करें।

बेहतर होगा कि प्रबंधन निगम को घाटे से निकालने की ठोस कार्ययोजना बनाए। इसे शासन और सरकार से साझा करे, उनका मार्गदर्शन ले। सरकार को भी चाहिए कि वह निगम की गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस पर नजर रखे। समय-समय पर निगम की योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करे।

झरोखों से नहीं झांकेगी दोस्ती, देउबा खोलेंगे बड़े दरवाजे

जागरण टीम, नई दिल्ली

सीमाओं ने भले दो देशों में विभाजित कर दिया, मगर संस्कार, सहजता और सहभागिता एक धारा में प्रवाहित होती रही। इसी के सहारे भारत और नेपाल की दोस्ती रोटी-बेटी के रिश्ते तक पहुंचती गई। मगर, मित्र देश में सियासत की स्याह छाया ने कुछ समय से दोस्ती को झरोखे में कैद कर रख दिया था। अब चीन की खातिर दोस्ती को स्वार्थ के पलड़े में रखने वाले केपी शर्मा ओली सत्ता से बेदखल किए जा चुके हैं। भारत से लगाव रखने वाले शेर बहादुर देउबा वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल की बदली सियासी तस्वीर का प्रभाव सिर्फ शब्दों तक सीमित मत रखिए, नेपालियों के बीच जाएंगे तो इसे महसूस भी करेंगे।

यह बात उल्लेखनीय है कि देउबा सुदूर पश्चिमी नेपाल के डडेलधुरा जिले के रहने वाले हैं। यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से सटा है। ऐसे में बचपन से उनका पिथौरागढ़ व भारत से खास लगाव रहा है। छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत के दौरान भी देउबा इस क्षेत्र में आते रहे।

गुरुवार की शाम दोनों ओर की चहल-पहल एहसास करा रही कि नेपाल का बदला राजनीतिक परिदृश्य मित्रता को झरोखे से निकालकर बड़े दरवाजे की ओर ले जा रहा। इसे नौजल्हा की बाजार से खाद्य सामग्री खरीदकर ला रहे दोधारा चांदनी के नौजवान बबलू से समझें... 'देखिए भारत और नेपाल के रिश्ते पर कोई सवाल करना ठीक नहीं। दो देश हैं, मगर जीवन-शैली एक जैसी है।' कहते-कहते वह माता सीता और भगवान राम का संदर्भ देते हुए भारत-नेपाल को रिश्तों से जोड़ते हैं। क्या अब माहौल बदलेगा, इस सवाल पर कहते हैं, सरकारें अपना काम करती हैं, मगर नागरिकों की संवेदनाएं अलग हैं। हो सकता है कि पुरानी सत्ता की सोच से कुछ परेशानी हुई हो, मगर नेपाल और भारत के लोगों में दूरी कभी नहीं बनी। उत्तराखंड की नंबर प्लेट वाली बाइक के मालिक बबलू कहते हैं कि मेरा तो अधिकतर समय भारत में ही गुजरता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरू में नौकरी करने लगा था। कोरोना संक्रमण के कारण घर आ गया हूं, कुछ दिन बाद वापस चला जाऊंगा।

- सीमावर्ती गांव में रहने वाले नेपालियों को उम्मीद, नरम होगा बार्डर का माहौल
- दोनों देशों के नागरिक चाहते हैं मधुर संबंध, आड़े आ रहा था ओली का रुख


नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का भारत से विशेष लगाव रहा है। फाइल

पिथौरागढ़ में भी जश्न

ओली की नीतियों का प्रभाव भारत-नेपाल के रोटी-बेटी के मधुर संबंधों पर भी पड़ा। ऐसे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत, बनबसा, टनकपुर और खटीमा की जिन बेटियों की शादी नेपाल में हुई वह न तो एक वर्ष से अपने घर आ पाईं और न ही मायके वाले बेटी के ससुराल पहुंचे। इस सब के बीच जब शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो काठमांडू व तराई के साथ ही सीमावर्ती पिथौरागढ़, चंपावत व खटीमा में भी जश्न मना। लोगों को लगा कि अब नेपाल से रिश्ते सामान्य होंगे और फिर पुराने सौहार्द के दिन लौटेंगे। रोटी-बेटी के संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

देउबा के प्रधानमंत्री बनने से मजबूत होगी रिश्तों की डोर

नेपाल के नए पीएम के समर्थन में उप्र के महराजगंज के समीपवर्ती नवलपरासी व रूपनदेही सहित मधेश बहुल 21 जिलों में जमकर जश्न मन रहा है। सभी को उम्मीद है कि नई दिल्ली व काठमांडू के बीच रिश्तों की गर्मजोशी को नया आयाम मिलेगा। नवलपरासी के सांसद व नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र राज कंडेल कहते हैं कि पांचवीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउबा अनुभवी नेता हैं। 75 साल के जीवन में उन्होंने कई राजनैतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। वह जब भी प्रधानमंत्री बने, भारत से नेपाल के रिश्ते बेहतर हुए।

अकाल तख्त के पास मिली सुरंग की एएसआइ करेगी जांच

जागरण संवाददाता, अमृतसर : गुरुनगरी में श्री अकाल तख्त साहिब के पास खोदाई के दौरान मिली सुरंग की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम करेगी। प्रशासन ने इस संबंध में एएसआइ को पत्र भेज दिया है।

गौरतलब है कि गुरुवार को श्री हरिमंदिर साहिब स्थित श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर जोड़ाघर के लिए खोदाई के दौरान नानकशाही ईंटों से बनी सुरंग मिली थी। इसको लेकर पक्ष आमने-सामने हो गए थे। एक पक्ष सुरंग बंद कराने और दूसरा इसकी जांच कराने पर अड़ा था। आखिर जिला प्रशासन ने काम रुकवा दिया। शुक्रवार को सुरंग की जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखा गया है।

दरअसल, अमृतसर शहर का सुरंगों से पुराना नाता रहा है और समय-समय पर सुरंगें मिलती रही हैं। महाराजा रणजीत सिंह के शासन के समय अमृतसर और लाहौर के बीच सुरंग के जरिये गुप्त संदेश पहुंचाए जाते थे। शेरशाह सूरी के कार्यकाल में भी सारा डाक सिस्टम सुरंगों के माध्यम से चलाया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुरु काल और उनके बाद श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास बुंगे (छोटे-छोटे कमरे) बनाए गए थे। हो सकता है कि अब जो सुरंग रूपी कमरे मिले हैं, यह उन्हीं बुंगों का हिस्सा हों।

जल पर्यटन के जरिये एक डोर में बंधेगी शिव और शक्ति की नगरी


बनारस में रविदास घाट पर गंगा में रो पैक्स। जागरण


रो पैक्स में इन सीटों पर बैठेंगे पर्यटक। जागरण

जेपी पांडेय, वाराणसी

देश में पर्यटन विस्तार के अभियान को जल पर्यटन आधार देगा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले से एक जलयान का संचालन हो रहा था तो अब पीएम के हाथों लोकार्पण के बाद गंगा में जल्द दो रो पैक्स के साथ ही एक और जलयान गंगा घाटों की छटा दिखाएगा। खास यह कि रो पैक्स मां विंध्यवासिनी धाम यानी मीरजापुर तक जाएंगे। बनारस के आकर्षण से भले ही देश-दुनिया के पर्यटक परिचित हैं, लेकिन जलमार्ग से जुड़ जाने पर वे विंध्य क्षेत्र के पर्वत, झीलों, प्राचीन किलों के साथ अद्भुत प्राकृतिक नजारों की अपार संपदा से भी रूबरू हो सकेंगे। 200 यात्री क्षमता वाले रो पैक्स को पहले चरण में पार्टी या ग्रुप के लिए बुक किया जा सकेगा। इसमें किचेन के साथ सांस्कृतिक आयोजन तक के लिए स्थान है। इसे अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराया गया है। माना जा रहा इसके संचालन से अब तक कम फोकस में रहा चुनार क्षेत्र भी पर्यटन के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फलक पर निखर कर सामने आएगा।

> रो पैक्स में कुछ काम बाकी हैं। इन्हें पूरा होने में 10 दिन लगेंगे। सावन में पूरी तैयारी के साथ संचालन शुरू किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। संत रविदास घाट को केंद्र मानकर एक रो पैक्स मारकंडेय महादेव और दूसरा शूलटंकेश्वर मंदिर की तरफ भेजा जाएगा।
>
> -विकास मालवीय, निदेशक, अलकनंदा क्रूज लाइन

फिलहाल रो पैक्स गाजीपुर में कैथी से शूलटंकेश्वर तक चलाए जाएंगे, मगर बहुत जल्द इनका विस्तार चुनार और मीरजापुर तक करने की योजना है। अध्यात्म, धर्म और इतिहास को समेटे बनारस के 84 घाटों का नजारा लोगों को खूब रोमांचित करता है। अब इन्हें अत्याधुनिक जलयान में बैठकर देखा जा सकेगा। पर्यटकों को घाटों का धार्मिक-आध्यात्मिक इतिहास आडियो-वीडियो के जरिये बताया जाएगा।

नाम है विवेकानंद, सैम मानेकशा : दोनों रो पैक्स भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उपलब्ध कराया। एक का नाम विवेकानंद क्रूज और दूसरे का सैम मानेकशा क्रूज है। इनमें 200 पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था है। वाशरूम और शौचालय की भी सुविधा है। इनकी कीमत 22 करोड़ रुपये है और रफ्तार 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है।

यह है सुरक्षा व्यवस्था : रो पैक्स में सुरक्षा के लिए 12 अग्निशमन यंत्र, 220 लाइफ जैकेट, 20 लाइफ राफ्ट बोट (आपात स्थिति में एक पर 10 लोग निकाले जा सकेंगे) होंगे। टिकट पैकेज में लंच व दो वक्त का नाश्ता होगा। टिकट का किराया जिला प्रशासन, पर्यटन व कंपनी मिलकर तय करेगी।

घरेलू नुस्खों से तैयार की औषधि, नाम संग पैसे भी कमा रहीं महिलाएं

जागरण विशेष

छत्तीसगढ़ में महिलाएं जंगल से करती हैं जड़ी-बूटियां एकत्रित, 40 क्विंटल चूर्ण का निर्माण कर 44 लाख रुपये का किया कारोबार

सुरेश देवांगन ● कोरबा

मजदूरी कर जीविकोपार्जन करने वाली महिलाओं के जेहन में आई एक युक्ति ने उनकी जिंदगी बदल दी है। घरेलू नुस्खे अपनाने वाली इन महिलाओं ने जंगल से जड़ी-बूटियां एकत्रित कर औषधि बनाने की शुरुआत की है। देखते ही देखते औषधियों की मांग बढ़ी और अब 44 लाख रुपये का सालाना कारोबार करने लगी हैं।

ये महिलाएं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के वनांचल ग्राम डोंगानाला की हैं। घरेलू नुस्खों की जानकारी यहां मजदूरी करने वाली 28 वर्षीय सरोज पटेल को थी। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में लाकडाउन के कारण काम मिलना मुश्किल हो गया, तब उन्होंने अपने घरेलू नुस्खों से ही औषधि बनाने की ठानी। गांव की ही 10 महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा और जंगल में मिलने वाली जड़ी-बूटियों को एकत्रित कर औषधि बनाने का काम शुरू किया। इस बीच हरिबोल स्वसहायता समूह का गठन किया और आठवीं कक्षा तक पढ़ी सरोज ने अध्यक्ष की कमान संभाली। समिति ने वन विभाग के कटघोरा संजीवनी मार्ट पर मधुमेह नाशक व त्रिफला चूर्ण की आपूर्ति की। मांग बढ़ती गई और राज्यभर के संजीवनी मार्ट से आर्डर आने लगे। वर्तमान में इन महिलाओं की ओर से 18 तरह के औषधि चूर्ण का निर्माण किया जा रहा है। वन मंडलाधिकारी कटघोरा शमा फारुकी ने बताया कि वर्ष 2020-21 में समिति ने 40 क्विंटल औषधि चूर्ण का निर्माण कर 44 लाख रुपये का कारोबार किया है। इससे समिति को काफी धनराशि अर्जित हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन महिलाओं की सराहना कर चुके हैं।

अब मुझे इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता : स्वसहायता समूह की बनाई औषधि का इस्तेमाल करने वाली फुटहामुड़ा बिलासपुर निवासी 70 साल की बुजुर्ग महिला बैशाखीन बाई का कहना है कि मधुमेह की वजह से वह बेहद परेशान थीं। उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। समूह के बनाए मधुमेह चूर्ण के नियमित सेवन के बाद अब उन्हें इंसुलिन नहीं लेना पड़ता।

ऐसे बनाती हैं मधुमेह चूर्ण: मधुमेह चूर्ण बनाने के लिए बेल की पत्ती, नीम की पत्ती, जामुन की गुठली, हर्र, आंवला, बहेड़ा, भूइनीम, गुड़हल पत्ती एकत्र करती हैं। बाजार से अजवाइन, मैथी, करेला बीज खरीदती हैं। सभी को सुखाकर अलग-अलग पीसा जाता है। इसी तरह अलग-अलग जड़ी-बूटियों से हिंग्वाष्टक, अजमोद, सितोपलादि, पंचारस, पुष्यानुग, महिला मित्र, शतावरी आदि चूर्ण तैयार करती हैं।


कोरबा। जंगल से एकत्रित की गई जड़ी-बूटियों को मशीन में पीसतीं महिलाएं।


कोरबा। कटघोरा संजीवनी मार्ट में औषधियों की बिक्री करतीं समूह की महिलाएं ● नईदुनिया

इकाई लगाने में वन विभाग ने की मदद, दिए छह लाख रुपये

औषधि तैयार करने के लिए महिला समूह ने इकाई लगाई है। कारोबार संचालित करने के लिए भंडारण ड्रम, ड्राई मशीन, पिसाई मशीन, इलेक्ट्रिक चलनी, पैकिंग मशीन आदि की खरीदारी की गई है। इसके लिए वन विभाग ने छह लाख की सहयोग राशि प्रदान की है। सरोज का कहना है कि आने वाले वर्ष में दो से ढाई करोड़ सालाना का कारोबार करने की योजना समिति ने बनाई है।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

महाराणा प्रताप की गलत जानकारी देने वाले शिलालेख हटाए गए

संवाद सूत्र, उदयपुर

- हल्दीघाटी में करीब चालीस साल पहले लगाए गए शिलालेख एएसआइ ने हटाए
- महाराणा की हार की दी गई थी जानकारी, जबकि उन्होंने अकबर को हराया था
- अगले महीने तक नए शिलालेख लगाए जाएंगे, जिसमें होगी राणा की जीत की गाथा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने हल्दीघाटी के रक्ततलाई में करीब चालीस साल पहले राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से लगवाए गए शिलालेख को हटवा दिया है, जिसमें निर्णायक हल्दीघाटी युद्ध को लेकर गलत तथ्य अंकित थे। अगले महीने तक यहां वास्तविक तथ्यों के साथ नए शिलालेख लगवाए जाएंगे।

एएसआइ जोधपुर मंडल के अधीक्षक बिपिन चंद्र नेगी के मुताबिक विवादास्पद कथन वाले शिलालेख हटवाए जाने संबंधी विभागीय आदेश की पालना में यह कार्रवाई की गई है। नए शिलालेख लिखवाए जाने से पहले हल्दीघाटी युद्ध को लेकर प्रामाणिक तथ्यों का अध्ययन जारी है। अगले महीने तक प्रामाणिक जानकारी के साथ नए शिलालेख लगवाए जाएंगे। पहले अंकित शिलालेखों में महाराणा प्रपात की सेना के पीछे हटने का उल्लेख था, जबकि इतिहासकारों व राजपूत समाज के कई संगठनों का कहना था कि हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की हार हुई थी।

राजपूत संगठनों ने किया स्वागत : राजपूत समाज सहित विभिन्न संगठनों ने विवादास्पद जानकारी वाले शिलालेख के हटाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लोगों को महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी युद्ध को लेकर गलत जानकारी दी जा रही थी, जिसे अब सुधारा जा रहा है। इस मुद्दे को पहली बार प्रामाणिकता से उठाने वाले उदयपुर के इतिहासकार प्रो. चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि पुस्तकों में हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत को स्वीकार कर प्रकाशित कर लिया गया, अब शिलालेख पर भी प्रामाणिक जानकारी मिले पाएगी।

2020 में कोरोना महामारी के बीच अमेरिका में ड्रग ओवरडोज के कारण रिकार्ड 93 हजार लोगों की मौत हुई है। कैलिफोर्निया विवि में मेडिसिन के प्रोफेसर डेनियल सिसकारोन के मुताबिक, 2019 में ड्रग ओवरडोज से 72 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई थी।

अफगानिस्तान में जंग कवर करने में गई भारतीय पत्रकार की जान

दुखद ▶ कंधार में तालिबान के हमले की चपेट में आ गए थे दानिश सिद्दीकी

दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की थी पत्रकारिता की पढ़ाई

काबुल, प्रेट्र : अफगानिस्तान में जंग कवर करने में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जान चली गई। समाचार एजेंसी रायटर के लिए काम करने वाले दानिश कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में तालिबान के हमले की चपेट में आ गए थे। पाकिस्तान सीमा से सटे इस जिले में पिछले कई दिनों से अफगान बलों और आतंकियों के बीच लड़ाई चल रही है, जिसे वह कवर कर रहे थे। पुलित्जर अवार्ड विजेता 38 वर्षीय दानिश दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने दिल्ली के ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद यहीं से 2007 में पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।

भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के जरिये कहा, 'गुरुवार रात कंधार में दोस्त दानिश सिद्दीकी की हत्या की दुखद खबर से गहरा दुख पहुंचा है। भारतीय पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता अफगान बलों के साथ थे। मैं उनसे दो हफ्ते पहले उनके काबुल रवाना होने से पहले मिला था। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है।' समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, सिद्दीकी ने बताया था कि वह लड़ाई कवर करने के दौरान हाथ में छर्रा लगने से घायल हो गए हैं। उनका इलाज किया गया है। वह जब उबर रहे थे तो तालिबान आतंकी स्पिन बोल्डक से पीछे हट गए थे। अफगान कमांडर ने बताया कि सिद्दीकी जब दुकानदारों से बात कर रहे थे, उसी दौरान तालिबान आतंकियों ने यहां दोबारा हमला कर दिया। वह हमले की चपेट में आ गए। सूत्रों के मुताबिक, तालिबान ने सिद्दीकी का शव इंटरनेशनल कमेटी आफ द रेड क्रास (आइसीआरसी) को सौंप दिया है। काबुल स्थित भारतीय दूतावास उनके शव को भारत भेजने के लिए अफगान अधिकारियों के संपर्क में है।


दानिश सिद्दीकी का फाइल फोटो। रायटर

2018 में मिला था पुलित्जर

सिद्दीकी ने टीवी पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह फोटो पत्रकार बन गए और वर्ष 2010 में रायटर से जुड़ गए थे। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या पर फोटोग्राफी के लिए 2018 में रायटर की टीम ने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। इस टीम में सिद्दीकी भी शामिल थे। उन्होंने दिल्ली दंगों को भी कवर किया था।

तीन साल में 33 पत्रकारों की मौत

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में वर्ष 2018 से 2021 के दौरान 33 पत्रकारों की जान गई। इनमें से 10 पत्रकारों की मौत 30 अप्रैल, 2018 को काबुल में एक आत्मघाती हमले में हुई थी।

दानिश की मौत पर नेताओं ने जताया दुख

दानिश सिद्दीकी की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी समेत तमाम नेताओं और प्रेस क्लब आफ इंडिया ने दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने कहा, 'मेरी संवेदनाएं दानिश के परिवार के साथ हैं।' मीडिया पेशेवरों के वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने भी दुख व्यक्त किया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी भारतीय पत्रकार की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, 'मैं रायटर के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत की खबर सुनकर दुखी हूं।'

> दानिश सिद्दीकी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड जीता था। उनकी मौत की खबर से गहरा दुख पहुंचा है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। -अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री

'...बैग में पासपोर्ट रखकर चलता हूं, क्या पता कब भागना पड़ जाए'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अफगानिस्तान में आतंकियों की कायराना हरकत का शिकार बने दानिश सिद्दीकी उच्चकोटि के फोटो पत्रकार थे। उनकी हत्या की खबर से यहां हर कोई गमजदा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने इसे पत्रकारिता और जामिया बिरादरी के लिए बड़ी क्षति बताया है। जामिया के शिक्षक व छात्र भी भावुक हैं।

दानिश सिद्दीकी की मौत की मनहूस खबर से जामिया नगर के गफ्फार मंजिल स्थित उनके आवास पर मातम पसर गया। पिता प्रो. अख्तर सिद्दीकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं। वह नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन के निदेशक रह चुके हैं। दानिश ने दो दिन पहले उनसे बात की थी और कहा था कि वह जल्द ही भारत वापस आएंगे। दानिश अपनी जर्मन मूल की पत्नी और दो बच्चों के साथ निजामुद्दीन स्थित आवास में रहते थे। उनके भाई उमर सिद्दीकी एलएंडटी में इंजीनियर हैं। बहन शाजिया चेन्नई में रहती हैं। दानिश के चाचा मुहम्मद असलम सिद्दीकी ने बताया कि वह और दानिश के पिता प्रो. अख्तर सिद्दीकी जुमे की नमाज पढ़कर घर लौटे ही थे कि बेटी ने एक वेबसाइट पर चल रही खबर उन्हें दिखाई। इसमें दानिश की मौत की बात लिखी थी। दानिश ने 2007 में जामिया के एजेके मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। दानिश को पत्रकारिता पढ़ाने वाली प्रो. शोहिनी घोष ने बताया कि हमें नहीं पता था कि वह फोटोग्राफी को अपना करियर बनाएंगे, लेकिन वह बेहतरीन फोटोग्राफर थे। दानिश अक्सर पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाने आते थे। कोरोना काल में आनलाइन पढ़ाते थे। आखिरी बार 26 अप्रैल को दानिश ने क्लास ली थी। छात्र बहुत खुश हुए थे।

एक दिन आनलाइन कक्षा के बाद छात्रों से मुखातिब होते हुए दानिश ने बताया था कि वह बैग में पासपोर्ट व अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लेकर चलते हैं। क्या पता कहीं से भागना पड़ जाए। दानिश ने जंग की रिपोर्टिंग के अपने अनुभव भी छात्रों से साझा किए थे।


दानिश सिद्दीकी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर खड़े शुभचिंतक और स्वजन। जगरण

अफगान बलों ने स्पिन बोल्डक को मुक्त कराने के लिए छेड़ा अभियान

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के साथ ही आतंकी संगठन तालिबान इस देश में अपना दायरा तेजी से बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में उसने हाल ही में पाकिस्तान से सटे कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले पर कब्जा कर लिया। अब इस जिले को तालिबान से मुक्त कराने के लिए अफगान बलों ने अभियान छेड़ा है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, 'अफगान सुरक्षा बलों ने स्थानीय बलों की मदद से स्पिन बोल्डक पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए अभियान शुरू किया है।' तालिबान आतंकियों ने पाकिस्तान की सीमा से सटे इस अहम शहर पर बुधवार को कब्जा कर लिया था। तालिबान ने बताया था कि उसने पाकिस्तान आने-जाने वाले अहम रास्तों और सीमा पर व्यापारिक शहर स्पिन बोल्डक पर कब्जा कर लिया है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, चश्मदीदों ने बताया कि दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई चल रही है। कई शव दिखाई दिए। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि देशभर में हालिया हिंसा में अफगान बलों के चार सैनिक की मौत हो गई। जबकि 63 तालिबान आतंकी मारे गए। अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से तालिबान ने कई जिलों पर कब्जा कर चुका है।

तालिबान की मदद कर रहा पाकिस्तान : समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी वायु सेना स्पिन बोल्डक और चमन जैसे सीमाई इलाकों में तालिबान को हवाई मदद मुहैया करा रही है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इससे इन्कार किया है।

अफगानिस्तान में शांति रक्षकों को भेजने की अपील : समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, महिला अधिकार समर्थकों ने संयुक्त राष्ट्र से अफगानिस्तान में शांति रक्षक बलों को भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है। इस बीच, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख रमीज अलकबरोव ने युद्ध प्रभावित इस देश को कुपोषण से मुकाबले में मदद के तौर पर 85 करोड़ डालर (करीब 6,300 करोड़) देने की अपील की है।


अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले पर तालिबान के कब्जे के बाद इससे सटे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी। एपी

बाढ़ ने बिगाड़ा यूरोप का हुलिया

- जर्मनी, बेल्जियम व नीदरलैंड जैसे देशों में स्थिति भयावह, 120 लोग मरे
- जर्मनी की स्थिति सबसे खराब, 1300 से अधिक लोग लापता


यूरोप के कई देश भीषण भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। जर्मनी के एरफस्टाट शहर में बने सिंकहोल में कई मकान समा गए। एपी


पश्चिमी जर्मनी में एहरेवीलर इलाके में बाढ़ से हुई बर्बादी का एक मंजर। एएफपी


बेल्जियम के लेग प्रांत में लोगों को बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। एपी

बर्लिन, एपी : यूरोपीय देशों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। जर्मनी, बेल्जियम व नीदरलैंड जैसे देशों में स्थिति भयावह है। नदियां और जलाशय उफान पर हैं। कई तटबंध टूट गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गईं, सैकड़ों वाहन बाढ़ में बह गए और इमारतें नष्ट हो गईं। पश्चिमी जर्मनी के कई हिस्सों और बेल्जियम में 120 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाढ़ में बहकर 1300 से अधिक लोग लापता हैं। अधिकारियों का कहना है राहत और बचाव कार्य जारी हैं लेकिन अभी भी बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाना बाकी है। फोन और इंटरनेट संपर्क टूट जाने की वजह से राहत कार्यों में दिक्कतें हो रही हैं।

जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टेमियर ने कहा, वह इस भयावह बाढ़ को देखकर स्तब्ध हैं। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित शहरों व कस्बों में मारे गए लोगों के परिजनों और बेघर होने वालों की मदद का आह्वान करते हुए कहा, समय की मांग है कि इस कठिन घड़ी में पूरा देश एकजुट हो। यह जरूरी है कि हम उन लोगों का साथ दें जो इस बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके हैं। रायटर के मुताबिक, पड़ोसी देश नीदरलैंड में कई शहर और गांव डूब चुके हैं। लिमबर्ग प्रांत में हजारों लोगों को अपने घर छोड़ देने को कहा गया है। आपात सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं। बेल्जियम के कई प्रांतों में सरकार ने यात्रा न करने की हिदायत जारी की है। बेल्जियम की सहायता के लिए फ्रांस ने 40 सैनिक और एक हेलीकाप्टर भेजा है। इधर एपी के अनुसार, जर्मन राज्य राइनलैंड-पैलेटिनेट के प्रशासन के मुताबिक, बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें वह 12 लोग भी शामिल हैं जो दिव्यांगों के सहायता केंद्र में रहते थे। पड़ोसी राज्य नार्थ राइन-वेस्टफैलिया में 43 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। साउथ-वेस्ट कोलोन के इर्टस्टैड कस्बे में भी कई लोगों की मौत हुई और उनके घर बह गए हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने गुरुवार रात करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला है, लेकिन अभी भी वहां 15 लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक, बाढ़ के चलते जर्मनी में कम से कम 1300 लोग लापता हैं। वहीं, बल्जियन में मृतक संख्या बढ़कर 12 हो गई है और पांच लोग लापता हैं। विश्व मौसम संगठन की प्रवक्ता क्लेयर नूलिस ने कहा कि पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में दो महीने में होने वाली बरसात दो दिनों में ही हो गई है। राइनलैंड-पैलेटिनेट राज्य के गर्वनर मालू ड्रेयर ने कहा कि बाढ़ को दोष देना जल्दबाजी होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है।

सुरक्षा परिषद के सुधारों और कोविड पर श्रृंगला और गुतेरस में गहन वार्ता

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र: भारत के विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने क्षेत्रीय मुद्दों से लेकर अफगानिस्तान, म्यांमार, पर्यावरण परिवर्तन, सुरक्षा परिषद में सुधारों और विश्व में कोविड-19 के हालात पर गहन विचार-विमर्श किया।

श्रृंगला 14 से 16 जुलाई तक न्यूयार्क की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह यहां सुरक्षा परिषद के तहत इस माह होने वाली फ्रेंच प्रेसिडेंसी की उच्चस्तरीय बैठक में भाग ले रहे हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद अगस्त के महीने में 15 देशों की सुरक्षा परिषद की शक्तिशाली अध्यक्षता के लिए भारत को तैयार करना है। गुरुवार की दोपहर को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतेरस का आहान किया था। साथ ही उन्हें दोबारा इस पद के लिए चुने जाने पर बधाई दी थी।


हर्ष वर्धन श्रृंगला। फाइल

- विदेश सचिव और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अफगानिस्तान व म्यांमार के हालात पर भी की बातचीत
- अगस्त में भारत की अध्यक्षता की तैयारियों पर थामस ग्रीनफील्ड से भी की अहम चर्चा


एंतोनियो गुतेरस। फाइल

भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि श्रृंगला ने सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता के लिए अगस्त माह की भारत की वरीयताओं जैसे सामुद्रिक जल क्षेत्र की सुरक्षा, शांति अभियान और आतंकवाद विरोधी अभियानों को सुनिश्चित किया और इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव से चर्चा की। बैठक के दौरान अफगानिस्तान और म्यांमार के हालात, पर्यावरण परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विश्व में कोविड-19 के हालात पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। गुतेरस ने कोरोना से जंग में भारत सरकार और भारतीयों के प्रयासों की सराहना की। गुतेरस ने यह भी इच्छा जताई की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आगामी अध्यक्षता के लिए भारत सबसे बेहतर साबित हो। श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थामस ग्रीनफील्ड के साथ भारत-अमेरिका के बीच बहुआयामी सहयोग पर बातचीत की।

अमेरिका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाक ने बनाया नया क्वाड समूह

प्रथम पृष्ठ से आगे

समाचार एजेंसी 'एएनआइ' के मुताबिक, अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने अफगान शांति प्रक्रिया और क्षेत्र में स्थायित्व व कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक नया क्वाडिलेटरल डिप्लोमैटिक ग्रुप बनाया है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सभी पक्षों ने भविष्य में सहयोग पर चर्चा के लिए आगामी महीनों में बैठक करने पर सहमति व्यक्त की है।

उज्बेक राष्ट्रपति ने किया चरक और सुश्रुत का जिक्र, जयशंकर ने दिया धन्यवाद: सम्मेलन में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जीयोयेव ने अपने भाषण में मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच के ऐतिहासिक संबंधों का हवाला दिया और इस क्रम में उन्होंने चरक, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त का नाम लिया जिनका असर आज भी मध्य एशियाई देशों में देखने को मिलता है। इस उदाहरण के लिए जयशंकर ने बाद में ट्विटर पर उज्बेकी राष्ट्रपति को धन्यवाद भी कहा।

अफगान उपराष्ट्रपति ने भी लगाया था पाक वायुसेना पर तालिबान की मदद का आरोप : समाचार एजेंसी 'प्रेट्र' के मुताबिक, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने भी गुरुवार को ट्वीट कर कहा था, 'पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान सेना और वायुसेना को आधिकारिक चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोल्दक इलाके से तालिबान को खदेड़ने के किसी भी कदम का पाकिस्तानी वायुसेना जवाब देगी। अब पाकिस्तानी वायुसेना कुछ इलाकों में तालिबान को करीबी सहायता दे रही है।' हालांकि पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने इस आरोप का खंडन किया है।

कोरोना को लेकर चीन में फिर जांच करना चाहता है डब्ल्यूएचओ

- शीर्ष वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रस्ताव पर बीजिंग की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया
- डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने एक दिन पहले कहा था, शुरुआती आंकड़े नहीं मिलने से पहली जांच में आई बाधा

जेनेवा, रायटर : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस के मूल का पता लगाने के लिए चीन और वुहान की प्रयोगशाला में दोबारा जांच का प्रस्ताव रखा है। राजनयिकों के मुताबिक चीन की तरफ से इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को सदस्यों देशों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में यह प्रस्ताव रखा था। इससे एक दिन पहले ही घेब्रेयेसस ने कहा था कि चीन में कोरोना वायरस के प्रसार के शुरुआती दिनों के आंकड़े नहीं मिलने से पहली जांच में बाधा आई थी।

डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व वाली एक टीम ने मार्च में वुहान का दौरा किया था। टीम के सदस्य कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चार हफ्ते तक वहां जांच पड़ताल करते रहे। इस दौरान चीन के शोधकर्ता उनके साथ साये की तरह बने रहते थे। बाद में संयुक्त रिपोर्ट में टीम ने किसी अन्य जानवरों के जरिये चमगादड़ों से मानव में कोरोना वायरस के फैलने की आशंका जताई थी।

दोबारा जांच की मांग की गई : अमेरिका समेत कई देशों को इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं हुआ और दोबारा जांच की मांग की गई, खासकर वुहान की प्रयोगशाला की जहां चमगादड़ों पर प्रयोग किया जाता है। राजनयिकों ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रस्ताव में सिर्फ चीन में दोबारा जांच की बात कही गई है और वह भी खासकर वुहान के आसपास की प्रयोगशालाओं की।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी चुनौतियों का सामना करेगा अमेरिका का ईगल

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने क्वाड देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने और चीन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया है। 'एन्श्योरिंग अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट : ईगल' नामक इस कानून में कई अहम प्रविधान शामिल हैं जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौतियों से मुकाबले में अमेरिका की कूटनीति और नेतृत्व को मजबूती देंगे। सांसद जोकिन कास्त्रो ने कहा, 'मैंने अक्सर कहा है कि चीन के प्रति अमेरिका की नीति यह होनी चाहिए कि जब जरूरी हो तो प्रतिस्पर्धा में शामिल हों, देश में हमारे स्रोतों को मजबूत करें और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, कानूनों, मानदंडों को मजबूत करके चीन को बताएं कि 'धोखे' का क्या अर्थ है।'

उन्होंने कहा, 'ईगल कानून हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी सरकार को साधन व दिशा देगा। विधेयक उस नीति को स्थापित करता है जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत राष्ट्रपति के कैबिनेट के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।'

विधेयक में अमेरिकी सरकार से हिंद-प्रशांत के इस महत्वपूर्ण हिस्से में सहयोगियों के साथ भागीदारी को मजबूत करने का आग्रह किया गया है। इसमें अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच लोगों से संपर्क को मजबूत करने के प्रविधान शामिल हैं। यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति से 'नियम 50' को रद करने का आहान करता है जो प्रतिस्पर्धा करते समय खिलाड़ियों द्वारा राजनीतिक अभिव्यक्ति पर रोक लगाता है। यह कानून हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा मूल्यों और हितों के साथ प्रमुख भागीदार अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्वाड अंतर-संसदीय कार्य समूह की स्थापना का समर्थन करता है।

हांगकांग में हालात बिगड़ रहे : बाइडन



वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि हांगकांग में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीन की सरकार उन प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रही है, जिसका उसने वादा किया था। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में बाइडन ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन हांगकांग के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी करने वाला है। हांगकांग में जो हो रहा रहा है वह समझना आसान भी है और कठिन भी है।

अमेरिका के आधे राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के नए केस

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका में कोरोना महामारी फिर बढ़ने लगी है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में नए मामलों में उछाल दर्ज किया जा रहा है। देशभर में बीते 24 घंटे में 31 हजार 815 नए केस पाए गए। दो माह बाद एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में नए संक्रमित पाए गए हैं। यहां डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ रहा है।

अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) के अनुसार, अमेरिका में कोरोना का डेल्टा वैरिएंट हावी होता जा रहा है। बीते दो हफ्ते में जितने मामले पाए गए, उनमें 50 फीसद से ज्यादा डेल्टा वैरिएंट के थे। 55.7 फीसद अमेरिकियों को कोरोना रोधी वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। कोरोना महामारी की दो लहरों का सामना कर चुके अमेरिका में फिर संकट गहराने लगा है।

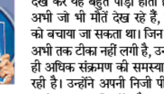
ब्रिटेन में डेल्टा के मिले 36 हजार मामले : समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, ब्रिटेन में डेल्टा वैरिएंट के साप्ताहिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते हफ्ते यहां 36 हजार 800 नए मामले पाए गए। इससे पहले वाले हफ्ते में डेल्टा वैरिएंट के 54 हजार 268 केस मिले थे। भारत में सबसे पहले पाया गया यह वैरिएंट बेहद संक्रामक बताया जाता है।

रूस में एक दिन में सर्वाधिक मौतें : रूस में बीते 24 घंटे में कोरोना से 799 पीड़ितों की मौत हो गई। एक दिन में मरने वालों की यह सर्वाधिक संख्या बताई जा रही है। इस दौरान 25 हजार 704 नए केस पाए गए। यहां भी डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ गया है।

कोविड से परिवार के 10 सदस्यों को खोया : डा. विवेक मूर्ति

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के सर्जन जनरल डा. विवेक मूर्ति ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते वह अपने परिवार के 10 सदस्यों को गंवा चुके हैं। उनके परिवार के यह सदस्य अमेरिका और भारत दोनों ही जगहों में रहते थे। उन्होंने इसीलिए अमेरिकियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वह इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगाएं।

व्हाइट हाउस में गुरुवार को टीकाकरण को लेकर अफवाहों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी चिकित्सक ने लोगों से आग्रह किया कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां साझा करने से पहले उचित स्रोत को जांच लें। ताकि बाकी सभी लोगों को यह सुनिश्चित करने में परेशानी नहीं हो कि विश्वसनीय और वैज्ञानिक स्रोतों से ही यह जानकारी दी गई है। मूर्ति ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि अभी तक 16 करोड़ अमेरिकियों का टीकाकरण हो चुका है। लेकिन हम अभी तक इस समस्या से अब तक पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं। करोड़ों अमेरिकियों को अभी भी वैक्सीन नहीं लगी है। इस पद पर दोबारा आसानी होने वाले 44 वर्षीय विवेक मूर्ति ने कहा कि निजी तौर पर उन्हें देख कर यह बहुत पीड़ा होती है कि हम अभी जो भी मौतें देख रहे हैं, उन सभी को बचाया जा सकता था। जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगी है, उन लोगों में ही अधिक संक्रमण की समस्या देखी जा रही है। उन्होंने अपनी निजी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि मेरे जैसा व्यक्ति हर दिन यह मनाता है कि उनके दस प्रियजन जो अब कोविड के कारण इस दुनिया में नहीं हैं, अगर उन्हें समय रहते वैक्सीन लग जाती तो उनकी जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि दो छोटे बच्चों का पिता होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को तो कम उम्र के कारण अभी वैक्सीन नहीं लग सकती है। लेकिन हम जानते हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा हम पर निर्भर है, इसलिए हमारा टीका लगवाना बेहद जरूरी है।



व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में टीकाकरण को लेकर अफवाहों के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते डा. विवेक मूर्ति। एएफपी

निश्चिंत रहें, टीका असरदार है

ब्रिटेन में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पहली फरवरी से 21 जून के बीच कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट से संक्रमित 257 लोगों की जान गई। इसमें से 163 यानी 63 फीसद से ज्यादा लोग ऐसे थे, जिन्हें टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी थी। पहली नजर में इस आंकड़े ने सबको डरा दिया, क्योंकि जान गंवाने वालों में टीका लगवा चुके लोगों की संख्या ज्यादा है। यूनिवर्सिटी आफ बाथ के क्रिश्चियन येट्स ने कहा कि असल में इसमें चिंता बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। न ही ये आंकड़े टीके पर सवाल उठाते हैं। बस जरूरत है कि आंकड़ों को सही संदर्भ में देखा जाए। सच यही है कि टीका बचाव में कारगर है और हर व्यक्ति को टीका लगवाना चाहिए।



आंकड़ों की सही तस्वीर समझना जरूरी

इन आंकड़ों को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि 100 फीसद लोगों का टीकाकरण हो चुका है। यह ज्ञात तथ्य है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकता है। 100 फीसद टीकाकरण के बाद भी कुछ लोग संक्रमित होंगे और उनमें से कुछ की जान जाएगी। ऐसे में जाहिर है कि जान गंवाने वालों में 100 फीसद लोग वही होंगे, जिन्हें टीका लग चुका है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि टीका बीमारी से बचाव नहीं करता है।

उम्र के साथ बढ़ता जाता है संकट

उम्र में हर सात साल का अंतर कोरोना के कारण जान जाने का खतरा करीब दोगुना कर देता है। यानी 35 साल वाले की तुलना में 70 साल के व्यक्ति में कोरोना के कारण जान जाने का खतरा करीब 32 गुना बढ़ जाता है। टीके के बाद संक्रमण गंभीर होने और जान जाने का खतरा तो कम होता है, लेकिन उम्र के कारण इस खतरे का अंतर बना रहता है।

टीका 20 गुना तक कम करता है खतरा

पीएचई का डाटा बताता है कि टीके की दोनों डोज डेल्टा वैरिएंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को करीब 96 फीसद कम करती है। टीका मौत के खतरे को और भी कम करता है। हालांकि इसे यदि इसी अनुपात में माना जाए, तब भी टीके की दोनों डोज जान जाने के खतरे को 20 गुना तक कम कर देती है। इससे समझा जा सकता है कि दोनों डोज के बाद भी 70 साल के बुजुर्ग में बिना टीका लगवाए 35 साल के युवा की तुलना में मौत का खतरा ज्यादा ही रहेगा। ब्रिटेन में भी टीकाकरण में बुजुर्गों को प्राथमिकता समूह में रखा गया था। इसी कारण से मौत के आंकड़ों में टीका लगवा चुके लोगों की संख्या ज्यादा लग रही है। (इनपुट : प्रेट्र)



परिवार सबसे जरूरी है और उसके बाद मेरा मानसिक स्वास्थ्य। मुझे वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से हटने का दुख नहीं है।
— डेनियल सैम्स, आलराउंडर, आस्ट्रेलिया

लाहिड़ी बारबासोल चैंपियनशिप में संयुक्त 31वें स्थान पर

निकलसविले, प्रेट्र : भारत के अनिर्बान लाहिड़ी चार अंडर 68 के स्कोर के साथ बारबासोल गोल्फ चैंपियनशिप पीजीए टूर टूर्नामेंट के पहले दौर के बाद संयुक्त 31वें स्थान पर हैं। खराब मौसम के कारण दो बार खेल रोकना पड़ा और बाद में स्थगित कर दिया जब 30 खिलाड़ियों का पहले दौर का मुकाबला बाकी था। ब्रायन स्टुअर्ड छह अंडर 64 के स्कोर के साथ शीर्ष पर हैं।



बुलेट चबाने जैसा श्रीलंका क्रिकेट का हाल : रसेल

- श्रीलंका मुख्य टीम से मजबूत भारत की बी टीम
- पहला एकदिवसीय रविवार को खेला जाएगा

श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी रसेल अर्नाल्ड का मानना है कि सीनियर खिलाड़ियों के एक साथ जाने के कारण श्रीलंका क्रिकेट का स्तर गिरता चला गया, जिसकी भरपाई करने के लिए अभी भी टीम प्रयासरत है। हालांकि टीम खेलती जा रही है लेकिन जीत नहीं रही। ऐसे में उसका हाल बुलेट (बंदूक की गोली) चबाने जैसा है। श्रीलंका और भारत के खिलाफ वनडे सीरीज रविवार से शुरू होगी। इसको लेकर **रसेल अर्नाल्ड** से **अभिषेक त्रिपाठी** ने खास बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश :



साक्षात्कार

दोनों टीमों की तुलना करें तो कौन सी टीम और क्यों मजबूत नजर आ रही है?

इस समय की बात करें तो मेरे हिसाब से भारत का पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि उनके पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपना खेल जानते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है। जबकि युवा खिलाड़ियों को भी पता है कई सीनियर खिलाड़ी इंग्लैंड में हैं तो वे इस मौके का जमकर फायदा उठाएंगे। वहीं श्रीलंका क्रिकेट अभी भी अपनी राह तलाश रहा है इसलिए मेरे हिसाब से भारत की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है।

राहुल द्रविड़ को श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम का कोच बनाकर भेजा गया है, इस पर आपकी क्या राय है?

द्रविड़ काफी दिनों से युवा खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें अंडर-19 के भी खिलाड़ियों को सिखाते हुए देखा है। उनके स्वभाव में गजब की शांति है जो युवाओं को पसंद है। वह ना सिर्फ क्रिकेट की बारीकियां सिखाते हैं बल्कि जेंटलमैन (यानी अच्छा आदमी) कैसे बनना है, वह भी सिखाते हैं। कोई विदेशी भी अगर उनसे बात करता है तो वह उसे भी सिखाते हैं। श्रीलंका क्रिकेट को भी ऐसे ही काम करना चाहिए।

● इस सीरीज के लिए आप श्रीलंका टीम को कैसे देखते हैं?

-यह काफी रोचक है क्योंकि पिछले कुछ सालों से तो श्रीलंका क्रिकेट टीम की कोई दिशा नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से नया कप्तान है। बहुत कुछ उथल-पुथल चोटों के चलते भी जारी है। श्रीलंका अभी भी सही राह की तलाश में हैं और उसके लिए कई फैसले भी ले रहा है। कुछ सीनियर खिलाड़ियों के होते हुए भी उन्हें क्वालिफिकेशन (टी-20 विश्व कप) में जाना पड़ा, जबकि टीम की रैंकिंग 8 या 9 के पास रही। यह कठिन फैसला है कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है। आपको अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को भी मौका देना होगा। इस लिहाज से श्रीलंका के लिए यह सीरीज काफी कठिन होने वाली है।

भारत-श्रीलंका मैच का पहला वनडे रविवार को दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। इसका प्रसारण सोनी टेन-3 पर होगा

● अर्जुन रणतुंगा ने श्रीलंका क्रिकेट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत की बी टीम से खेलना खराब फैसला है?

-मेरे विचार से यह भारतीय टीम काफी मजबूत है और हर देश को भारत की तरह बनना चाहिए कि वह एक समय में दो इतनी मजबूत टीम बनाकर भेज सकता है। भारत की इस टीम में काफी अनुभवी खिलाड़ी भी हैं तो कई शानदार युवा खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं टीम में काफी गहराई भी है तो एक समय में इस तरह की दो टीमों को बनाने की योग्यता भारतीय क्रिकेट के पास है इसकी मैं सराहना करता हूं। कोरोना महामारी के कारण जिस तरह के हालात हैं, ऊपर से बायो-बबल भी है। ऐसे में दो टीमें बनाने से खिलाड़ियों को आराम भी मिल रहा है। यह अच्छी चीज है।

● आप श्रीलंका के लिए एक फिनिशर का रोल अदा करते थे। ऐसे में आपको वर्तमान श्रीलंका टीम में जैसा कोई खिलाड़ी नजर आ रहा है?

जिस तरह से टीम पिछले कुछ महीनों में खेली है उससे साफ नजर आता है कि खिलाड़ी खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। क्रिकेट हो या फिर जीवन, उसमें छोटे-छोटे लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है और उन्हें पाकर ही आप अंत तक पहुंच सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी खिलाड़ी स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे और ना ही बल्लेबाजी में गियर शिफ्ट कर पा रहे थे। मेरे विचार से एंजेलो मैथ्यूज के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी श्रीलंका का खिलाड़ी क्रिकेट के खेल को पढ़ पा रहा है।

● श्रीलंका टीम में एक समय महेला जयवर्धने, कुमार संगाकारा, सनत जयसूर्या, चमिंडा वास, लसित मलिंगा व आप थे, अब टीम में एसे मजबूत स्तंभ नहीं नजर आते हैं। ऐसा हाल क्यों हुआ?

1996 विश्व कप के समय कई शानदार खिलाड़ी जैसे मर्वन अट्टापट्टू व सनत जयसूर्या आए। इसके बाद जयवर्धने, दिलशान और संगाकारा जब टीम में आए उस समय सीनियर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे तो इन लोगों ने निडर होकर अपने शुरुआती दिनों में क्रिकेट खेला। 2007 विश्व कप में युवा खिलाड़ियों के तौर पर मलिंगा, दिलहारा फर्नांडो और तिलकरत्ने दिलशान जैसे शानदार विकल्प मौजूद थे। अभी आप देखें तो ऐसे युवा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि श्रीलंका क्रिकेट पीछे होता चला गया। इसमें एक कारण यह भी कि जयवर्धने और संगाकारा जैसे खिलाड़ी बढ़ती उम्र के साथ एक ही समय में टीम से बाहर हुए और युवा खिलाड़ियों से आप उन्ही की तरह अपेक्षाएं करने लगे।

● साल 2017 के बाद से श्रीलंका के करीब 9 से 10 वनडे कप्तान बदले गए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ?

यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है कि पिछले कुछ सालों से जो जीत की राह हम खोज रहे हैं उसमें इतने बदलाव करते चले गए। जब आपको नतीजे नहीं मिल रहे होते हैं तो आप बदलाव करते चले जाते हैं। दरअसल, श्रीलंका को इंग्लैंड और भारत के जैसा कोई खिलाड़ी ही नहीं मिला जो लगातार शानदार प्रदर्शन करके टीम के मनोबल को उठा पाता और उसे आगे ले जा पाता। टीम की सफलता के लिए कप्तान का नियमित प्रदर्शन करना बहुत आवश्यक है। जिससे पूरी टीम पर असर पड़ता है। ऐसा खिलाड़ी न मिलने के कारण कप्तान बदलते गए और यह बहुत ही चिंताजनक बात है।

टी-20 विश्व कप में महामुकाबले की एंट्री

आइसीसी ने किए पूल घोषित, भारत और पाकिस्तान की टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : बेशक भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट बंद हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने इन दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच महामुकाबले के लिए एक और मंच तैयार कर दिया है। आइसीसी ने 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप के पूल घोषित कर दिए हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। वनडे विश्व कप 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी।

टी-20 विश्व कप के ग्रुप मुकाबले दो दौर में खेले जाएंगे, जिन्हें राउंड-1 और सुपर-12 नाम दिए गए हैं। राउंड-1 में आठ टीमें होंगी, जिनमें श्रीलंका और बांग्लादेश ने स्वतः क्वालीफाई किया है, जबकि छह अन्य टीमों ने आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप क्वालीफायर 2019 के जरिये अपने स्थान पक्के किए हैं। इन आठों टीमों को दो ग्रुपों में बांटा गया है, जिनमें ग्रुप-ए और ग्रुप-बी शामिल हैं। ग्रुप-ए में श्रीलंका के साथ आयरलैंड, नीदरलैंड्स और नामीबिया हैं, ग्रुप-बी में बांग्लादेश के साथ ओमान, पपुआ न्यू गिनी (पीएनजी) और स्काटलैंड की टीमें हैं। इन दोनों ग्रुप से दो-दो टीमें शीर्ष टीमें सुपर-12 में प्रवेश करेंगी।

सुपर-12 में भी दो ग्रुप होंगे, जिन्हें ग्रुप-1 और ग्रुप-2 नाम दिए गए हैं। दोनों ग्रुपों में छह-छह टीमें शामिल होंगी। ग्रुप-1 में गत विजेता वेस्टइंडीज, 2010 की चैंपियन इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका हैं, जबकि राउंड-1 से दो टीमें इस ग्रुप में जुड़ेंगी। ग्रुप-दो में भारत और पाकिस्तान को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है। इन चार टीमों के अलावा राउंड-1 से दो टीमें इस ग्रुप में भी जुड़ेंगी। आइसीसी के अनुसार, सुपर-12 के ग्रुप को 20 मार्च 2021 तक की टीम रैंकिंग के आधार पर चुना गया है।

टी-20 विश्व कप के मैचों का कार्यक्रम अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है। टूर्नामेंट पहले भारत में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के चलते इसे बाहर कराने का फैसला किया गया। आइसीसी के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी ज्योफ अलार्डिस ने बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के पहुंचने के बाद मस्कट में ड्रा निकाला। वर्ष 2016 के बाद पहली बार टी-20 विश्व कप का आयोजन होना है। पिछली बार कोलकाता में हुए फाइनल में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया था।



> कोविड-19 द्वारा उत्पन्न हुई बाधा को देखते हुए हमने कट-आफ तारीख जितना संभव हो उतना टूर्नामेंट के करीब रखी है, ताकि हम ग्रुप निर्धारित करने वाली रैंकिंग में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट शामिल कर सकें। इसमें कोई शक नहीं कि तीन महीनों के अंदर जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो हमें काफी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट देखने को मिलेगा।
> **ज्योफ अलार्डिस, कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी, आइसीसी**

यहां होंगे टी-20 विश्व कप के मैच
- दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई
- शेख जाएद स्टेडियम, अबूधाबी
- शारजाह स्टेडियम, शारजाह
- ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड, मस्कट

> आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप की मेजबानी से ओमान को विश्व क्रिकेट दायरे में लाते हुए देखना अच्छा है। इससे काफी युवाओं को इस खेल में दिलचस्पी लेने में मदद मिलेगी। हम जानते हैं कि यह दुनिया के इस हिस्से के लिए विश्व स्तरीय टूर्नामेंट होगा। दोनों ग्रुप में खेल के छोटे प्रारूप की काफी प्रतिस्पर्धी टीमें हैं। **सौरव गांगुली, बीसीसीआइ अध्यक्ष**

आइसीसी टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान

साल	टूर्नामेंट	परिणाम
1992	वनडे विश्व कप	भारत 43 रन से जीता
1996	वनडे विश्व कप	भारत 39 रन से जीता
1999	वनडे विश्व कप	भारत 47 रन से जीता
2003	वनडे विश्व कप	भारत छह विकेट से जीता
2004	चैंपियंस ट्राफी	पाकिस्तान तीन विकेट से जीता
2007	टी-20 विश्व कप	भारत बाल आउट में जीता
2007	टी-20 विश्व कप	भारत पांच रन से जीता
2009	चैंपियंस ट्राफी	पाकिस्तान 54 रन से जीता
2011	वनडे विश्व कप	भारत 29 रन से जीता
2012	टी-20 विश्व कप	भारत आठ विकेट से जीता
2013	चैंपियंस ट्राफी	भारत आठ विकेट से जीता
2014	टी-20 विश्व कप	भारत सात विकेट से जीता
2015	वनडे विश्व कप	भारत 76 रन से जीता
2016	टी-20 विश्व कप	भारत छह विकेट से जीता
2017	चैंपियंस ट्राफी	भारत 124 रन से जीता
2017	चैंपियंस ट्राफी	पाकिस्तान 180 रन से जीता
2019	वनडे विश्व कप	भारत 89 रन से जीता

परेरा भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर, शनाका बने कप्तान

कोलंबो, प्रेट्र : भारत के खिलाफ 18 जुलाई से शुरू हो रही छह मैचों (तीन वनडे व तीन टी-20) की सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका ने दासुन शनाका की अगुआई में 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

शनाका पिछले चार साल में श्रीलंका के 10वें कप्तान हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे एवं खेल मंत्री नमल राजपक्षे से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका क्रिकेट ने टीम की घोषणा की। कुशल परेरा घुटने में चोट कारण टीम का हिस्सा नहीं है। बायें हाथ के तेज गेंदबाज बिनुरा फर्नांडो को भी टखने में चोट लगी है। वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए है।

भुवी बोले, मेरे लिए कोई प्राथमिकता नहीं : भुवनेश्वर कुमार तीनों प्रारूपों में से किसी एक को प्राथमिकता नहीं देना चाहते, लेकिन वह भविष्य में एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट खेलने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, भले ही यह लाल गेंद का क्रिकेट हो या फिर सफेद गेंद का। अगर मैं लाल गेंद के क्रिकेट के लिए चुना जाता हूं व टीम का हिस्सा होता हूं तो मैं निश्चित रूप से योगदान देने की कोशिश करूंगा। मैं सभी प्रारूपों के लिए तैयारी पर काम कर रहा हूं।'

मेसी आधे वेतन पर बार्सिलोना से जुड़ेंगे

बार्सिलोना, एपी : अर्जेंटीना के लियोन मेसी पांच और साल (2026 तक) के लिए बार्सिलोना में बने रहेंगे। हालांकि अब उनका वेतन पहले से आधा होगा। मेसी का करार 30 जून को खत्म हो चुका था। पिछले करार में मेसी को प्रति सत्र 16 करोड़ डालर (करीब 1215 करोड़ रुपये) की रकम मिलती थी। अब उन्हें करीब 607 करोड़ रुपये ही मिलेंगे।



भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे शुक्रवार को मुंबई में अपनी महिला मित्र अंजुम खान के साथ शादी के बंधन में बंधे। यह शादी हिंदू-मुस्लिम दोनों रीति-रिवाज से हुई ● ट्विटर

सुमित नागल को मिला ओलिंपिक टिकट

ओलिंपिक डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने शुक्रवार को टोक्यो ओलिंपिक की पुरुष सिंगल्स स्पर्धा का टिकट हासिल किया। बड़े पैमाने पर कई खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे 144वीं रैंकिंग वाले भारत के शीर्ष खिलाड़ी सुमित को ओलिंपिक में सीधे रैंकिंग के आधार पर प्रवेश मिल गया। इसके तुरंत बाद ही अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) ने दिविज शरण का नामांकन वापस लेकर पुरुष डबल्स प्रतियोगिता के लिए रोहन बोपन्ना के साथ तुरंत सुमित की जोड़ी बनाई, क्योंकि सिंगल्स खिलाड़ियों को डबल्स ड्रा में भी प्रवेश करने में प्राथमिकता मिल रही थी।

नागल ने कहा, 'मुझे पता था कि यह (कट-आफ) काफी गिरने वाला है। किसी भी अन्य ओलिंपिक की तुलना में इस साल चीजें अलग हैं। बहरहाल, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है।'



सुमित नागल ● फाइल फोटो, एएफपी

ओलिंपिक खेलेंगे जोकोविक

बेलग्रेड, प्रेट्र : विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविक ने कहा कि वह सर्बिया के लिए टोक्यो ओलिंपिक खेलेंगे जिससे गोल्डन स्लैम का उनका सपना पूरा हो सकता है। जोकोविक ने ट्वीट किया, टोक्यो की टिकट करा ली है। ओलिंपिक में सर्बिया के लिए खेलना गर्व की बात है। इस साल आस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने वाल जोकोविक ओलिंपिक में सिंगल्स का स्वर्ण व उसके बाद यूएस ओपन जीत लेते हैं तो गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले वह पहले पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे।

भारतीय ओलिंपिक टीम का आधिकारिक पार्टनर बना स्पोर्ट्स फार आलः भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) ने स्पोर्ट्स फार आल (एसएफए) प्राइवेट लिमिटेड के साथ टोक्यो ओलिंपिक के लिए भारतीय दल के एक प्रायोजक के तौर पर करार किया है। करार के तहत कंपनी ने आइओए को एक करोड़ रुपये देने का वादा किया है। आइओए सचिव राजीव मेहता ने कहा, 'एसएफए प्राइवेट लिमिटेड ने प्रायोजन राशि के तौर पर एक करोड़ रुपये देने की पुष्टि की है। अपने प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफार्म और मेगा-स्केल के साथ, स्कूल और कालेज स्तर पर आन-ग्राउंड मल्टी-स्पोर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा।'



1976
खाली हाथ लौटी भारतीय हॉकी टीम

टोक्यो ओलिंपिक



06 दिन शेष

यह पहले ओलिंपिक थे, जिन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कुछ अफ्रीकी अन्य देशों ने इन खेलों में भाग नहीं लिया। यह पहला मौका था, जब भारतीय हाकी टीम ओलंपिक से खाली हाथ लौटी। चैंपियन टीम पोडियम फिनिश करने में भी चूक गई।

नहीं मिला सोना

मेजबान कनाडा पदक तालिका में 27वें स्थान पर रहा। उसने 11 पदक जीते, लेकिन इसमें एक भी स्वर्ण पदक नही था। वह अकेला ऐसा मेजबान देश बना जो एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत सका।

पूर्वी जर्मनी ने चौंकाया

पूर्वी जर्मनी ने सभी अनुमानों को धता बताते हुए पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। उसके ऊपर आरोप लगते रहे कि वहां के एथलीट प्रदर्शन सुधारने के लिए मादक द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं।

17 जुलाई-01 अगस्त

6084 एथलीट | 92 देश | 21 खेल 198 मुकाबले

ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जापानी निशानेबाजी टीम के सदस्य तारो असो 32 साल बाद अपने देश के प्रधानमंत्री बने।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
सोवियत संघ	49	125
पूर्वी जर्मनी	40	90
अमेरिका	34	94
प. जर्मनी	10	39
जापान	09	25

भारतीय प्रदर्शन : 1976 में तो भारतीय टीम सातवें स्थान पर रही और ओलंपिक के इतिहास में पहली बार खाली हाथ लौटी। 1928 में पदार्पण करने वाली भारतीय हाकी टीम ने 1956 तक लगातार छह स्वर्ण जीतकर अपना परचम लहराया था। बात सिर्फ पदक की नहीं, बल्कि भारतीय पारंपरिक हाकी के उस जादू की थी जो कभी सिर चढ़कर बोलता था। लेकिन घास के मैदान की विदाई और एस्ट्रो टर्फ के आगमन के बाद वह जादू मानो खो गया। इस बदलाव का फायदा न्यूजीलैंड को मिला, जो स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा।



1980
12 साल बाद फिर फहराया तिरंगा

पहली बार सोवियत संघ में ओलिंपिक खेलों का आयोजन हुआ। पूर्वी यूरोप के पहले देश की मेजबानी में यह खेल अमेरिकी बहिष्कार से चर्चा में रहे। भारतीय हाकी टीम ने 12 वर्ष बाद फिर पीला तमगा जीतकर मास्को में तिरंगा फहराया।

झलकियां
- सबसे अधिक महिला खिलाड़ियों (21 प्रतिशत) ने हिस्सा लिया। अब तक के सबसे मुकाबले (203) हुए
- पहली बार ओलिंपिक झंडा स्थानांतरण कार्यक्रम समापन समारोह में हुआ। अगले मेजबान के रूप में अमेरिकी झंडे के बजाय लांस एंजिलिस शहर के झंडे को लहराया गया। इसी तरह ओलिंपिक झंडे को लांस एंजिलिस के मेयर को देने की बजाय अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के अध्यक्ष को सौंपा गया

19 जुलाई-03 अगस्त

5179 एथलीट | 80 देश | 21 खेल 203 मुकाबले

उद्घाटन के बाद हटा लाइबेरिया

इस आयोजन में 81 देशों ने हिस्सा लेने का निश्चय किया, लेकिन लाइबेरिया ने उद्घाटन समारोह के बाद अपना नाम वापस ले लिया। इस प्रकार कुल 80 देश ही रह गए

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
सोवियत संघ	80	195
पूर्वी जर्मनी	47	126
बुल्गारिया	08	41
क्यूबा	08	20
इटली	08	15

अमेरिकी बहिष्कार

1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। विरोध में अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी और जापान समेत 62 देशों ने बहिष्कार किया। यद्यपि इन देशों के कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक झंडे तले भाग लिया।

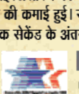
भारत ने हाकी में फिर जीता सोना : पुरुष हाकी टीम ने ओलिंपिक में अपने आठवें पदक के रूप में इस आयोजन का स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में स्पेन को हराया। सोवियत संघ को कांसे से संतोष करना पड़ा। महिला हाकी टीम चौथे स्थान पर रही।



1984
इतिहास बनाने से चूकीं ऊषा

विरोध के बीच आयोजन में निजी कंपनियों को पैसा लगाने की छूट दी गई। प्रसारण का सौदा भी आकर्षक रहा। 22.3 करोड़ डालर की कमाई हुई। रोम में मिल्खा सिंह के बाद यहां पीटी ऊषा एक सेकेंड के अंतर से इतिहास बनाने से चूक गई।

मेजबानी



1984 ओलिंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए लास एंजिलिस के अलावा तेहरान दौड़ में था। ईरान में जारी राजनीतिंक और सामजिक उथल-पुथल की वजह से उसने अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया। लिहाजा आइओसी ने स्वाभाविक रूप से लास एंजिलिस को मेजबानी दे दी।

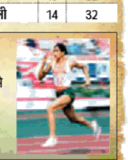
19 जुलाई-03 अगस्त

6829 एथलीट | 140 देश | 21 खेल 221 मुकाबले

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	83	174
रोमानिया	20	53
पूर्वी जर्मनी	17	59
चीन	15	32
इटली	14	32

चौथे स्थान पर रहीं ऊषा : 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत की उड़नपरी पीटी ऊषा चौथे स्थान पर रहीं। वह सेकेंड के सौवें हिस्से से कांस्य पदक पाने से चूक गई। रोमानिया की क्रिस्टिनिया (55.41 सेकेंड) ने ऊषा (55.42 सेकेंड) को पछाड़कर कांसा जीता। हालांकि ऊषा किसी ओलिंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई।



सोवियत संघ का विरोध

मास्को ओलिंपिक (1980) का अमेरिका ने बहिष्कार किया था। बदले की कार्रवाई करते हुए सोवियत संघ समेत पूर्वी यूरोप के 14 देशों ने अमेरिका में हो रहे खेलों के इस महाकुंभ का बहिष्कार किया।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
जोश नई राहों का
शनिवार, 17 जुलाई, 2021



अगर आप एक सच्चे लीडर हैं, तो आपको सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की सफलता पर भी ध्यान देना जरूरी है। -सुंदर पिचाई

यहां सर्च करें नई नौकरियां

टेक लर्निंग

आजकल नौकरियों को सर्च करना पहले की तुलना में आसान हो गया है। कई ऐसे एप्स हैं, जो आपको नई नौकरियों को सर्च करने में मदद करेंगे। ये आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल से मैच करती नई जाब ओपनिंग की जानकारी देते रहेंगे। आइए, जानते हैं कुछ ऐसे ही एप्लीकेशंस के बारे में...

लिंक्डइन जॉब सर्च: लिंक्डइन केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट ही नहीं है, बल्कि यह जॉब सर्च करने का एक अच्छा जरिया बना गया है। अच्छी बात यह है कि यह लोकेशन के आधार पर आपको नई जाब ओपनिंग्स की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आटोमैटिकली भेजता रहता है। साथ ही, यहां पर लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए ही अप्लाई करने की सुविधा दी गई है। अगर आप चाहें, तो जाब सर्च को कंपनी के नाम, जाब पोजिशन आदि के आधार पर भी फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा, यह आपके प्रोफाइल से मैच करते हुई नई जाब ओपनिंग्स की जानकारी भी देता है। कंपनी का दावा है कि वह जाब सर्च के दौरान यूजर्स की प्राइवेसी का खयाल भी रखता है। इस एप्लीकेशन को एंड्रायड और आइओएस डिवाइस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

ग्लासडोर: जाब सर्च के लिए इस एप की मदद भी ले सकते हैं। यहां पर जाब सर्च के अलावा और भी बहुत कुछ है। जिस कंपनी में जाब करना चाह रहे हैं, यहां उसका रिव्यू देख सकते हैं। प्रोफाइल के हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, यह उसकी जानकारी भी आपको देता है। आप यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंट, कस्टमर सर्विस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर, आइटी, सेल्स, शिपिंग, साफ्टवेयर आदि फील्ड से रिलेटेड जाब को सर्च कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन एंड्रायड और आइओएस डिवाइस के लिए उपलब्ध है।

फीचर डेस्क



फोटो : इमेजेज बाजार

जिप रिक्रूटर

यह भी एक उपयोगी एप है। यहां पर भी जाब सर्च बहुत आसान है। यहां स्किल्स, क्राइटेरिया, फिल्टर्स आदि के आधार पर जाब सर्च की सुविधा दी गई है। अगर जाब प्रोफाइल से मैच करता है, तो यह आपको उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए देता है। यहां रिज्यूमे को डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलती है और बस एक क्लिक में जाब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर नर्सिंग, लाजिस्टिक्स, जर्नलिज्म, पार्टटाइम, रिमोट आदि जैसी नौकरियों को सर्च किया जा सकता है। यह एप एंड्रायड और आइओएस दोनों डिवाइस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

कोरोना महामारी की वजह से बेशक रोजगार के मोर्चे पर कठिनाइयां पैदा हुई हैं, लेकिन इससे तमाम नये अवसर भी सामने आए हैं और युवा स्टार्टअप के जरिए इन अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी अपने किसी इनोवेशन के साथ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए...



फोटो : इमेजेज बाजार

स्टार्टअप की ओर कैसे बढ़ाएं कदम



टर्निंग प्वाइंट

मिलन सिन्हा
मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेलनेस कंसल्टेंट

देश में इस समय शिक्षित युवाओं द्वारा व्यवसाय-व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में स्टार्टअप के रूप में पहल लगातार आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। कोरोना महामारी के दौरान रोजगार की प्रतिकूल परिस्थिति ने इस पहल को गति प्रदान की है। जब कोई गंभीर समस्या हमारे युवाओं के सामने आती है, तो देखा गया है कि वे नवाचार और रचनात्मक तरीके से सफलता के रास्ते तलाश लेते हैं। इसके प्रत्यक्ष अनुभव से हाल ही में मुझे गुजरने का अवसर मिला, जब देशभर से प्राप्त सैकड़ों स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में से उत्तम दस प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करने वाले एक निर्णायक मंडल में मैं सक्रिय रूप से जुड़ा। इसमें आइआइएम, आइआइटी, एनआइटी सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षित छात्र-छात्राओं ने हेल्थ केयर, ट्रैवल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, लैंग्वेज लर्निंग, डिजिटल हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन व मार्केटिंग आदि अनेक विषयों से संबंधित नायाब प्रोजेक्ट्स पेश किए। इनका आकलन-विश्लेषण करने के क्रम में हमने कई बातें नोट कीं और टाप टेन प्रोजेक्ट्स के प्रेजेंटेशन सेशन में हमने उन पर चर्चा भी की। बताते चलें कि 'स्टार्टअप इंडिया' भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है जिससे आर्थिक विकास के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें।

अवसर हैं बड़े: दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति बढ़ते रुझान के कारण देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में अच्छी प्रगति देखी गई है। नवाचार और जोखिम से जूझने के उनके सकारात्मक जज्बे के कारण यह विश्वास निरंतर मजबूत हो रहा है। टेक्नोलाजी का सपोर्ट भी देश में स्टार्टअप की वृद्धि को गति प्रदान कर रहा है। इंटरनेट की सुलभता, इसका उपयोग करने वालों की संख्या में तेज वृद्धि और इंटरनेट शुल्क में कमी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में पचास करोड़ से ज्यादा भारतीय संपूर्ण देश में इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। हां, समाज और सरकार का रुख भी इस मामले में उत्साहवर्धक रहा है। पिछले दिनों नैसकाम के टेक्नोलाजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय दुनिया भारत की तरफ अधिक भरोसे और उम्मीद से देख रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में ज्ञान-विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में भारत ने न केवल खुद को साबित किया है, बल्कि लगातार आगे भी बढ़ाया है। ऐसे में स्टार्टअप को ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना चाहिए जो ऐसे विश्वस्तरीय उत्पाद तैयार कर सकें, जो उत्कृष्टता के मामले में एक बेहतर मानक स्थापित कर सकें।

स्टार्टअप के रूप में काम करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए इन पहलुओं पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है:

आइडिया है अहम: किसी भी तरह के स्टार्टअप के लिए आइडिया बहुत अहम होता है। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आइडिया में इस आकर्षण के साथ-साथ इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी इसे जमीन पर उतारना संभव है या नहीं, इसकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रस्तावित प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से कितना फलदायी होगा, यह जांचना भी जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आपके प्रोजेक्ट को व्यावहारिक रूप में खड़ा करना न केवल तकनीकी रूप से मुमकिन हो, बल्कि वह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद भी हो।

प्रोजेक्ट से आपका लगाव: कई बार यह बात सामने आती है कि प्रोजेक्ट तो प्रथम दृष्ट्या ठीक है, लेकिन आपका उससे कोई लगाव नहीं है या यह आपके पैशन का हिस्सा नहीं है। आपने मिलते-जुलते किसी सफल प्रोजेक्ट को देखकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि तैयार कर ली है या करवा लिया है। आपका ऐसे सेक्टर के किसी प्रोजेक्ट से वास्तविक जुड़ाव या उसका अनुभव नहीं है। इससे प्रोजेक्ट की निरंतरता और दीर्घकालिक सफलता संदिग्ध हो जाती है।

खूबियां और खामियां: कहते हैं जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके विषय में पूरी जानकारी (छोटी या बड़ी सब) आपको होनी चाहिए। कहीं और कभी भी प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन में उसकी खूबियों और खामियों को स्पष्ट रूप से लोगों को बताना आपको मार्केट में एक अच्छी पहचान दे सकता है। इसके अनेक फायदे हैं। प्रोजेक्ट को संचालित करने में जिनकी प्रमुख भूमिका हो, उनके प्रोफाइल स्ट्रांग और पारदर्शी होना भी जरूरी है, जिससे शुरुआत में इन्वेस्टर या बैंक को कनविंस करना आसान हो जाए। ऐसे में इसका बहुआयामी फायदा प्रोजेक्ट को आगे भी बराबर मिलता रहता है।

3-सी के फार्मूले पर परखना जरूरी: इस संबंध में प्रोजेक्ट को 3-सी यानी कैपेसिटी, कैपिटल और कैरेक्टर के चिरस्थापित फार्मूले की कसौटी पर परखना भी जरूरी है। कहने का अभिप्राय यह कि आपकी क्षमता क्या है, आपके पास कैपिटल जुटाने के क्या-क्या विकल्प हैं और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के पीछे आपकी योजना और सोच क्या है? इसके साथ ही प्रोजेक्ट के सामने उपस्थित और संभावित अवसरों और जोखिमों का विस्तृत आकलन-विश्लेषण करना आवश्यक है। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के मामले में मार्केट में डिमांड-सप्लाई और प्रतिस्पर्धा की स्थिति से अवगत होना भी अच्छा होता है। इस क्रम में आपको जमीनी हकीकत से परिचित होने का सुअवसर मिलता है।

जानें कानूनी पहलुओं को: प्रोजेक्ट से संबंधित सभी छोटे-बड़े कानूनी पहलुओं को अच्छी तरह जानना चाहिए, जिससे कि प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर उसके सफल परिचालन तक सभी कानूनी शर्तों का कंप्लायंस यानी नियमों का पालन समय से हो सके। जहां पेटेंट आदि करवाना जरूरी है, वहां उस प्रक्रिया का पालन करें, अन्यथा आगे चलकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ईमेल : hellomilansinha@gmail.com

चुनौतियों से न घबराएं



यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस क्षेत्र में ज्ञात-अज्ञात कई तरह की चुनौतियां कभी भी सामने आ सकती हैं। अतः अपनी ओर से तैयारी पूरी रखें और यथासंभव प्रो-एक्टिव होकर काम करें। देश-विदेश में जितने भी स्टार्टअप आज सफलता का परचम लहरा रहे हैं, कमोबेश उन सभी को इसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा है। यहां स्वामी विवेकानंद के इस अनमोल विचार को हमेशा याद रखें कि, 'जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या न आये, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।'

जरूरी है आइडिया पर भरोसा



सक्सेस मंत्रा

दीपक साहनी
संस्थापक/सीईओ, हेल्दिएंस

अस्पताल की चारदीवारी से बाहर निकल चुकी है स्वास्थ्य सेवा इंडस्ट्री। अब घर बैठे तमाम प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जा सकते हैं। अपने हेल्थ को मैनेज किया जा सकता है। सैंपल परीक्षण के साथ डाक्टरों से परामर्श एवं दवाएं भी आनलाइन मंगाई जा सकती हैं। कोविड-19 ने यह भी सिखा दिया है कि कैसे तेज गति से विश्वसनीय टेस्ट कराए जा सकते हैं और उनका परिणाम भी आनलाइन पा सकते हैं। यह सब मशीन लर्निंग, एआइ, आइओटी जैसी टेक्नोलाजी से संभव हो पाया है। तभी तो देश में हेल्थटेक स्टार्टअप्स की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। हेल्दिएंस भी एक ऐसा ही स्टार्टअप है, जो लोगों को घर बैठे डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ दीपक साहनी कहते हैं, 'मैं एक स्वस्थ भारत देखना चाहता हूं। लोगों के घरों तक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यही कारण है कि वर्ष 2014 में महज पांच लोगों से शुरू की गई कंपनी में आज 1500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मार्केट में हमारे प्रति लोगों ने विश्वास जताया है। मैं मानता हूं कि अगर हमें अपने आइडिया पर भरोसा है, तो निवेशक जरूर मिलेंगे। इसलिए विश्वास रखें। हां, अति-उत्साह से बचने की कोशिश करनी चाहिए।'

दीपक साहनी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स किया है। लेकिन उद्यमिता में पहला कदम 19 वर्ष की आयु में ही रख दिया था। तब इन्होंने कंप्यूटर असेंबलिंग का बिजनेस शुरू किया था। 2003 में इन्होंने डिजिटल हेल्थकेयर एजेंसी के जरिये स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र का रुख किया। विश्व के 120 अस्पतालों के साथ काम किया। दीपक बताते हैं, 'उन दिनों मेरा 70 फीसद समय अस्पतालों में बीतता था। मैंने देखा था कि कैसे मरीज कटु अनुभवों के साथ अस्पताल से लौटते थे। खयाल आया कि क्यों न इलाज से पहले एहतियात पर ध्यान दिया जाए। मैंने डायग्नोस्टिक सर्विस इंडस्ट्री में भी एक खाई देखी थी। ग्राहकों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए 'हेल्दिएंस' शुरू करने का आइडिया आया।'

अस्तित्व पर संकट की चुनौती: हम सबने देखा कि महामारी की शुरुआत मैं कैसे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री तैयार नहीं थी। दीपक ने बताया, 'गैर-कोविड मरीजों की संख्या में आई गिरावट के कारण हमारे जैसी कंपनियों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगने वाला था। इसी से यह जरूरत महसूस की गई कि इंडस्ट्री के छोटे एवं बड़े खिलाड़ियों को मिलकर काम करना होगा, जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। हां, इसमें टेक्नोलाजी ने मदद की। डिजिटल टूल्स की मदद से हम कई चुनौतियों का सामना कर सके।'

बातचीत : अंशु सिंह



फोटो : इमेजेज बाजार

समय है सबसे बड़ी पूंजी

किसी भी स्टार्टअप के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है फंड्स की। कई निवेशकों से मिलने के बाद दीपक ने क्रिकेटर युवराज सिंह से मुलाकात की। उन्हें अपने आइडिया एवं विजन से अवगत कराया। इसके बाद, युवराज सिंह ने इनके प्रोजेक्ट का समर्थन किया। इससे ब्रांड को स्थापित करने में आसानी हुई। लोग सहजता से जुड़ते चले गए। दीपक कहते हैं, 'बहुत से उद्यमियों के लिए कारोबार एक चुनौती होती है। उन्हें लगता है कि इस रास्ते पर जितना कम चला जाए, उतना अच्छा। लेकिन यह सोच सही नहीं है। हां, इस सफर में चुनौतियां आती हैं। मगर उनसे ही सीखकर आगे बढ़ना होता है।'

उत्साही लीडर बनने की राह



लाइफ स्किल

डा. अनिल सेठी
मोटिवेटर एवं लाइफ कोच



आज कोरोना के दौर में हम सबको लीडरशिप की भावना की आवश्यकता है। चाहे आप प्राइवेट जाब में हों, सरकारी जाब में हों या कोई बिजनेस करते हों या कुछ और...। सभी जगह अगर ऐसी लगन और निष्ठा हो, तो हम सब इस कठिन दौर से भी आगे निकल जाएंगे।

वैसे, हम सब जीवन में लीडर बनना चाहते हैं। किसी भी क्षेत्र में हों आगे रहना चाहते हैं। मुझे लीडर की एक परिभाषा सबसे अच्छी लगती है वह है-'लीडर इज ए डीलर इन होप', मतलब जो आपको आशा की किरण दिखा सके, वही लीडर या नायक होता है। किसी भी क्षेत्र, कंपनी, देश की तरक्की में सभी का योगदान होता है। यह किसी एक के कार्य का परिणाम नहीं होता है। जब तक टीम के सभी लोग एक लीडर की तरह अपना काम पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, तब तक सफलता संभव नहीं होती है। इस बात को समझाने के लिए मैं दो कहानियां सुनाना चाहता हूं...।

पहला किस्सा रामायण से जुड़ा है। जब भगवान श्रीराम की सेना लंका जाने के लिए समुद्र में पत्थर से पुल बना रही थी, तो वहां एक गिलहरी बार-बार आ-जा रही थी और उसको बचाने के चक्कर में काम की गति कम हो रही थी। उस गिलहरी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। अंत में यह बात श्रीराम तक पहुंची। उन्होंने गिलहरी को बुलाया और कहा कि तुम काम में बाधा क्यों डाल रही हो। गिलहरी ने कहा, महाराज मैं तो पुल बनाने में मदद कर रही हूं। श्रीराम ने पूछा, वह कैसे, तो गिलहरी ने कहा मैं मिट्टी पर लोटती हूं और मेरे ऊपर जो मिट्टी चिपक जाती है उसे मैं पत्थरों के ऊपर जाकर झाड़ देती हूं, जो कि पत्थरों के बीच की जगह को भर देती है और मजबूती प्रदान करती है। गिलहरी की बात सुनकर श्रीराम मुस्कुरा दिए। सभी उस गिलहरी की निष्ठा और लगन के कायल हो गए।

इसी तरह, दूसरी घटना अमेरिका की है। राष्ट्रपति जेएफ कैनेडी ने दुनिया का पहला मिशन मून (चंद्रमा पर जाने का अभियान) प्रारंभ किया। मिशन की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने एक बार नासा हेडआफिस का दौरा किया। उस विजिट के दौरान जब वह एक कारिडोर से जा रहे थे, तभी एक आदमी जो कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उनके सामने आया और बड़ी गर्मजोशी से बोला-गुड मार्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट। जब कैनेडी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो वह बोला, सर मैं इस मिशन मून का बहुत महत्वपूर्ण अंग हूं और वह चला गया। लेकिन प्रेसिडेंट ने देखा कि कुछ लोग उस आदमी पर हंस रहे थे। उन्होंने उत्सुकतावश पूछा कि यह कौन था, उत्तर मिला कि यह नासा का सफाई कर्मचारी है। तब कैनेडी ने कहा उसको बुलाओ, मुझे मिलना है। थोड़ी देर में वह आदमी प्रेसिडेंट के सामने था। कैनेडी ने पूछा कि आप कौन हो और आप कैसे इस मिशन के महत्वपूर्ण भाग हो, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यहां रोजाना यह सुनिश्चित करता हूं कि पूरा आफिस साफ-सुथरा रहे, सभी वस्तुएं अपनी निश्चित जगह पर हों ताकि किसी का समय नष्ट न हो। उसकी भावना को सुनकर जेएफ कैनेडी ने कहा आपकी लीडरशिप देखकर मैं अब मिशन की सफलता के प्रति सौ फीसद आश्वस्त हो गया हूं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि लीडरशिप के लिए किसी पद या डेजिग्नेशन की आवश्यकता नहीं होती। आपके अंदर की भावना ही आपको लीडर या नायक बनाती है।

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 17 जुलाई, 2021 शनिवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी का राशिफल।

आज का राहुकाल: प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक।

आज का दिशाशूल: पूर्व।

पर्व एवं त्योहार: महाष्टमी।

आज की भद्रा: प्रातः 04:35 बजे से शाम 03:41 बजे तक।

मेष: दांपत्य जीवन सुखमय होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है।

वृष: अज्ञात भय शारीरिक और मानसिक कलेश देगा। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में प्रगति होगी।

मिथुन: बहुप्रतिक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी, पड़ोसी आदि के कारण तनाव मिल सकता है।

कर्क: वाणी पर संयम रखें। चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। उदर विकार या चोट का भय है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

सिंह: बहुप्रतिक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि आएगी, लेकिन नेत्र विकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

कन्या: उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी।

तुला: शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफलता देगा। नए संबंध बनेंगे।

वृश्चिक: पारिवारिक कलह के प्रति सचेत रहें। व्यावसायिक, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन दांपत्य जीवन में तनाव आ सकता है।

धनु: जीवनसाथी का सहयोग एवं सान्निध्य मिलेगा। नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो।

मकर: व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ: दांपत्य जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। कर्ज में न्यूनता आएगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा।

मीन: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। अधीनस्थ कर्मचारी, मित्र या भाई के कारण तनाव मिल सकता है। संयम से काम लें।

कल 18 जुलाई का पंचांग

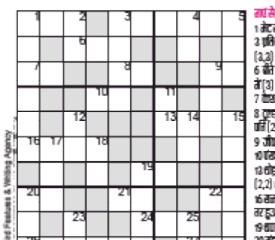


कल का दिशाशूल: पश्चिम।

पर्व एवं त्योहार: कंदर्प नवमी।

विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की नवमी 24 घंटे 30 मिनट तक, तत्पश्चात् दशमी स्वाती नक्षत्र 24 घंटे 08 मिनट तक, तत्पश्चात् विशाखा नक्षत्र साध्य योग 25 घंटे 56 मिनट तक, तत्पश्चात् शुभ योग तुला में चंद्रमा।

वर्ग पहेली-1639



बाएं से दाएं

1 [illegible] (3)। 3 [illegible] (3,3)। 6 [illegible] (3)। 7 [illegible] (2)। 8 [illegible] (2)। 9 [illegible] (2)। 10 [illegible] (2)। 13 [illegible] (2,2)। 16 [illegible] (4)। 19 [illegible] (2)। 20 [illegible] (2)। 21 [illegible] (2)। 22 [illegible] (2)। 24 [illegible] (3)। 26 [illegible] (3,3)। 27 [illegible] (3)।

ऊपर से नीचे

1 [illegible] (3,3)। 2 [illegible] (2)। 3 [illegible] (4)। 4 [illegible] (2)। 5 [illegible] (3)। 9 [illegible] (2)। 11 [illegible] (2)। 12 [illegible] (2)। 14 [illegible] (2)। 15 [illegible] (3,3)। 17 [illegible] (3)। 18 [illegible] (2)। 19 [illegible] (4)। 20 [illegible] (3)। 23 [illegible] (2)। 25 [illegible] (2)।

कल का हल



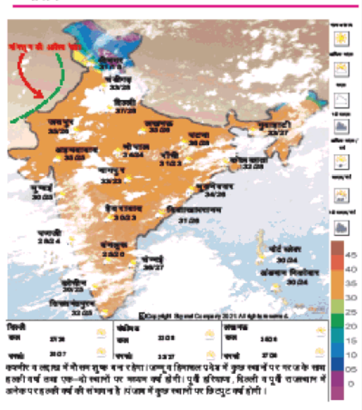
जागरण सुडोकू-1639

		7		3		5		4
2	1				5			3
		5	2		7	8	9	
9			1	2		4		7
		2			6		3	
1				8				6
5	7			1		9		
	9	1		7			4	
4			6		8	7		5

कल का हल

5	6	4	9	1	2	7	8	3
3	9	2	8	4	7	5	1	6
1	8	7	5	6	3	2	9	4
4	7	8	6	3	5	1	2	9
9	2	1	4	7	8	6	3	5
6	3	5	1	2	9	4	7	8
7	1	9	3	5	6	8	4	2
2	5	3	7	8	4	9	6	1
8	4	6	2	9	1	3	5	7

मौसम



कल पढ़ें



ओलंपिक में तकनीक का जलवा

ओलंपिक में तकनीक का जबरदस्त जलवा दिखेगा। दर्शकों को एडवांस टेक्नोलाजी की वजह से एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। जानेंगे, जापान कैसे करेगा ओलंपिक में तकनीक का इस्तेमाल...

महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती की पात्रता मिली

1948 में आज ही देश में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और आइपीएस समेत सभी नागरिक सेवा में भर्ती की पात्रता मिली थी। इस फैसले के बाद अन्ना राजम मल्होत्रा प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थीं।





बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया गया

माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को आज ही 1995 में फोर्ब्स पत्रिका ने पहली बार दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया था। वह 24 साल तक लगातार टाप पर रहे। 2018 में उन्हें पछाड़कर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।

वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों



परमवीर चक्र पाने वाले वायुसेना के इकलौते जवान फ्लाइंग आफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म आज ही 1943 में लुधियाना में हुआ था। पिता के वायुसेना में होने के चलते इन्हें बचपन से ही सेना में जाने का जुनून था। 1967 में वायुसेना में शामिल हुए। 14 दिसंबर, 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर पाकिस्तान के छह सैबर जेट विमानों के हमले का इन्होंने अकेले सामना किया था। इसी लड़ाई में उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। मरणोपरांत 1972 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

इधर-उधर की

एक-दूसरे में फंस गए उल्लू और कछुआ



एनिमल कंट्रोल टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचाया ● इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी : कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है, जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। पिछले दिनों अमेरिका के आर्लिंगटन में एनिमल कंट्रोल टीम के सामने भी ऐसा ही मामला सामने आया। किसी ने फोन कर टीम को बताया कि उनके घर के पीछे एक उल्लू उड़ नहीं पा रहा है। टीम के लोग वहां पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि उल्लू का पंजा एक कछुए की खोल में फंस गया था। टीम दोनों को लेकर कार्यालय पहुंची और वहां उन्हें सुरक्षित तरीके से अलग किया गया। टीम ने बताया कि उल्लू को थोड़ी चोट आई है और कछुआ पूरी तरह सुरक्षित है। उन्हें दोबारा जंगल में छोड़े जाने तक एक प्रशिक्षित व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा।

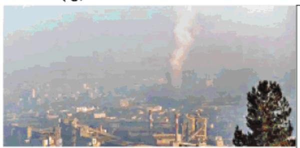
प्रदूषण से बच्चों में मोटापे का खतरा

चिंताजनक ▸ बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फार ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं के अध्ययन में आया सामने

प्रदूषण का हमारी शारीरिक गतिविधि और नींद पर पड़ता है असर

वाशिंगटन, एएनआइ : धरती पर लगातार बढ़ रहा प्रदूषण कई बीमारियों का कारण बन रहा है। अब इस कड़ी में एक और चिंताजनक बात सामने आई है। एक नवीन अध्ययन में बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण मोटापे का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि, शोधकर्ता प्रदूषण और मोटापे के बीच सीधे संबंध का पता नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने ऐसी वजहें जरूर बताई हैं, जिनकी वजह से शहरी क्षेत्रों में रह रहे बच्चे मोटापे से पीड़ित हो रहे हैं।

यह अध्ययन बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फार ग्लोबल हेल्थ (आइएसग्लोबल) के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया, जिसमें ला कैक्सा फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फार प्राइमरी केयर रिसर्च जोर्डी गोल ने सहयोग किया। इस अध्ययन को एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किया गया है।



एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किया गया है अध्ययन। फाइल फोटो

इस तरह किया अध्ययन : इस अध्ययन के लिए सबडेल में नौ से 12 वर्ष की आयु के 2,213 बच्चों के डाटा का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में सामने आया कि 40 फीसद बच्चे अधिक वजन वाले या मोटे थे। शोधकर्ताओं ने बच्चों में मोटापे और शहरी कारकों के बीच संबंध की जांच की। इसमें अक्टूबर 2017 से जनवरी 2019 के बीच बच्चों का परिवेश (वायु प्रदूषण, हरा-भरा स्थान, खानपान, सड़क यातायात और वाहनों के कारण ध्वनि प्रदूषण) देखा गया। इस दौरान बच्चों की विभिन्न मापें जैसे बाडी इंडेक्स मास, कमर व शरीर में जमा चर्बी की भी माप की गई। इसके अलावा बच्चों में फास्ट फूड के सेवन की आदत, शारीरिक गतिविधि, नींद का समय आदि को भी देखा गया। अभी तक ऐसे कुछ अध्ययन किए जा चुके हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के व्यवहार और वहां के माहौल के बीच संबंध और मोटापे के खतरे का विश्लेषण किया गया है। यह नवीन अध्ययन और गहराई से बच्चों में मोटापे की पड़ताल करता है।

यह आया सामने : इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और आइएसग्लोबल व आडीआइपी जोर्डी गोल में शोधकर्ता जेरोएन डी बोंट के मुताबिक, हमारे अध्ययन में सामने आया कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर और ट्रैफिक व शोर का संबंध बॉडी इंडेक्स मास और बचपन में अधिक वजन या मोटापे से होता है। यानी शहरी क्षेत्रों में जहां ट्रैफिक अधिक है वहां ध्वनि और वायु प्रदूषण के अधिक होने के कारण बच्चों में मोटापे का खतरा अधिक देखा गया। हालांकि, प्रदूषण और मोटापे के सीधे संबंध का पता अभी नहीं चल सका है, लेकिन वैज्ञानिकों के दल ने इसके लिए विभिन्न परिकल्पनाओं के प्रस्ताव रखे हैं।

ये हो सकती हैं वजहें : शोधकर्ताओं के मुताबिक, वायु प्रदूषण आणविक तंत्र को बाधित कर सकता है, जो सूजन या आक्सीडेटिव तनाव, हार्मोन व्यवधान और आंत में वसा के कारण मोटापे की वजह बन सकता है। चूहों पर इसी तरह का अध्ययन प्रकाशित भी हो चुका है। वहीं, शोर नींद में व्यवधान पैदा करता है, जिससे तनाव वाले हार्मोंस की वृद्धि होती है। इसकी वजह से बच्चों के शारीरिक विकास पर असर पड़ता है और उनमें मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि शोर के कारण बच्चे चैन की नींद नहीं ले पाएंगे तो उनकी शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाएंगी। इस वजह से वजन बढ़ सकता है।

ये भी हो सकते हैं कारण

शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि शहरी क्षेत्रों के खानपान में फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है। ऐसे में बच्चों द्वारा इसका अधिक सेवन भी उनके मोटापे की वजह है, क्योंकि इसके जरिये वे अधिक कैलोरी लेते हैं, लेकिन शारीरिक गतिविधियां कम होने से उसे बर्न नहीं कर पाते। वहीं, शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि शहरी क्षेत्र में प्रदूषण और मोटापे के बीच संबंध का पता लगाने के लिए अभी इस दिशा में और अध्ययन की आवश्यकता है।

फिल्म रिव्यू

तूफान

प्रमुख कलाकार : फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर, परेश रावल, दर्शन कुमार, सुप्रिया पाठक
निर्देशक : राकेश ओमप्रकाश मेहरा
अवधि : दो घंटा 41 मिनट
रिलीज प्लेटफार्म : अमेजन प्राइम वीडियो

ठंडा है यह तूफान



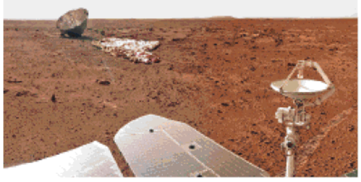
बाक्सिंग के इर्दगिर्द बनी फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा अभिनीत 'मैरी काम' और विनीत कुमार सिंह अभिनीत 'मुक्काबाज' लोकप्रिय हुईं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित 'तूफान' के केंद्र में भी बॉक्सिंग है, लेकिन इसमें कोई खास आवेग नहीं है।

मुंबई के डोंगरी इलाके का स्ट्रीट फाइटर अजीज अली (फरहान अख्तर) राबिन हुड सरीखा है। वह जफर भाई (विजय राज) के लिए जबरन वसूली का काम करता है और अपनी कमाई यतीम बच्चों पर खर्च करता है। मारपीट के दौरान चोट लगने पर अली चैरिटी अस्पताल में कार्यरत डाक्टर अनन्या (मृणाल ठाकुर) के पास मरहम-पट्टी के लिए जाता है। थोड़ी नोकझोंक के बाद अनन्या उसे बाक्सर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह नाना प्रभु (परेश रावल) के पास बाक्सिंग सीखने जाता है। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि नाना ही अनन्या के पिता हैं। एक ब्लास्ट में अपनी पत्नी को खोने की वजह से वह एक समुदाय के प्रति नफरत रखते हैं, लेकिन अनाथ अली को प्रशिक्षण देने को तैयार हो जाते हैं। उनकी सरपरस्ती में वह बेहतरीन बाक्सर बनकर उभरता है। वह मुंबई के मुहम्मद अली के तौर पर विख्यात होता है। नाना उसे तूफान नाम देते हैं। हालांकि बेटी के साथ प्रेम संबंध का पता चलने पर वह आगबबूला हो जाते हैं। अनन्या घर छोड़कर अली के पास रहने आती है। इस बीच मैच में हारने के लिए पैसे लेने की खबर वायरल होते ही अली पर फेडरेशन पांच साल का प्रतिबंध लगा देती है। घटनाक्रम मोड़ लेते हैं। अली-अनन्या शादी कर लेते हैं। वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। उनकी पांच साल की बेटी है। फेडरेशन अली पर बाक्सिंग पर प्रतिबंध हटाने का खत भेजती है। अनन्या चाहती है कि अली रिंग में वापसी करे। क्या अली वापसी करेगा? क्या नाना के साथ उनके रिश्ते बदलेंगे, इसके इर्दगिर्द कहानी गढ़ी गई है।

'भाग मिल्खा भाग' के करीब आठ साल बाद राकेश ओम प्रकाश और फरहान साथ आए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि खेल आधारित यह फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' की तरह शानदार होगी, मगर यह तूफान ठंडा है। राकेश ओम प्रकाश ने बाक्सिंग के साथ आतंकवाद, लव जेहाद, धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। फिल्म देखते हुए लगता है कि खेल आधारित कई फिल्मों की कहानियों को मिलाकर 'तूफान' बना दी गई है। इसमें न जोश है, न उमंग। रिंग में खिलाड़ियों की भिड़ंत में बाक्सिंग के प्रति जोश पैदा करने में राकेश विफल रहे हैं। फिल्म में दर्शन का किरदार अविकसित है। फिल्म में कई दृश्य अनावश्यक हैं। 'भाग मिल्खा भाग' में एथलीट बनने के बाद फरहान ने जुझारु बाक्सर की भूमिका निभाई है। उन्होंने कसरती शरीर के साथ उस हिम्मती मन पर भी मेहनत की है, जो अली के चरित्र को आत्मसात करने के लिए जरूरी था। हालांकि गुंडे के तौर पर वह प्रभावित नहीं करते। मृणाल मासूम लगी हैं, वहीं कोच की भूमिका में परेश रावल अपने अभिनय से किरदार को प्रभावशाली बनाते हैं।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

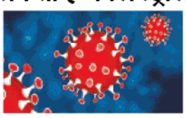


चीन के रोवर ने भेजी मंगल की तस्वीर : मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं। इसी दिशा में चीन ने अपना एक रोवर मंगल ग्रह पर भेजा, जिसने अब सतह की फोटो और वीडियो भेजना शुरू कर दिया है। इस रोवर का नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर जूरोंग रखा गया है। इसने अब तक 236 मीटर की दूरी तय की है। रिमोट नियंत्रित रोवर ने मंगल की सतह पर अपने लैंडिंग कैप्सूल के रैंप को नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद चीन मंगल की जमीन पर परिक्रमा करने, उतरने और रोवर तैनात करने वाला पहला देश बन गया है। छह पहियों वाला रोवर यूटोपिया प्लैनिटियाकी जगह का सर्वेक्षण कर रहा है। जूरोंग धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और हर तीन दिन में यह महज 10 मीटर चलेगा। एएफपी

कोरोना में काम आ सकती है कोलेस्ट्राल कम करने की दवा

अनुसंधान

कोरोना वायरस (कोविड-19) से मुकाबले में कोलेस्ट्राल कम करने वाली दवा को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि यह दवा कोरोना में काम आ सकती है। इससे मौत के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अध्ययन के अनुसार, स्टैटिन दवा का इस्तेमाल करने वाले रोगियों में कोरोना से मौत का खतरा 41 फीसद कम पाया गया है। यह दवा आमतौर पर ब्लड कोलेस्ट्राल के स्तर को कम करने में इस्तेमाल की जाती है। स्टैटिन कोलेस्ट्राल बनने के लिए उत्तरदायी लिवर एंजाइम को रोकने का काम करती है।



स्टैटिन दवा का इस्तेमाल करने वाले रोगियों में कोरोना से मौत का खतरा 41 फीसद कम पाया गया। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

अमेरिकी सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन का अनुमान है कि 93 फीसद मरीज कोलेस्ट्राल कम करने के लिए स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं। इस दवा के उपयोग का संबंध उन कोरोना रोगियों में मौत के 32 फीसद कम खतरे से पाया गया है, जो हृदय रोग या उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहे हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, ऐसे मरीज स्टैटिन और उच्च रक्तचाप रोधी दवाओं के इस्तेमाल के चलते कोरोना से उबर सकते हैं। पीएलओएस वन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, यह निष्कर्ष 10 हजार 541 मरीजों के डाटा के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। इन मरीजों को कोरोना संक्रमण के चलते गत वर्ष जनवरी से सितंबर के दौराना अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लौरी डेनियल ने कहा, 'हम अपने पूर्व के नतीजों की पुष्टि करते हैं कि स्टैटिन का संबंध अस्पतालों में भर्ती कोरोना रोगियों में मौत के कम खतरे से पाया गया है।' -आइएएनएस

स्क्रीन शॉट

जब एक सीन को महसूस करने के लिए रितिक ठंडे पानी में कूदे



रितिक ने ताजा कीं जिंदगी न मिलेगी दोबारा की यादें।

फिल्मों के कुछ सीन में डायलाग नहीं होते हैं, जिन्हें निभाना बेहद ही मुश्किल होता है। बिना लाइनों के सिर्फ एक्सप्रेशन पर पूरे सीन को करने के लिए उस पल को महसूस करना जरूरी होता है। ऐसा ही कुछ किया रितिक रोशन ने फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में। हाल ही में इस फिल्म ने रिलीज के 10 साल पूरे किए हैं। एक लाइव के दौरान फिल्म की पूरा स्टारकास्ट ने उन सींस को दोबारा पढ़ा, जो फिल्म में उनके पसंदीदा थे। रितिक ने बताया कि स्कूबा डाइविंग के बाद फिल्म के सभी किरदार एक नाव पर बैठते हैं और फरहान की आवाज में सिर्फ एक कविता बैकग्राउंड में चलती है। उस सीन में मैं बहुत नर्वस था। उस एक सीन में मेरा किरदार अर्जुन वास्तविक में कैसा है, वह क्या महसूस कर रहा है, वह दर्शाना था, लेकिन कई टेक्स के बाद भी वह अहसास नहीं मिल रहा था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तभी मुझे लगा था कि वह सीन आसान नहीं होगा। पेपर पर वह सीन बहुत सुदंर था, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल था। कई बार वह सीन आउट फोकस हो रहा था। दरअसल, मैं उस सीन में खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो सीन नहीं हो पाएगा। मैंने निर्देशक जोया अख्तर से कहा कि मुझे कुछ सेकंड के लिए पानी में डुबकी लगाने दो। उन्होंने मुझे कहा कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। मैंने कहा कि मैं कर लूंगा। जब मैंने उस ठंडे पानी में डुबकी लगा ली, तब जाकर मैं उस पल को करीब से महसूस कर पाया था।

राहुल की ओर से दिशा को प्रपोज किए जाने के बाद से ही दोनों सितारों के एक होने का प्रशंसक इंतजार कर रहे थे। बिग बास के घर में राहुल के दोस्त बने अली गोनी ने इस शादी में जमकर धमाल किया है। शादी में कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए थे।

परिणय सूत्र में बंधे राहुल वैद्य और दिशा परमार

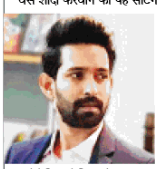
गायक राहुल वैद्य और दिशा परमार शुक्रवार को परिणय सूत्र में बंध गए। कोरोना काल की वजह से शादी में राहुल और दिशा के बहुत ही करीब रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। राहुल आफ व्हाइट रंग की शेरवानी में थे, वहीं दिशा शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। बिग बास 14 के घर में राहुल के दोस्त बने अली गोनी ने इस शादी में धमाल मचाने में कोई कमी नहीं रखी। अली ने राहुल की शादी के कई वीडियोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए हैं। राहुल ने घुटनों पर बैठकर पहले दिशा को अंगूठी पहनाई, फिर उनके साथ पूरे रीति-रिवाज से सात फेरे लिए और मांग में सिंदूर भरा। अली चूंकि लड़के वालों की तरफ से थे, इसलिए उन्होंने राहुल के जूते भी अपने पास संभालकर रख लिए थे, ताकि उन्हें दिशा की बहनें चुरा न पाएं। मेरे यार की शादी है... गाने पर राहुल और दिशा अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों के संग खूब झूमे। राहुल के दोस्तों ने नागिन डांस भी जमकर किया। उल्लेखनीय है कि राहुल ने दिशा को शादी के लिए बिग बास 14 में प्रपोज किया था। इसके बाद से ही दोनों के प्रशंसक इस शादी का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने अपनी शादी की सभी रस्मों की तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट मीडिया पर साझा किए हैं।



बिग बास में राहुल ने किया था दिशा को शादी के लिए प्रपोज ● इंटरनेट मीडिया

दोस्तों को भगाने और उनकी शादी में मदद कर चुके हैं विक्रांत मेस्सी

कई बार फिल्म में कुछ सींस ऐसे होते हैं, जो वास्तविक जीवन की याद दिलाते हैं। फिल्म 14 फेरे में विक्रांत मेस्सी का किरदार खुद की शादी करवाने के लिए कई तरह की सेटिंग करता है। वैसे शादी करवाने की यह सेटिंग विक्रांत ने वास्तविक जीवन में भी की है। खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के लिए। दैनिक जागरण से बातचीत में विक्रांत ने एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि मैं कई कोर्ट मैरिज का गवाह रह चुका हूं। मेरा एक दोस्त शादी के लिए घर से भाग गया था। हम दोस्तों ने मिलकर उसकी शादी करवाई। हमने खुशी-खुशी पति-पत्नी की मदद की और अब वे बच्चों के साथ खुशी-खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आखिरकार हम फिल्म के माध्यम से यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार एक खूबसूरत अहसास है और अगर आप खुद पर और अपने प्यार पर विश्वास करते हैं तो चीजें ठीक हो जाती हैं। 14 फेरे फिल्म जी5 पर 23 जुलाई को रिलीज होगी।



14 फेरे फिल्म में विक्रांत ने मुख्य किरदार निभाया है।

आप जो हैं वो ही बने रहें, नकल करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे : संजय मिश्रा

कहा जाता है कि सफलता की बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी इंसान का अपनी जड़ों से जुड़ा रहना जरूरी होता है, नहीं तो उसके भटकने की संभावना होती है। कामयाब, गोलमाल और टोटल धमाल जैसी फिल्मों के अभिनेता संजय मिश्रा भी ऐसे ही हस्तियों में हैं, जो सिनेमा जगत की चकाचौंध के बीच रहने पर भी अपने गांव और मिट्टी से जुड़े रहना पसंद करते हैं। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में संजय ने कहा, 'मुझे अपने गांव और मिट्टी की कभी याद नहीं आती, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उससे अलग हुआ हूं। मेरा शरीर भले ही दुनिया के किसी कोने में रहे, लेकिन मन वहीं बसता है। इंसान को अपनी जमीन से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि एक जमीन ही तो है सभी को कुछ न कुछ देती है। एक कलाकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो वो है वह बना रहे। इससे उसे जीवन में कई सहूलियतें मिलती हैं। नए कलाकारों से भी मेरा यही कहना है कि भगवान ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसे गुण दिए होते हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। आप अपने उन्हीं गुणों को निखारें, दूसरों की नकल करने का प्रयास मत करें। नकल करेंगे तो फंस जाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि यह शख्स किसी की नकल कर रहा है। कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल, लेकिन कौवे को हंस बनने की जरूरत ही क्या है। वह कौवा बनकर क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है।' संजय आगामी दिनों में सर्कस और जोगीरा सारा रा रा जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।



आगामी दिनों में सर्कस और ग्वालियर जैसी फिल्मों में नजर आएंगे संजय।

15 किलो वजन बढ़ाने के बाद डर रही थीं कृति सैनन

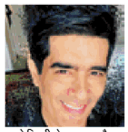
अभिनेत्री कृति सैनन की आगामी फिल्म मिमी है। इस फिल्म में कृति एक विदेशी जोड़े के लिए सरोगेट (किराए की कोख) मां का किरदार निभाएंगी। कृति इस फिल्म के प्रमोशन के लिए लाइव जुड़ीं। इस दौरान उन्होंने बताया, फिल्म में प्रेग्नेंसी वाले सीन के लिए 15 किलो वजन बढ़ाया था। मैं जब इस किरदार के लिए वजन बढ़ाकर आई थी, तो डरी हुई थी। सबसे पूछती थी कि मोटी लग रही हूं या नहीं। 15 किलो बढ़ाने के बाद भी अगर कोई यह कहता कि मोटी नहीं लग रही हो, तो पता नहीं मैं उसका क्या करती। उस सीन के लिए मुझे बहुत खाना पड़ा था। उन्होंने बताया कि फिल्म में एक मजेदार सीन है, जो उनके वास्तविक जीवन से लिया गया है। कृति कहती हैं, मेरे पापा बचपन में मुझे स्कूल के लिए जब उठाते थे, तो मेरे पैर पकड़कर खींचते थे और जब मेरा आधा शरीर बेड से नीचे आ जाता था, तो फिर पैर छोड़ देते थे। फिर मुझे न चाहते हुए भी उठना पड़ता था। ऐसा ही एक सीन फिल्म में भी है, जब अभिनेत्री सई ताम्हणकर मुझे आकर उठाती है, प्रेग्नेंसी से पहले वाले सीन में तो उन्होंने मुझे आराम से खींच लिया था। लेकिन जब मैं वजन बढ़ाकर आई, तो तब वह मुझे हिला ही नहीं पाईं। फिर फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर सर ने आकर मुझे उस सीन में खींचा। सीन में जो हाथ हैं, वह लक्ष्मण सर के हैं। मिमी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर 30 जुलाई को रिलीज होगी।



आगामी फिल्म मिमी में सरोगेट मां के किरदार में नजर आएंगी कृति ● इंस्टाग्राम

निर्देशन में कदम रखेंगे मनीष मल्होत्रा

यह तो सब जानते हैं कि फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और करण जौहर जिगरी दोस्त हैं। खबर है कि तमाम फिल्मी सितारों के कपड़े डिजाइन करने वाले मनीष अब निर्देशन में हाथ आजमाएंगे। उनकी यह फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस तले बनेगी। बताया जाता है कि यह फिल्म देश विभाजन की पृष्ठभूमि में म्यूजिकल लव स्टोरी होगी। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस पीरियड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले के पीछे मनीष ही हैं। इसे इतिहासकार और लेखकों की मदद से अंतिम रूप दिया जाएगा। मनीष श्रीदेवी, जूही चावला, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, मनीषा कोइराला, रानी मुखर्जी समेत अनेक अभिनेत्रियों की फिल्मों के स्टाइलिस्ट रहे हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल और रंगीला में उर्मिला मातोंडकर के डिजाइन कपड़ों से वह लाइमलाइट में आए। उल्लेखनीय है कि फिल्म निर्देशन के प्रति मनीष अपनी दिलचस्पी पहले एक साक्षात्कार में व्यक्त कर चुके हैं। उनके भतीजे पुनीत मल्होत्रा ने 2010 में करण के प्रोडक्शन हाउस तले बनी फिल्म आई हेट लव स्टोरीज से निर्देशन में कदम रखा था।



अपने जिगरी दोस्त करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस तले फिल्म बनाएंगे मनीष ● इंस्टाग्राम

'मुझे मानवीय रिश्तों के बारे में लिखना और पढ़ना पसंद है'



अभिनय के अलावा लेखन में भी दिलचस्पी रखती हैं रुबीना।

सिनेमा और टीवी की दुनिया के कई ऐसे कलाकार हैं जो अभिनय के अलावा संगीत, लेखन या चित्रकारी समेत कई अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी रखते हैं। बिग बास 14 की विजेता और धारावाहिक 'शक्ति अस्तित्व के अहसास की' की अभिनेत्री रुबीना दिलैक के पिता लेखक हैं। लिहाजा वह अभिनय के साथ-साथ लेखन में भी दिलचस्पी रखती हैं। अपनी इस दिलचस्पी के बारे में रुबीना ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया, 'मुझे फुर्सत के वक्त पढ़ना और लिखना पसंद है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यहां से अपने हिमाचल प्रदेश स्थित घर पर जाते हुए अपने साथ कुछ किताबें भी लेकर गई थी, जो मुझे कोरोना संक्रमित होने के दौरान क्वारंटाइन में रहने के समय बहुत काम आईं। उन किताबों से मुझे सकारात्मक रहने में मदद मिली। मैं मानवीय रिश्तों और उसकी साइकोलाजी (मनोविज्ञान) के बारे में लिखना और पढ़ना पसंद करती हूं। हालांकि, अभी मैं खुद को इतनी परिपक्व नहीं मानती कि मैं कोई फिल्म या शो लिख सकूं। भविष्य में थोड़ा और अनुभव हो जाने के बाद अगर मुझे कोई फिल्म या शो लिखने का मौका मिला तो मैं उसके लिए जरूर कोशिश करूंगी।' करियर की आगे की योजनाओं पर रुबीना का कहना है, 'मैंने पिछले साल जितनी भी योजनाएं बनाई थीं, वह सब धरी की धरी रह गईं। इसलिए मैंने इस साल कोई प्लानिंग नहीं की है। पिछले साल मैंने कुछ म्यूजिक वीडियो जरूर शूट किया था, लेकिन अभी इन सब चीजों से दूर कुछ समय तक मैं अपने शो को ही वक्त दूंगी।'

सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम

नितेश ने केबीसी 13 के लिए बनाई शार्ट फिल्म

गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के 13वें सीजन का प्रमोशन शुरू हो गया है। शो के लिए तीन पार्ट की शार्ट फिल्म बनाने वाले निर्देशक नितेश तिवारी शुक्रवार को मीडिया से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने इसका पहला पार्ट दिखाया, जिसमें गांव वालों को स्कूल बनाने के लिए 25 लाख की जरूरत होती है और वे हर तरह से कोशिश कर रहे होते हैं। फिर केबीसी के रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्हें पता चलता है। गांव वालों को जिससे उम्मीद नहीं होती है, उसे केबीसी से बुलावा आता है। इसके आगे भी कहानी के दो हिस्से होंगे। इस कैंपेन को लेकर नितेश ने दैनिक जागरण से कहा कि इस फिल्म का नाम 'सम्मान' है। इस फिल्म को हमने भोपाल से डेढ़ घंटे दूर एक गांव में फिल्माया है। मैंने अपना बचपन मध्य प्रदेश में बिताया है, इसलिए वहां की परिस्थितियों को समझना मेरे लिए आसान था। छिछोरे और दंगल जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके नितेश फीचर फिल्म और शार्ट फिल्म के बीच के अंतर पर कहते हैं कि दोनों को फिल्माने का तरीका एक ही होता है। कहानियों को कहने का एक तरीका होता है। अंतर होता है वक्त का। शार्ट फिल्मों में वक्त कम मिलता है।



नितेश ने भोपाल में की शूटिंग ● टीम सोनी टीवी